सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

nidm

समुत्थानशील भारत, आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

/NIDMMHAINDIA /NIDMMHAINDIA /NIDMMHAINDIA

/NIDMMHAINDIA /NIDMINDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2024–25

nidm
समुत्थानशील भारत – आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम 2024-25

कॉपीराइट © 2025, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दिल्ली

प्रकाशक

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार),

प्लॉट नंबर 15, पॉकेट-3, ब्लॉक-बी, सेक्टर-29, रोहिणी, दिल्ली-110042

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम)

दृष्टिकोण

"भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन पर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक प्रमुख संस्थान बनना और क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में पहचान स्थापित करना। सभी स्तरों पर आपदा निवारण और तैयारी की संस्कृति को विकसित करना और उसे बढ़ावा देकर आपदा-मुक्त भारत निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना"

(18 अप्रैल 2007 को आयोजित संस्थान (निकाय) की पहली बैठक से ली गई पंक्तियां)

विषय सूची

1 सिंहावलोकन 1

2 संगठनात्मक व्यवस्था 7

3 प्रशिक्षण कार्यक्रम 17

4 परियोजनाएँ 27

5 ज्ञान प्रबंधन और जागरुकता गतिविधियाँ 43

6 प्रमुख कार्यक्रम/कार्यशालाएँ/सम्मेलन/सेमिनार एवं बैठकें 65

7 वित्त और लेखा 121

8 अनुलग्नक 147

nidm
Resilient India - Disaster Free India

मधुप व्यास, भा. प्र. से.
कार्यकारी निदेशक
Madhup Vyas, IAS
Executive Director

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
National Institute of Disaster Management
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
प्लॉट नं. 15, ब्लॉक बी, पॉकेट 3,
सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली - 110042
Plot No. 15, Block B, Pocket 3,
Sector 29, Rohini, Delhi-110042

कार्यकारी निदेशक के पटल से

बीता हुआ वर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के लिए उल्लेखनीय विकास एवं परिवर्तन का काल रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया के क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रति समर्पित रहते हुए, हमने विशेषज्ञ संकाय सदस्यों के साथ अपनी टीम को और सशक्त बनाया है। हमें यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जो एक आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण में हमारे योगदानों को रेखांकित करता है, जहाँ हम सरकारी अधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन को मुख्यधारा में ला रहे हैं।

इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर की स्थापना थी, जिसका औपचारिक उद्घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री के. राम मोहन नायडू और आंध्र प्रदेश सरकार के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया। यह परिसर हमारे बढ़ते राष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक है और उभरते आपदा जोखिमों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण और तैयारी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एक अग्रणी संस्थान के रूप में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने निरंतर अनुकूलनशीलता और नवाचार का परिचय दिया है, जिससे समुदायों की सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण और आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, संस्थान ने एक वर्ष तक चलने वाला एक व्यापक ''भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम'' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लक्षित प्रशिक्षण, ज्ञान प्रसार और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से भूकंपीय घटनाओं के प्रति राष्ट्रीय समुत्थानशीलता को बढ़ाना है। यह पहल भुज भूकंप की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ की गई है।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), अंतरिक्ष विभाग (डीओएस), और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से एनआईडीएम ने ''आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी'' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और इसी विषय पर गृह मंत्रालय (एमएचए) और एनआरएससी-इसरो के सहयोग से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह पहल आपदा जोखिम प्रबंधन में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एकीकरण तथा आपदाओं से निपटने में अंतरिक्ष आधारित समाधानों के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई।

अक्तूबर 2024 में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ''सशक्त युवा, सुरक्षित भविष्य'' थीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया, जिसमें समुत्थानशीलता निर्माण में समावेशिता की महत्ता को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना और भोपाल गैस त्रासदी पर भी स्मृति कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनके माध्यम से ऐतिहासिक आपदाओं पर चिंतन करने और भविष्य में बेहतर तैयारी एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उनसे प्राप्त शिक्षाओं को समझने का अवसर प्राप्त हुआ।

पिछले वर्ष के दौरान, एनआईडीएम ने पूरे भारत में विविध आपदाओं और क्षेत्र-विशेष की चुनौतियों को संबोधित करते हुए बहुआयामी आपदा प्रबंधन पहलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कर्नाटक में, संस्थान ने ''जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थानशीलता: एक समग्र दृष्टिकोण'' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय समुत्थानशीलता के लिए व्यापक रणनीतियों को प्रोत्साहित करना था। पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का फोकस शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करना था, जबकि मणिपुर में, आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान बाल संरक्षण और अधिकारों पर केन्द्रित था। जम्मू एवं कश्मीर में शिक्षाविदों के लिए एक क्षेत्रीय क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। समग्र रूप से, ये प्रयास आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक व्यापक और क्षेत्रीय प्रासंगिक दृष्टिकोण के प्रति एनआईडीएम की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि एनआईडीएम को भारत भर में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में इसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए क्षमता निर्माण आयोग द्वारा ''Good'' रेटिंग प्रदान की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एनआईडीएम ने ''समुत्थानशील समुदाय, सशक्त राष्ट्र: आपदा प्रबंधन में भारत-ऑस्ट्रेलिया की सहयोगात्मक रणनीति'' विषय पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली में आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान आपदा समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने हेतु व्यापक और समन्वित रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

यह वार्षिक रिपोर्ट एनआईडीएम द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई पहलों और कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला पर प्रकाश डालती है, संस्थान पूरे देश में अपने विस्तार को निरंतर बढ़ाते हुए सभी स्तरों पर रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करके एक आपदा-प्रतिरोधी भारत के निर्माण की अपनी दृष्टि को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। मैं एनआईडीएम की पहलों को मिले समर्थन तथा गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

(मधुप व्यास)

गतिविधियों की समीक्षा

इस वर्ष, 107 आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें कुल 5262 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 57 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 5251 प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही, 22 बुनियादी एवं विषयगत ई-लर्निंग पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए (चार सप्ताह और छह सप्ताह की अवधि वाले), जिनमें 485 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने तीन आईजीओटी पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 5,076 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, एनआईडीएम ने वर्ष 2024-25 में 24 प्रकाशन प्रकाशित किए। एनआईडीएम की पिछले कुछ वर्षों की विभिन्न गतिविधियों को निम्नलिखित ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाई गई है-

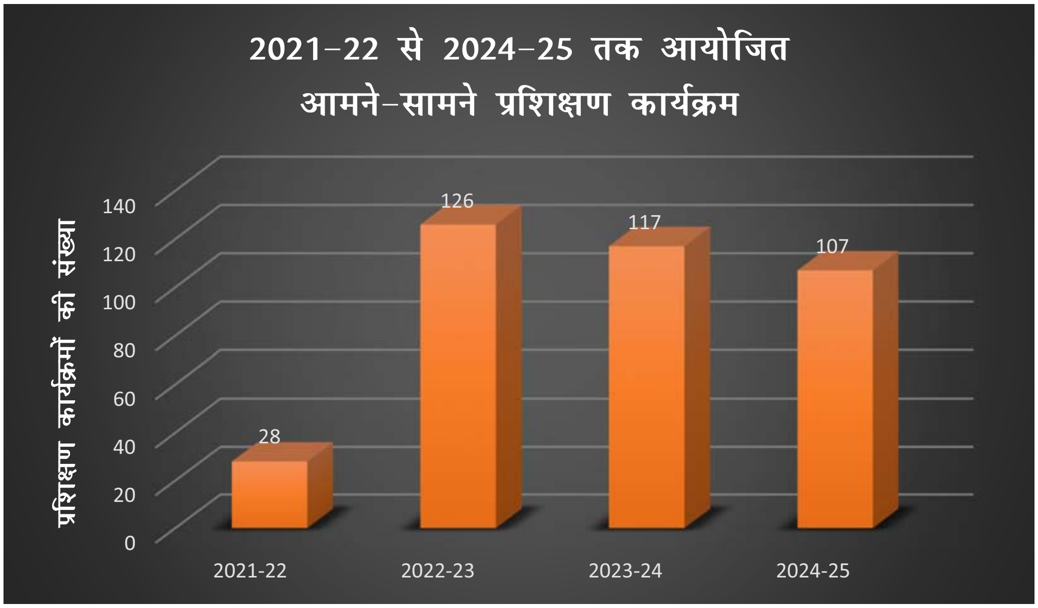

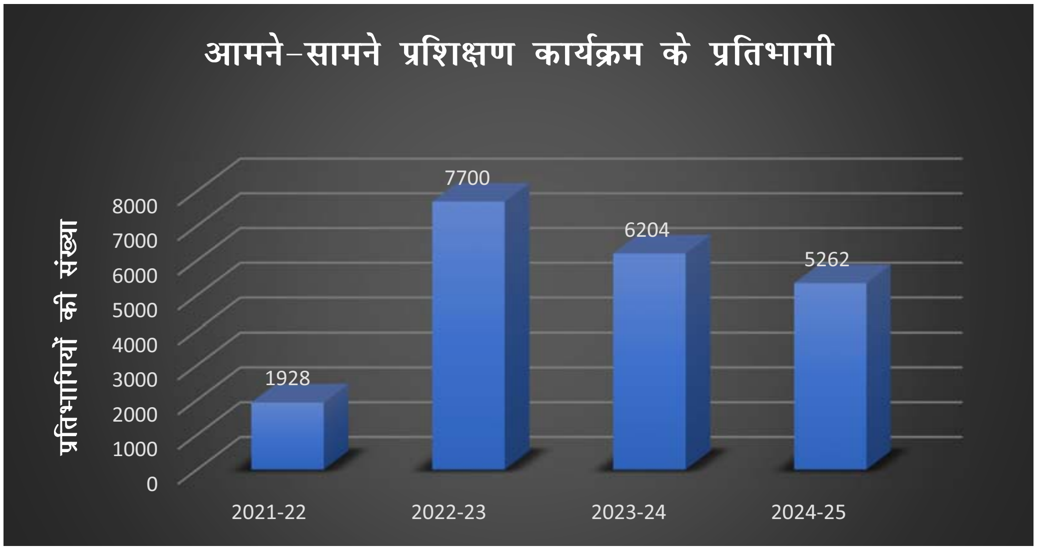

प्रकाशन
प्रकाशनों की संख्या
40
35
30
25
20
15
10
5
0
31
38
20
24
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25

अध्याय 1

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

1.1 संस्थान के बारे में

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन 30.10.2006[1] को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को आपदा प्रबंधन नीतियों, निवारक तंत्र और शमन उपायों[2] के संबंध में आपदा प्रबंधन प्रलेखन और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करने के क्षेत्र में योजना बनाने और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से 16 अक्टूबर, 2003 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के रूप में पुनः अधिकारिक नामकरण के बाद से एनआईडीएम सभी स्तरों पर आपदा नियंत्रण और इसके लिए तैयार रहने की संस्कृति का विकास करके तथा इसे बढ़ावा देकर एक आपदा जागरुक भारत तैयार करने के अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है।

1.2 प्रबंधन संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नियम, 2006 के अनुसार, संस्थान और शासी निकाय नामक संस्थान के 2 निकाय हैं। संस्थान में 42 सदस्य होते हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों/विभागों के सचिव, मौजूदा राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान एवं तकनीकी संगठनों के अध्यक्ष साथ ही प्रमुख वैज्ञानिक एवं डीआरआर विशेषज्ञ शामिल हैं। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री संस्थान के अध्यक्ष हैं। एनआईडीएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों और दिशा-निर्देशों के अधीन कार्य करता रहा है।

संस्थान की शासी परिषद् में 14 सदस्य हैं जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और गृह सचिव उपाध्यक्ष[3] हैं। चूंकि एनडीएम के उपाध्यक्ष का पद खाली है, इसलिए गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। संस्थान के दैनिक प्रशासन का संचालन कार्यकारी निदेशक द्वारा किया जाता है।

संस्थान के निम्नलिखित शैक्षणिक विभाग हैं:-

- सुशासन एवं समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)
- आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति प्रभाग (डीआरएंडआर)
- भू-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)
- समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग (आरआईडी)
- सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)
- पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम)

---

[1]एनआईडीएम का गठन 30.10.2006 से एस.ओ. 1862(ई) द्वारा किया गया है।
[2]आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, धारा 42(8)
[3]एनआईडीएम नियम, 2006 की धारा 6

इसके अलावा, संस्थान के 21 केंद्र और 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं।

1.3 मिशन

- नीति निर्माण में सहायता देकर सरकार के लिए एक विचारक मंडल के रूप में कार्य करना;
- निम्नलिखित द्वारा आपदाओं के दुष्परिणामों और प्रभावों को कम करने में सहायता देना;
  - » प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सेवाओं की योजना बनाना एवं उन्हें बढ़ावा देना;
  - » अनुसंधान, प्रलेखीकरण और राष्ट्रीय स्तर का सूचना आधार तैयार करना;
  - » आपदा के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करने और राहत के लिए पद्धति विकास और सुविज्ञता को प्रोत्साहित करना;
  - » जागरूकता को बढ़ावा देना और सभी हितधारकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना;
  - » सभी संबंधितों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए सांस्थानिक तंत्र का सुदृढ़ीकरण;
  - » नेटवर्किंग और सूचना, अनुभव और सुविज्ञता के आदान-प्रदान को सुगम बनाना।[4]

1.4 कार्य

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान को निम्न कार्य[5] सौंपे गए हैं:-

- आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना, अनुसंधान और प्रलेखन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन विकास योजना का निर्माण और कार्यान्वयन;
- राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करने में सहायता प्रदान करना;
- विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक सहायता प्रदान करना;
- राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढांचे के निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक अन्य सहायता के रूप में राज्य सरकार और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता प्रदान करना;
- शैक्षणिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित आपदा प्रबंधन के लिए शैक्षणिक सामग्रियों का विकास;
- कॉलेज या स्कूल के शिक्षकों और छात्रों, तकनीकी कर्मियों और बहु-जोखिम न्यूनीकरण, तैयारियों और प्रतिक्रिया उपायों से जुड़े अन्य लोगों सहित हितधारकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना;
- उपरोक्त उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए देश के भीतर और बाहर अध्ययन पाठ्यक्रम, सम्मेलनों, व्याख्यानों, सेमिनारों को आयोजित करना और सुगम बनाना;
- पत्रिकाओं, शोध पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करना और पुस्तकालयों की स्थापना और रख-रखाव आदि;

---
[4]प्रबंधन समिति की पहली बैठक की कार्यसूची
[5]आपदा प्रबंधन अधिनियम, धारा 42(9)

- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक तथा प्रासंगिक अन्य सभी विधि सम्मत कार्य करना;
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्यो का निष्पादन;

1.5 प्रमुख क्षेत्र

1.5.1 प्रशिक्षण

1. **आमने-सामने प्रशिक्षण:** एनआईडीएम सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए व्यापक विषयों और क्षेत्रों को कवर करते हुए विभिन्न विषयों पर परिसर में और परिसर के बाहर दोनों जगह प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।
2. **वेब आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण:** यह संस्थान आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विशेष विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। उपयोगकर्ता रजिस्टर करके ऑनलाइन अध्ययन पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं।
3. **स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम:** संस्थान ने वेब आधारित स्व-अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू किए हैं जिसके लिए, कोई भी, किसी भी समय लॉग-ऑन कर सकता है और इन पाठ्यक्रमों के अध्ययन से सीख सकता है।
4. **कार्यशाला, सेमिनार, परामर्श:** संस्थान आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर कार्यशाला, सेमिनार, परामर्श/ सम्मेलन का आयोजन करता है।
5. **iGOT**- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया iGOT प्लेटफॉर्म, आपदा प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों और हितधारकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एनआईडीएम आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और प्रबंधन पर विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए iGOT का उपयोग करता है।

1.5.2 अनुसंधान और प्रलेखीकरण

एनआईडीएम देश में होने वाली बड़ी आपदाओं का प्रलेखीकरण करता है ताकि इसके प्रबंधन से सबक लिया जा सके और इन मामलों के अध्ययन का प्रयोग प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए संसाधन सामग्री और अनुकरण अभ्यास के लिए किया जा सके। एनआईडीएम ने डीआरआर के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने के लिए एनआईडीएम डॉक्टरेट फेलोशिप कार्यक्रम, अनुसंधान परियोजना, सर्वश्रेष्ठ थीसिस रैंकिंग सहित राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा भी शुरू की है।

1.5.3 नीति अध्ययन और सहायता

एनआईडीएम, एक ज्ञान एवं अनुसंधान आधारित संस्थान होने के नाते, राष्ट्रीय स्तर के दिशा-निर्देश, नीतियाँ और योजनाएँ आदि तैयार करने में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य हितधारकों को सहायता प्रदान करता है। एनआईडीएम, राज्य सरकारों और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को राज्य स्तरीय नीतियों, रणनीतियों, आपदा प्रबंधन ढाँचे के निर्माण में सहायता प्रदान करता है और हितधारकों के क्षमता निर्माण हेतु उनकी (राज्य सरकारों या राज्य प्रशिक्षण संस्थानों) आवश्यकतानुसार अन्य सहायता भी प्रदान करता है। संस्थान केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को भी सहायता प्रदान करता है।

1.5.4 ज्ञान एकीकरण

एनआईडीएम प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण आदि के लिए कार्यक्रम आधारित गतिविधियों पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य विशिष्ट संगठनों के साथ नेटवर्किंग और सहयोग के माध्यम से ज्ञान एकीकरण करता है।

*****

अध्याय 2

संगठनात्मक व्यवस्था

संगठनात्मक व्यवस्था

केंद्रीय गृह मंत्री इस संस्थान के अध्यक्ष हैं, और कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं। संस्थान में 42 सदस्य हैं, जिनमें भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नोडल मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, अनुसंधान और तकनीकी संस्थानों के अध्यक्षों के अलावा प्रसिद्ध विद्वान, वैज्ञानिक और व्यवसायी शामिल हैं। **(8.1 अनुलग्नक–I: संस्थान के सदस्यों की सूची)**

संस्थान की एक शासी परिषद् है, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और केंद्रीय गृह सचिव संस्थान के शासी परिषद् के उपाध्यक्ष हैं। **(8.2 अनुलग्नक–II: संस्थान के शासी परिषद् के सदस्यों की सूची)**

संस्थान के छः प्रभाग और 21 विशेष केंद्र हैं जिनकी सहायता के लिए 7 कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ हैं। **(चित्र 2.1)**

2.1. संगठनात्मक ढांचा

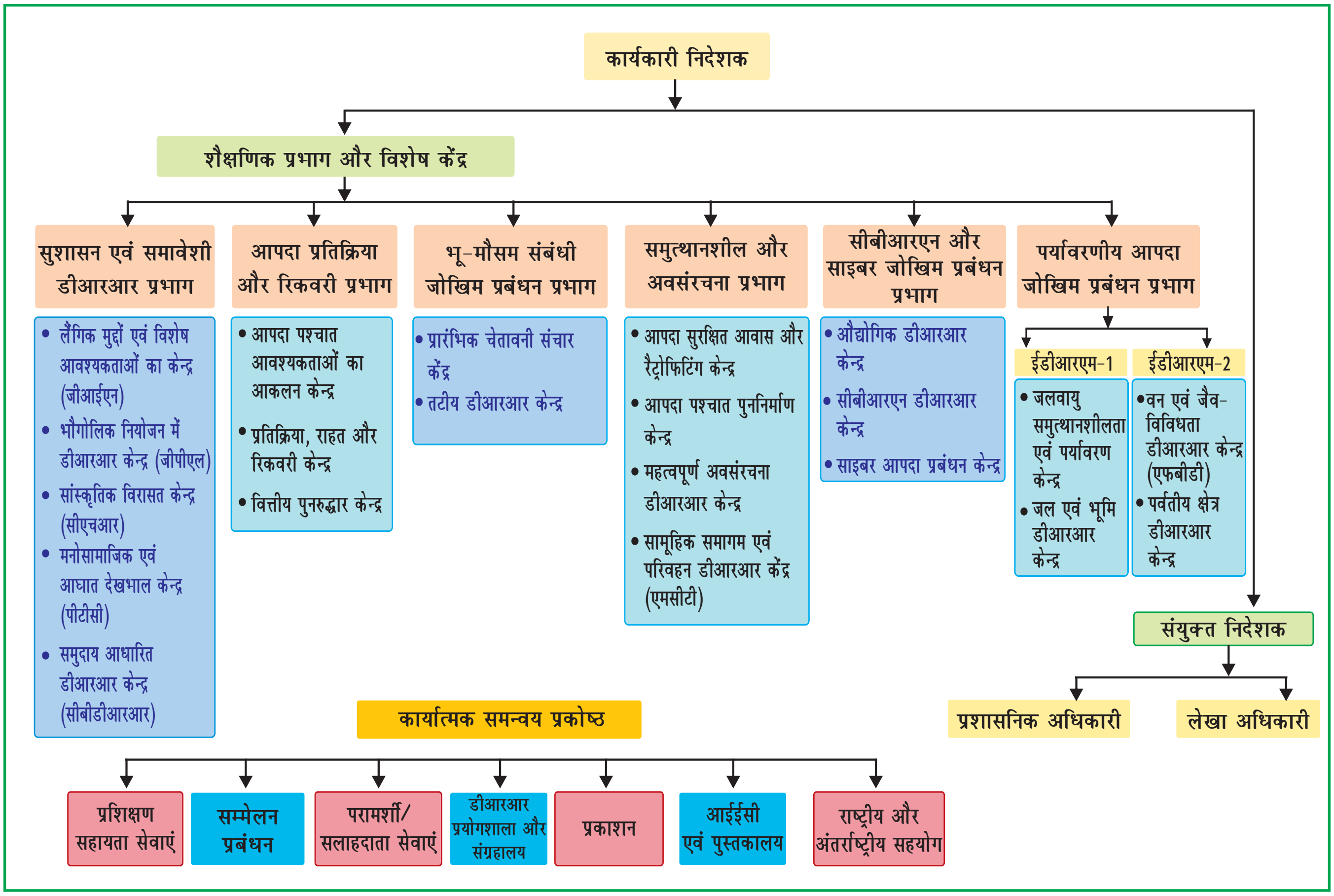

चित्र 2.1 एनआईडीएम की नियोजित शैक्षणिक और कार्यात्मक संरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (दोनों परिसरों) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (दिनांक 31.03.2025)

तालिका 2.1: एनआईडीएम के कार्यकारी अधिकारी

क) कार्यकारी निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री, राजेन्द्र रत्नू, आईएएस	कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम

ख) संयुक्त निदेशक

क्र.सं.	नाम	अवधि
2.	कर्नल पी. एस. रेड्डी	संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर एवं प्रभारी संयुक्त निदेशक, दिल्ली परिसर (दिनांक 12.09.2024 से प्रभावी)
3.	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, दिल्ली (11.09.2024 तक)

तालिका 2.2: प्रभागवार एनआईडीएम की संकाय सूची

1. सुशासन और समावेशी डीआरआर प्रभाग (जीआईडीआरआर)	
डॉ. अजिन्दर वालिया एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष/प्रभारी)	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	लैंगिक मुद्दों और विशेष आवश्यकताओं का केंद्र (जीआईएन)
ii.	भौगोलिक नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (जीपीएल)
iii.	सांस्कृतिक विरासत केंद्र (सीएचआर)
iv.	मनोसामाजिक एवं आघात देखभाल केंद्र (पीटीसी)
v.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (सीबीडीआरआर)

2. आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रभाग (डीआरआरडी)	
डॉ. अजिन्दर वालिया एसोसिएट प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष/प्रभारी)	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	आपदा पश्चात् आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) केन्द्र
ii.	प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्प्राप्ति केंद्र (आरआरआर)
iii.	वित्तीय पुनरुद्धार केंद्र (एफआर)
प्रभाग से जुड़े संकाय	
i.	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर (प्रभारी)

3. भू-मौसम संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रभाग (जीएमआरडी)	
डॉ. सूर्य प्रकाश प्रोफेसर एवं प्रमुख	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	प्रारंभिक चेतावनी संचार केंद्र (ईडब्लयूसी)
ii.	तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (सीडीआरआर)

4. समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग (आरआईडी)	
डॉ. आमिर अली खान एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	आपदा सुरक्षित आवास और रेट्रोफिटिंग केंद्र (डीएसएचआर)
ii.	आपदा पश्चात् पुनर्निर्माण केंद्र (पीडीआर)
iii.	महत्वपूर्ण अवसंरचना आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (सीआईडी)
iv.	सामूहिक समागम एवं परिवहन आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (एमसीटी)
प्रभाग से जुड़े संकाय सदस्य	
i.	श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर

5. सीबीआरएन एवं साइबर जोखिम प्रबंधन प्रभाग (सीआरएमडी)	
डॉ. सूर्य प्रकाश प्रोफेसर एवं प्रमुख	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (आईएनडी)
ii.	सीबीआरएन आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (सीबीआरएन)
iii.	साइबर आपदा प्रबंधन केंद्र (सीवाईडी)

6. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम–1)	
डॉ. सुषमा गुलेरिया (05.11.2024 से प्रभावी) सहायक प्रोफेसर	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
i.	जलवायु समुत्थानशीलता एवं पर्यावरण केंद्र (सीआरई)
ii.	जल एवं भूमि आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र (डब्ल्यूएलडी)

7. पर्यावरणीय आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम–2)	
श्री एस.एन. सिद्ध (05.11.2025 से प्रभावी) सहायक प्रोफेसर	
प्रभाग के साथ संबद्ध केंद्र	
iii.	वन एवं जैव-विविधता डीआरआर केंद्र (एफबीडी)
iv.	पर्वतीय क्षेत्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण केन्द्र

8. कार्यात्मक समन्वय प्रकोष्ठ		
i.	प्रशिक्षण सहायता सेवाएँ (टीसीएस)	सुश्री रीतू सूद, प्रशासनिक अधिकारी
ii.	सम्मेलन प्रबंधन (सीएफएम)	
iii.	परामर्श/सलाहकार सेवाएँ (सीएएस)	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख (27.09.2024 तक) श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर सुश्री रीतू सूद, प्रशासनिक अधिकारी
iv.	डीआरआर प्रयोगशाला एवं संग्रहालय (डीएलएम)	डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर सुश्री रीतू सूद, प्रशासनिक अधिकारी
v.	प्रकाशन (पीयूबी)	श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष
vi.	आईईसी एवं पुस्तकालय (आईईएल)	श्री संतोष कुमार तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष सुश्री जया, पुस्तकालय परिचारिका
vii.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (एनआईसी)	श्री राजेन्द्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, प्रमुख (03.09.2024 से 31.03.2025 तक) श्री शेखर चतुर्वेदी, सहायक प्रोफेसर सुश्री नाजिया ख़ान, वरिष्ठ सलाहकार (आईपीआरओ) डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर एवं प्रमुख (02.09.2024 तक) डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर (03.09.2024 तक)

2.2 सामान्य प्रशासन

संस्थान के कार्यकारी निदेशक संस्थान के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और शासी निकाय के निर्देशन और मार्गदर्शन में शक्तियों का प्रयोग करते हैं। कार्यकारी निदेशक की सहायता संयुक्त निदेशक, लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जाती है। संस्थान के प्रशासन में मुख्यतया समन्वय, सांविधिक बैठकों का आयोजन, स्थापना एवं कार्मिक प्रबंधन, सुरक्षा, परिसर सहायता सेवाएं और कर्मचारियों का कल्याण शामिल है। यह कार्यक्रमों के सुचारू आयोजन के लिए आवश्यक अवस्थापना और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके संस्थान के शोध, प्रशिक्षण और परामर्शी गतिविधियों को सुगम बनाता है। एनआईडीएम के कर्मचारियों की सूची **तालिका 2.3** में दी गई है।

तालिका 2.3: एनआईडीएम (रोहिणी परिसर, दिल्ली) के संकाय

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. सूर्य प्रकाश	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (जीएमआरडी)
2.	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (दिनांक 27.09.2024 तक)
3.	डॉ. आमिर अली खान	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (आरआईडी)
4.	डॉ. अजिंदर वालिया	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख (जीआईडीआरआर)
5.	श्री शिव नारायण सिद्ध	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 02.09.2024 से प्रभावी)
6.	डॉ. सुषमा गुलेरिया	सहायक प्रोफेसर
7.	श्री शेखर चतुर्वेदी	सहायक प्रोफेसर
8.	श्री प्रेरणा जोशी	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 08.07.2024 से प्रभावी)
9.	श्री पंकज कुमार	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 08.07.2024 से प्रभावी)
10.	श्री अर्कप्रभा सरकार	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 09.07.2024 से प्रभावी)
11.	श्री गगनदीप सिंह	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 11.07.2024 से प्रभावी)

तालिका 2.4 एनआईडीएम के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	सुश्री रीतू सूद	प्रशासनिक अधिकारी
2.	श्री एस.एस. बिष्ट	लेखा अधिकारी
3.	श्री हेमंत कुमार	कंप्यूटर प्रोग्रामर
4.	श्री संतोष कुमार तिवारी	पुस्तकालयाध्यक्ष
5.	श्री अविनाश कुमार पाण्डेय	निजी सचिव (दिनांक 28.02.2025 को सेवानिवृत)
6.	श्री जे.एन. झा	कनिष्ठ अभियन्ता
7.	सुश्री अमृता गुप्ता	निजी सहायक (24.03.2025 तक) निजी सचिव (25.03.2025 से प्रभावी)
8.	सुश्री संतोष मिश्रा	प्रशिक्षण सहायक

9.	सुश्री गीता शर्मा	प्रशिक्षण सहायक
10.	सुश्री मेघा कोहली	प्रशिक्षण सहायक
11.	श्री राजीव कुमार	प्रशिक्षण सहायक
12.	श्री अमर सिंह	मशीन ऑपरेटर
13.	सुश्री जया	पुस्तकालय परिचारिका
14.	श्री लक्ष्मण सिंह	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
15.	श्री पंकज कुमार	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)

तालिका 2.5: एनआईडीएम (दक्षिणी परिसर) के संकाय सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री मनजीत सिंह	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 08.07.2024 से प्रभावी)
2.	श्री रोहित कुमार	सहायक प्रोफेसर दिनांक 09.07.2024 से प्रभावी)
3.	श्री अमरजीत कुमार	सहायक प्रोफेसर (दिनांक 15.07.2024 से प्रभावी)

तालिका 2.6: एनआईडीएम (दक्षिणी परिसर) के कर्मचारी

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री साहस निकथोटी	प्रशासनिक अधिकारी (दिनांक 12.07.2024 से प्रभावी)
2.	श्री ठाकुर देवबर्धन किन्वर	पुस्तकालयाध्यक्ष (दिनांक 13.09.2024 से प्रभावी)

2.3 यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यौन उत्पीड़न रोकथाम (POSH) समिति और दिशा-निर्देश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टाफ सदस्यों, प्रबंधकों और बाहरी विशेषज्ञों सहित विविध पृष्ठभूमि से समर्पित व्यक्तियों से मिलकर बनी POSH समिति यह सुनिश्चित करती है कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की गहन जांच की जाए और गोपनीयता, समानता और व्यवहार कुशलता के मूल्यों को बनाए रखते हुए तुरंत उनका समाधान किया जाए।

एनआईडीएम की POSH नीति यौन उत्पीड़न को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है, कर्मचारियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है, रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं स्थापित करती हैं, और अपराधियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई निर्दिष्ट करती

है। नियमित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, एनआईडीएम अपने कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के मामलों की पहचान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है।

इसके अलावा, एनआईडीएम कार्यस्थल पर आचरण, सहमति और उत्पीड़न के मुद्दों पर कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण सत्रों जैसी शैक्षणिक पहलों के माध्यम से रोकथाम पर जोर देता है। खुले संवाद और परस्पर सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर, एनआईडीएम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है, जहाँ हर व्यक्ति मूल्यवान, सुरक्षित और प्रतिशोध के डर के बिना उत्पीड़न की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त महसूस करे।

यौन उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति और सशक्त सहयोग प्रणाली के साथ, एनआईडीएम का प्रयास है कि वह एक ऐसा कार्यस्थल विकसित करे जहाँ प्रत्येक व्यक्ति भय या भेदभाव से मुक्त होकर अपनी पूरी क्षमता के साथ उन्नति कर सके।

2.4 हिंदी का प्रगामी प्रयोग

एनआईडीएम का हिन्दी प्रकोष्ठ कार्यालय के दैनिक कार्यो में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुगम बनाने के लिए पूर्णतया सक्रिय है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में चार हिन्दी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 135 अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधिकारिक कामकाज की अनिवार्यताओं के अनुसार भाग लिया। एनआईडीएम की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजी जाती है।

कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जो कार्यालय में राजभाषा नियमों/अधिनियमों आदि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से करती है। चालू वर्ष के दौरान इस समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं।

परामर्शदाता (राजभाषा) और पुस्तकालयाध्यक्ष ने 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा के हीरक जयंती समारोह और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में एनआईडीएम का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों के अनुरूप, एनआईडीएम के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कार्यालय में एक हिंदी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संस्थान ने 1 से 14 सितंबर, 2024 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया, जिसमें निबंध लेखन, टिप्पण लेखन, पत्र लेखन, श्रुतलेख, और हिन्दी भाषण जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। इन आयोजनों में लगभग 30

अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, संस्थान ने राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार राजभाषा नियमों और विनियमों के कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने के लिए चेक प्वाइंट्स स्थापित की हैं।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गृह मंत्रालय को भेजी गई। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान हिन्दी प्रकोष्ठ सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों, भाषणों, आईडीआरएन पुस्तिकाओं, प्रशिक्षण मॉड्यूल, आपदा प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर पुस्तकों और सरकारी कामकाज की नियमित मदों के अनुवाद में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है।

*****

अध्याय 3

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपदा प्रबंधन में संलग्न पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण पर जोर देना एनआईडीएम के प्रमुख प्रयासों में से एक रहा है। इस प्रयास के रूप में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में विभिन्न क्षमता निर्माण मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की विधि के आधार पर कार्यक्रम को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

i. आमने-सामने प्रशिक्षण

ii. ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

iii. स्व-अध्ययन

iv. विमर्श/कार्यशालाएं आदि

एनआईडीएम, कार्यक्रमों के संचालन की निरंतरता बनाए रखने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 द्वारा सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के लिए, अपने कार्यों में ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करने की पद्धति को शामिल किया है। इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा गया है। संस्थान ने नवंबर 2021 से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ अपने आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी फिर से आरंभ कर दिए हैं।

एनआईडीएम आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, एनआईडीएम सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज से जुड़े संगठनों (आपदा प्रबंधन पेशेवरों), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, शिक्षाविदों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों (सरकारी विभागों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय स्वंय सेवी संगठनों) को प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

3.1 उद्देश्य

एनआईडीएम का प्राथमिक उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) को मुख्य धारा में लाने के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में आवश्यक कौशल प्रदान करना है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों और आपदा एवं विकास गतिविधियों में लगे अन्य पेशेवरों को केंद्रित और उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए, एनआईडीएम के प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए हैं:

- प्रभावी कार्यक्रम नियोजन और कार्यान्वयन के लिए विकास पदाधिकारियों में जागरूकता पैदा करना, कौशल में सुधार करना और ज्ञान को बढ़ाना;
- सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उभरती जरूरतों के प्रति केंद्र, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को संवेदनशील बनाना;
- अनुभव-भ्रमण, केस स्टडी और विकासात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से विकास कर्मियों के दृष्टिकोण में बदलाव लाना ।

3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम

एनआईडीएम द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने की विधि, लक्षित समूह एवं विषय-वस्तु के आधार पर वर्गीकृत की गई है।

3.2.1 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/आमने-सामने कार्यक्रम

संस्थान अपने परिसर अथवा राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई)/राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में आमने-सामने प्रशिक्षण पद्धति के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन के लगभग सभी पहलुओं को शैक्षणिक प्रभागों के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से शामिल किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, 107 आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 5262 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 57 कार्यशालाएं आयोजित किए गए, जिसमें 5251 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया।

तालिका 3.1: वर्ष 2024-25 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

आमने-सामने कार्यक्रम		कार्यशालाएं	
कुल कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या	कुल कार्यशालाओं की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
107	5262	57	5251

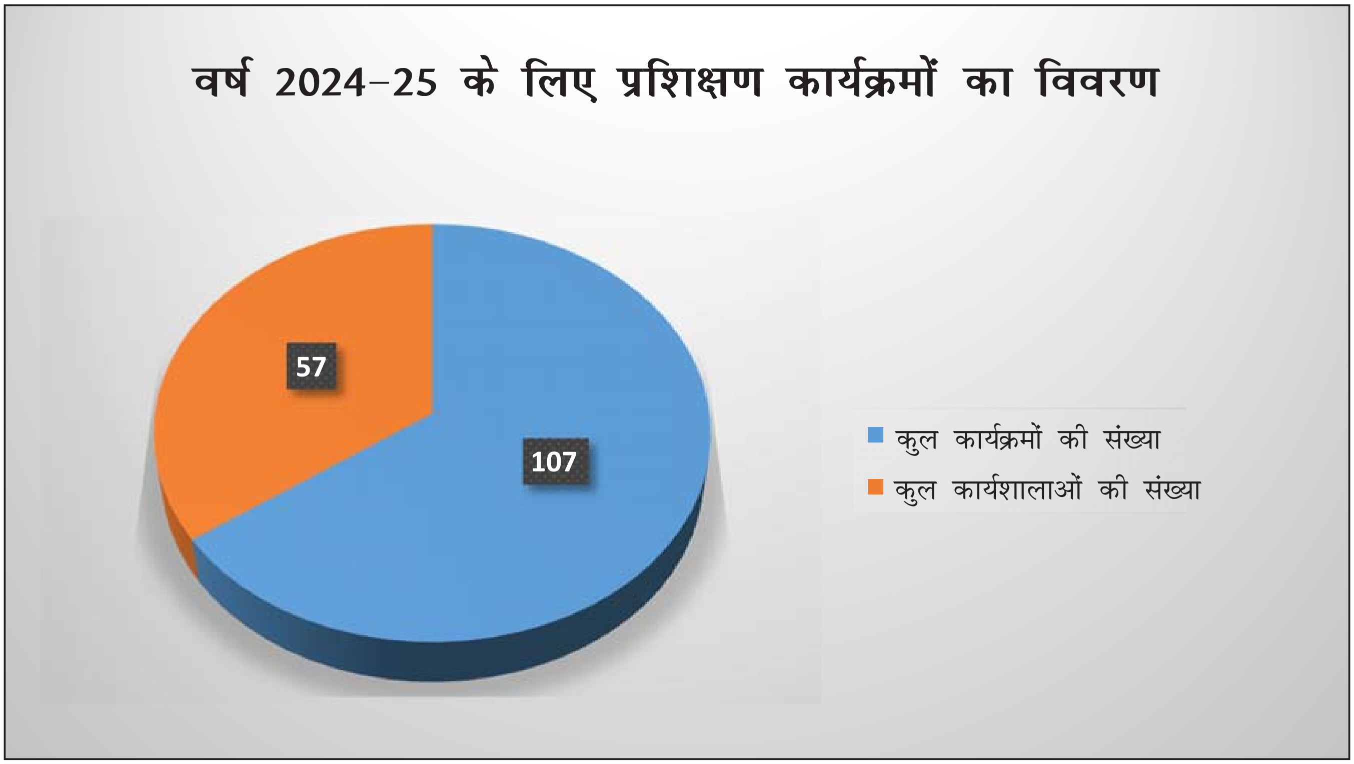

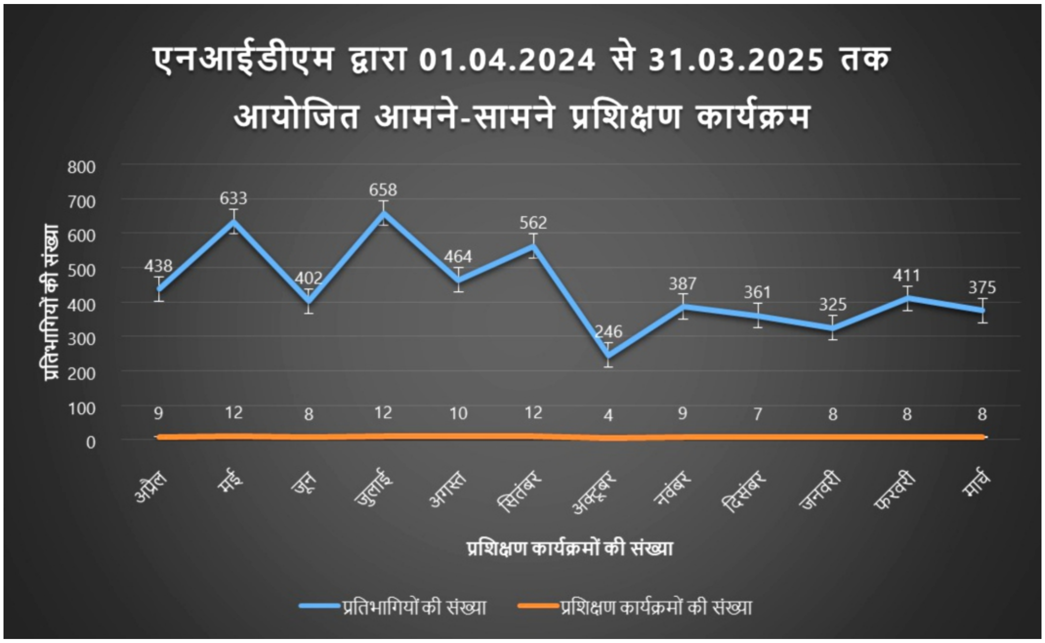

3 प्रशिक्षण विधि

प्रशिक्षण की विविधता और कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्रशिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। प्रशिक्षण विधियों में शामिल हैं:

- व्याख्यान सह–विचार–विमर्श
- केस स्टडी प्रस्तुतीकरण
- कार्य का अभ्यास
- सामूहिक वाद–विवाद/अभ्यास
- पैनल चर्चा
- अनुकरण एवं भूमिका निर्वहन
- टेबल टॉप अभ्यास

3.4 प्रतिभागियों का विवरण

चूंकि, एनआईडीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपदा प्रबंधन में लगे विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को शामिल किया गया है, अतः प्रशिक्षुओं की प्रोफाइल को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है;

- सरकारी कर्मचारी (केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर के अधिकारी);
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू);
- शिक्षाविद् (शोधकर्ता, वैज्ञानिक, स्कूल शिक्षक एवं विश्वविद्यालय संकाय);
- ज्ञान भागीदार संस्थान;

- अंतर्राष्ट्रीय भागीदार (सरकारी विभाग, यूएन एजेंसियां,आईएनजीओ);
- अवसंरचना पेशेवर (इंजीनियर, वास्तुकार, निर्माण एजेंसियां आदि);
- नागरिक समाज संगठन (आपदा प्रबंधन पेशेवर)

3.5 ई–लर्निंग

3.5.1 ऑनलाइन पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) विभिन्न क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का एक व्यापक समूह प्रदान करता है। ये पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विविध हितधारकों के बीच जागरूकता, तैयारी, विश्लेषणात्मक कौशल और पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं।

ई–लर्निंग कार्यक्रम एक अद्वितीय क्षमता निर्माण पहल है, जो मूडल (MOODLE)- आधारित वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पारस्परिक संवाद के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने में सहायक है। प्रतिभागी चर्चा मंचों के माध्यम से विश्वभर के समकक्ष लोगों और विषय विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं, जिससे मत, विचार एवं जानकारी वैश्विक स्तर पर साझा कर एक गतिशील वातावरण का निर्माण होता है।

संबंधित पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर को 'संवाद सत्र' 'पाठ्यक्रम कार्यों के मूल्यांकन' और 'पाठ्यक्रम परियोजना के समापन' जैसे निर्धारित मापदंडों के आधार पर आंका जाता है, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें सफल घोषित किया जाता है और एनआईडीएम द्वारा जारी 'पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया जाता है।

प्रस्तुत पाठ्यक्रम

एनआईडीएम अपने समर्पित पोर्टल http://elearning.nidm.gov.in के माध्यम से कुल 10 संरचित ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

1. **व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा (सीडीआरएमएफ)**- यह एक बुनियादी पाठ्यक्रम है, जो आपदा प्रबंधन की मूलभूत अवधारणाओं और अनुप्रयोगों पर जानकारी प्रदान करता है। इसकी अवधि 6 सप्ताह की है।

इसके अतिरिक्त 4 सप्ताह की अवधि के निम्नलिखित 9 ''विषयगत पाठ्यक्रम'' भी प्रतिभागियों को उपलबध कराए जाते हैं –

2. समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन (सीबीडीआरएम);
3. भूकंप जोखिम न्यूनीकरण (ईआरआर);
4. जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम (सीसीडीआर);
5. क्षति एवं पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन (डीआरएनए);
6. आपदा रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू (जीएडीआरआर);
7. जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना (आरएसएलयूपी);

8. जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण (आरए);
9. सुरक्षित शहर (एससी);
10. आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ (एफए)

ऑनलाइन पाठ्यक्रम पोर्टल पर **अप्रैल 24, 2025** तक **आगंतुकों की संख्या 1,12,749** है। पाठ्यक्रम सामग्री पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए उनके संबंधित पाठ्यक्रम प्लेटफार्म पर आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे ऑफ लाइन संदर्भ के लिए भी डाउनलोड किया जा सकता है।

शैक्षणिक वर्ष का अवलोकन

शैक्षणिक वर्ष **2024–25** के दौरान, एनआईडीएम ने 22 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें **485 प्रतिभागियों** ने भाग लिया:

क्रमांक	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम संख्या
1.	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचा	4
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन	2
3.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण	2
4.	जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन	2
5.	क्षति और पुनर्निर्माण की आवश्यकता का आकलन	2
6.	आपदा रिकवरी और पुनर्निर्माण के लैंगिक पहलू	2
7.	जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना	2
8.	जोखिम पहचान, आकलन और विश्लेषण	2
9.	सुरक्षित शहर	2
10.	आपदाओं के आर्थिक प्रभावों के प्रबंधन के लिए वित्तीय रणनीतियाँ	2
	कुल	**22**

कोविड काल के पश्चात आपदा संबंधी ज्ञान प्रदान करने के लिए एनआईडीएम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने हेतु ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को और विकसित करने का प्रयास कर रहा है।

3.5.2 स्व अध्ययन कार्यक्रम

एनआईडीएम का स्व-अध्ययन कार्यक्रम (एसएसपी) ई-लर्निंग की एक स्व-गतिशील प्रणाली है, जिसमें सभी संबंधित हितधारकों को बिना किसी समय और स्थान की सीमा के आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को अपनी गति से सीखने का अवसर और सुविधा प्रदान किया जाता है। ई-लर्निंग का यह तरीका स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी मानवीय सहायता के अपनी सुविधानुसार आपदा प्रबंधन विषयों की समझ बढ़ा सकते हैं।

आपदा प्रबंधन में शामिल हितधारकों के ज्ञान के आधार को व्यापक बनाने में स्व-अध्ययन मॉड्यूल मूल्यवान संसाधन साबित हुए हैं।

पोर्टल पर जाने के लिए https://ssp.nidm.gov.in/ पर लॉग इन करें

एनआईडीएम द्वारा स्व-अध्ययन पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित 10 स्व-अध्ययन मॉड्यूल प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

क्रमांक संख्या	स्व अध्ययन मॉडयूल
1.	आपदा प्रबंधन की मूल बातें
2.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
3.	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए एक मार्गदर्शिका
4.	बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
5.	चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
6.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन का अवलोकन
7.	व्यापक भूस्खलन जोखिम प्रबंधन
8.	स्कूल सुरक्षा
9.	भूकंप जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय
10.	औद्योगिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन का परिचय

3.6 आईगोट प्लेटफॉर्म पर एनआईडीएम पाठ्यक्रम

मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों की उभरती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण ढाँचे में बदलाव लाना है। यह कार्यक्रम सिविल सेवकों की कार्यात्मक और व्यवहारिक दक्षताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका संचालन भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक सर्वोच्च संस्था द्वारा किया जाता है।

इस मिशन के एक भाग के रूप में, डिजिटल इंडिया पहल के तहत आईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म (https://portal.igotkarmayogi.gov.in) विकसित किया गया है ताकि सरकारी अधिकारियों के लिए एक व्यापक डिजिटल शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य किया जा सके। यह निरंतर व्यावसायिक विकास को सुगम बनाने, शासन के प्रति भूमिका-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और संस्थागत प्रभावशीलता में सुधार के लिए संरचित शिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

यह प्लेटफॉर्म सुगम्यता और लचीलेपन के सिद्धांतों पर आधारित है, जो ''कभी भी, कहीं भी, किसी भी उपकरण'' पर शिक्षा प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दूरस्थ और दूरगम स्थानों सहित सभी भौगोलिक क्षेत्रों के कर्मियों को प्रशिक्षण उपलब्ध हो। कौशल संवर्धन और ज्ञान विकास को बढ़ावा देकर, आईगोट कर्मयोगी सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व में उल्लेखनीय सुधार लाने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आईगोट प्लेटफॉर्म पर चार प्रशिक्षण मॉड्यूल सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा, पहुँच और समावेशिता को और व्यापक बनाने के लिए सात भारतीय भाषाओं में कई आगामी पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। इन कार्यक्रमों को उपयोगकर्ताओं द्वारा खूब सराहा गया है और इन्हें औसतन 4.5 की रेटिंग मिली है, जो उनकी प्रासंगिकता और शिक्षण गुणवत्ता को दर्शाता है।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	लेखक	भाषा	लॉन्च तिथि	नामांकन संख्या	पूर्ण करने वाले प्रतिभागी	रेटिंग
1.	आपदा तैयारी में क्या करें और क्या न करें	डॉ. सुषमा गुलेरिया	अंग्रेजी	7-10-2024	2484	943	4.4
2.	आपदा प्रबंधन की मूलभूत बातें	डॉ. सुषमा गुलेरिया	अंग्रेजी	7-10-2024	2004	563	4.4
3.	बाढ़ प्रबंधन	श्री मनजीत सिंह ढिल्लों	अंग्रेजी	11-10-2024	6854	3570	4.3
				कुल	11342	5076	

आईगोट प्लेटफॉर्म में अपने योगदान को और मजबूत करने के लिए, एनआईडीएम वर्तमान में अतिरिक्त पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं और जल्द ही अपलोड किए जाएँगे। ये पाठ्यक्रम डिजिटल रूप से सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा के निर्माण के मिशन कर्मयोगी विजन के अनुरूप हैं। आगामी मॉड्यूल में शामिल हैं:

- स्कूल सुरक्षा (प्रत्येक 90 मिनट के दो मॉड्यूल में विभाजित)
- बहु-खतरा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
- डीआरआर/एसडीजी के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का एकीकरण और मुख्यधारा में समावेशन

3.7 इंटर्नशिप कार्यक्रम

एनआईडीएम को हर साल, खासकर गर्मियों के महीनों में, शैक्षणिक/शोध/प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों/शोधकर्ताओं से इंटर्नशिप के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। इंटर्नशिप के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- प्रासंगिक विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को समग्र आपदा प्रबंधन प्रणाली और इसके विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के छात्रों को आपदा प्रबंधन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और शोध में व्यवहारिक अनुभव लेने में मदद करना।
- छात्रों को उनके कौशल के परीक्षण के लिए नवाचार और नए विचारों तथा तकनीकों को शामिल करने का पर्याप्त अवसर देना।

- औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, व्यवसायिक संस्थानों को एनआईडीएम और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी देना।
- एनआईडीएम में इंटर्नशिप प्रक्रिया को इस उद्देश्य के लिए तैयार और स्वीकृत नीति के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है। इंटर्नशिप के लिए आवेदन खुले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- कार्योन्मुख अनुसंधान कार्य करने के लिए पूरे भारत के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विभिन्न विषयों से प्रशिक्षुओं का चयन किया जाता है।
- वर्ष 2024–25 में कुल 21 इंटर्न नियमित इंटर्नशिप (गैर–भुगतान) कार्यक्रम में शामिल हुए।

*****

अध्याय 4

परियोजनाएं

परियोजनाएं

4.1 राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जलवायु अनुकूलन नीति और दिशा-निर्देश का विकास

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ''राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देश विकास'' परियोजना शुरू की है। यह वर्तमान अध्ययन भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की जलवायु समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। एनआईडीएम इस परियोजना को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मंडी और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ कंसोर्टियम पार्टनर के रूप में कंसोर्टियम मोड में कार्यान्वित कर रहा है। हाई कैप परियोजना की संयुक्त परियोजना संचालन समिति की अध्यक्षता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। एनआईडीएम और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी संयुक्त परियोजना संचालन समिति (जेपीएससी) के पदेन सदस्य हैं और परियोजना निदेशक, हाईकैप इसके सदस्य सचिव हैं।

समयसीमा: मई 2024-अप्रैल 2026

मुख्य उद्देश्य

(i) जलवायु चरम सीमाओं और बहु-खतरनाक जोखिम प्रवण क्षेत्रों के प्रति संभावित संवेदनशील राजमार्ग खंडों और परिसंपत्तियों का अध्ययन करना।

(ii) उपयुक्त और लागत-प्रभावी अनुकूलन विकल्पों की पहचान करना और समुत्थानशील ढाँचे की रूपरेखा तैयार करना।

(iii) मौजूदा संहिताओं, नियमावलियों और प्रथाओं का अध्ययन करना और अनुकूलन रणनीति एकीकरण की सिफारिश करना।

(iv) भारत में राजमार्गों के लिए डीआरआर सहित जलवायु अनुकूलन नीति और दिशा-निर्देश तैयार करना।

(v) परिवहन आपातकालीन प्रबंधन योजना (टीईएमपी) और यातायात निकासी योजना (टीईपी) तैयार करना।

(vi) अनुकूलन नीति और दिशा-निर्देशों पर क्षमता टूलकिट विकसित करना और पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ:

- खतरा-जोखिम विश्लेषण के लिए 2000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का चयन
- चयनित राष्ट्रीय राजमार्ग के 2000 किलोमीटर के 30 संवेदनशील खंडों का चयन और अध्ययन

- चिन्हित 30 खंडों से मेल खाते क्षेत्रों के लिए जलवायु प्रभाव अनुमान और भविष्य की चरम
- प्रमुख बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख खंडों की संवेदनशीलता का आकलन
- चिन्हित 30 खंडों में से प्रत्येक के लिए प्रमुख आपदाओं के लिए बहु-खतरा जोखिम मॉडलिंग
- आपदा-जोखिम और संवेदनशीलता संदर्भो के आधार पर, उपयुक्त अनुकूलन विकल्पों की पहचान जिसमें प्रत्येक संवेदनशील खंड के लिए समुत्थानशीलता शामिल है।
- लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर राजमार्गो के लिए डीआरआर विकल्पों सहित लागत-प्रभावी अनुकूलन की सिफारिशें,
- जलवायु अनुकूलन नीति और अनुकूलन के लिए दिशा-निर्देश (डीआरआर सहित) का विकास और, मैनुअल, संहिताओं, मानकों आदि का अद्यतन/संशोधन।
- आपदा जोखिम-प्रवण राजमार्गो और संबंधित बुनियादी ढाँचे के लिए एचआरवीसीए और अनुकूलन रणनीतियों पर केस स्टडी, अच्छी प्रथाओं और उदाहरणों के संग्रह का विकास।
- टीईएमपी और टीईपी का विकास।
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम-प्रशिक्षणों के लिए टूलकिट और संदर्भ पाठ्य सामग्री का विकास।
- क्षेत्रवार और राष्ट्रीय स्तर पर पायलट प्रशिक्षणों का कार्यान्वयन।

मार्च 2025 तक की उपलब्धियाँ:

- राष्ट्रीय राजमार्ग के 2000 किलोमीटर बहु-खतरा प्रवण खंड की पहचान की गई है और उसे 30 अध्ययन स्थलों में वर्गीकृत किया गया है।
- अध्ययन स्थलों का जलवायु प्रभाव प्रक्षेपण और संवेदनशीलता के आकलन का कार्य प्रगति पर है।
- एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम और दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।
- दो संयुक्त परियोजना संचालन समिति की बैठकें और कई परामर्शदात्री/समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।
- राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना प्रणालियों की आपदा और जलवायु समुत्थानशीलता के लिए अनुकूलन को बढ़ावा देने वाली श्रेष्ठ प्रथाओं के संकलन का कार्य प्रगति पर है।

वित्त पोषण एजेंसी: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित

4.2 चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से संबंधित मानव स्वास्थ्य मुद्दों पर उत्कृष्टता केंद्र (एनपीसीसीएचएच परियोजना)

जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के अंतर्गत, एनआईडीएम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एनसीडीसी द्वारा चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से संबंधित मानव स्वास्थ्य मुद्दों पर उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया गया है। यह परियोजना संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने, संसाधनों का विकास करने और तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्यः

क) जलवायु और स्वास्थ्य समुत्थानशीलता के लिए संस्थागत तंत्र और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना।

ख) प्रशिक्षण, ज्ञान प्रसार और संसाधन विकास के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य विभागों और हितधारकों की क्षमता में वृद्धि करना।

ग) चरम मौसम की घटनाओं के लिए स्वास्थ्य निगरानी, तैयारी और प्रतिक्रिया ढाँचे के विकास में सहायता करना।

घ) अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और नीति परामर्श के माध्यम से एनपीसीसीएचएच गतिविधियों को तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान करना।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँः

- चरम मौसम की घटनाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल, आईईसी सामग्री और ज्ञान उत्पादों का विकास।
- एनपीसीसीएचएच के अंतर्गत राज्य नोडल अधिकारियों और सलाहकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित करना।
- जलवायु-संवेदनशील रोगों और स्वास्थ्य परिणामों के लिए निगरानी तंत्र का विकास और पायलट परीक्षण।
- क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, नीति संवादों और हितधारक परामर्शों का आयोजन।
- सर्वोत्तम अभ्यास दस्तावेज, समाचार पत्र और केस स्टडी तैयार करना।
- ताप-स्वास्थ्य कार्य योजनाओं और संबंधित अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने में राज्यों को सहायता प्रदान करना।

मार्च 2025 तक की उपलब्धियांः

- एनआईडीएम में हीट-हेल्थ राष्ट्रीय स्तर की क्षमता निर्माण कार्यशाला और सम्मेलन (24-26 मार्च, 2025) का आयोजन किया गया।
- भाग लेने वाले राज्यों और हितधारकों को अध्ययन सामग्री और प्रस्तुतियाँ प्रदान की गईं।
- राज्य-स्तरीय अनुकूलन रणनीतियों के लिए हितधारक जुड़ाव और सामग्री विकास की पहल की गई।

वित्त पोषण एजेंसीः राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

4.3 आयुष मंत्रालय के लिए आपदा प्रबंधन योजना (आयुष-डीएमपी)

आयुष-डीएमपी परियोजना का उद्देश्य आयुष मंत्रालय के लिए एक समग्र आपदा प्रबंधन योजना विकसित करना है, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को सुदृढ़ करना है। यह योजना बहु-आपदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है, विशेषकर स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के संदर्भ में, ताकि

स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुदृढ़ और सक्षम बनी रहे।

मुख्य उद्देश्यः

- आयुष मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आपदा प्रबंधन योजना विकसित करना।
- बड़ी आपदाओं की स्थिति में स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं की तैयारी सुनिश्चित करना।
- दीर्घकालिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों का समर्थन करने के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल और विषयगत पेपर के विकास को सुगम बनाना।
- आयुष स्वास्थ्य क्षेत्र में आपदा प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँः

- आयुष मंत्रालय के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना का विकास।
- समीक्षा और प्रतिक्रिया के लिए 10 दिसंबर 2024 को एनडीएमए में आपदा प्रबंधन योजना की प्रस्तुति।
- क्षमता निर्माण और जागरूकता के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रारूप तैयार करना।
- डीएमपी के प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों के आधार पर एक विषयगत पेपर तैयार करना।
- प्रतिक्रिया और संशोधन के लिए आयुष मंत्रालय, एनडीएमए और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय।

मार्च 2025 तक की उपलब्धियाँः

- एनडीएमए से आपदा प्रबंधन योजना की सशर्त स्वीकृति।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल और विषयगत पेपर का प्रारूप, जिसे वर्तमान में अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गई है और प्रसार से पहले अंतिम संशोधनों की प्रतीक्षा है।

वित्त पोषणः आयुष मंत्रालय

4.4 आपदा प्रबंधन योजना-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएमपी-डीएफपीडी)

एनआईडीएम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 के तहत कानूनी अधिदेश का उपयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएमपीडीएफपीडी) की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहायता कर रहा है। आपदा प्रबंधन योजना की समुत्थानशीलता बढ़ाने और तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के कारण होने वाले संभावित व्यवधान को कम करना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना प्रशिक्षण नियमावली तैयार करना

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ:

- खतरा जोखिम संवेदनशीलता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) कार्यशाला
- क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला
- कार्य समूह की बैठकें
- प्रशिक्षण मैनुअल का निर्माण: मैनुअल का ख़ाका एवं रूपरेखा

4.5 आपदा जोखिम प्रतिक्रिया के लिए सामाजिक व्यवहार परिवर्तन (एसबीसी–डीआरआर)

एनआईडीएम और यूनिसेफ ने डीआरआर के सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं को संबोधित करने के लिए एसबीसीसी में सरकारी अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

इस साझेदारी का समग्र उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सेवा प्रदाताओं को सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन के महत्व और मूल अवधारणाओं को समझने के लिए सशक्त बनाना है और आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी रूपों में एसबीसीसी को एकीकृत करने की क्षमता प्रदान करना है, जिसमें रोकथाम, शमन और तैयारी से लेकर संकट प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति तक शामिल हैं।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ: आयुष

- एसबीसी के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्य योजना
- एनआईडीएम शिक्षाविदों, एनएमडीए और यूनिसेफ के राष्ट्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के साथ एसबीसी और डीआरआर में विशेषज्ञ समिति का गठन
- प्रस्तावित 03 क्षेत्रीय कार्यशालाओं (2025–26) में भागीदारी को प्राथमिकता देना

मार्च 2025 तक की उपलब्धियां

- सामाजिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया और राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जुलाई 2024, एनआईडीएम, नई दिल्ली में परीक्षण किया गया।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण टूलकिट तैयार किया गया और पायलट परीक्षण किया गया।
- राजस्थान में पहली क्षेत्रीय कार्यशाला (मई 2025) आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है।

वित्त पोषण एजेंसी: लागू नहीं है।

4.6 आपात स्थिति में भोजन और पोषण की आवश्यकता: भारत में आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया और तैयारी रणनीतियों का एकीकरण

एनआईडीएम और डब्ल्यूएफपी इंडिया ने अंतर-पोषण सुरक्षा के महत्व पर चर्चा की और ''आपात स्थितियों के लिए खाद्य एवं पोषण रणनीतियों, तैयारी और प्रतिक्रिया'' के लिए दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने और भारत के आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा एजेंडे को मुख्यधारा में लाने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए सिफारिशों को आगे बढ़ाने हेतु सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

चरण I: भारत के ईपीआर पैकेज में खाद्य एवं पोषण रणनीतियों के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का विकास

चरण II: आपात स्थितियों में खाद्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं हेतु क्षमता सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण में सहायता

चरण III: देशों के लाभ के लिए आपातकालीन तैयारी एवं प्रतिक्रिया में खाद्य एवं पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ:

प्रशिक्षण मॉड्यूल का अद्यतनीकरण

मार्च 2025 तक की उपलब्धियां:

मॉड्यूल का अद्यतन संस्करण एनआईडीएम के प्रिंट अनुभाग में डिजाइन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

वित्त पोषण एजेंसी: लागू नहीं है।

4.7 सतत शहरी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर शहरों को सक्षम बनाना

एनआईडीएम और जीआईजेड ने सतत शहरी विकास स्मार्ट सिटीज-II (एसयूडीएससी-II) परियोजना के अंतर्गत ''सतत शहरी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर शहरों को सक्षम बनाना'' नामक एक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

1. शहर नियोजन प्रक्रिया में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्यधारा में समावेशन
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों (जैसे, सेंडाई फ्रेमवर्क) के आधार पर शहरों को जलवायु जनित आपदाओं के प्रति समुत्थानशील बनाने के लिए एक रोडमैप/दिशा-निर्देश तैयार करना

3. सहकर्मी नेटवर्क्स के माध्यम से ज्ञान के आदान–प्रदान और अनुसंधान को सुगम और प्रोत्साहित करना

वित्तपोषण एजेंसी: जर्मन सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जीआईजेड) जीएमबीएच

समयावधि	**1 मार्च 2023–30 नवम्बर 2024)**
परियोजना में शामिल राज्य एवं शहर	अनुसंधान अध्ययन के अंतर्गत शामिल शहर: कोयंबटूर (तमिलनाडु), माणिकोंडा (तेलंगाना), गुवाहाटी (असम) क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रबंधन पहलों के अंतर्गत शामिल शहर: कोयंबटूर (तमिलनाडु), माणिकोंडा (तेलंगाना), गुवाहाटी (असम), मंगलुरु (कर्नाटक), कोच्चि (केरल) और भुवनेश्वर (ओडिशा)

परियोजना के अंतर्गत की गई गतिविधियाँ:

परियोजना प्रस्ताव और अनुदान समझौते में उल्लिखित विभिन्न परियोजना गतिविधियाँ समयबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं। परियोजना की प्रमुख उपलब्धियाँ नीचे दी गई तालिका में वर्णित हैं।

घटक	गतिविधियाँ
विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु नीतिगत सहयोग	तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु नीतिगत सहयोग पर अध्ययन
शहरों को सुदृढ़ बनाने हेतु बाढ़ जोखिम मूल्यांकन रूपरेखा और रोडमैप का विकास	शहरों को सुदृढ़ बनाने हेतु बाढ़ जोखिम मूल्यांकन रूपरेखा और रोडमैप के विकास पर अध्ययन – माणिकोंडा (तेलंगाना) और गुवाहाटी (असम)

घटक	गतिविधियाँ
ज्ञान प्रबंधन	**प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना:** (i) डीआरआर और सीसीए उपायों को विकास योजनाओं में शामिल करने पर प्रशिक्षण मॉड्यूल (iii) आपदा-पश्चात स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल
1. क्षमता निर्माण	**प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन:** i. शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण पर 11-13 जून, 2024 तक विजयवाड़ा में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ii. शहरी बाढ़ प्रबंधन पर 14 जून, 2024 को विजयवाड़ा में कार्यशाला iii. विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के एकीकरण पर 21-23 अगस्त, 2024 को कोयंबटूर में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम iv. शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम मूल्यांकन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों पर 19-21 नवम्बर, 2024 तक गुवाहाटी में प्रशिक्षण कार्यक्रम
2. परामर्श एवं प्रैक्टिशनर्स समुदाय	**i. हितधारक परामर्श:** अध्ययन निष्कर्षों और प्रशिक्षण मॉड्यूल की समीक्षा हेतु दिल्ली (मई 2024) एवं हाइब्रिड मोड में परामर्श कार्यक्रम (जुलाई 2024) आयोजित किया गया । **ii. प्रैक्टिशनर्स समुदाय के लिए कार्यशाला:** इस कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में नवंबर 2024 में किया गया, जिसमें 18 संगठनों के 103 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें अगरतला के बाढ़ जोखिम मूल्यांकन और नागालैंड के आपदा बीमा जैसे केस स्टडीज प्रदर्शित किए गए ।
3. शहरी समुत्थानशीलता पर ज्ञान वर्टिकल	**शहरी समुत्थानशीलता पर ज्ञान वर्टिकल** कॉप कार्यशाला में 28 नवंबर 2024 को शुभारंभ **उद्देश्य:** आईयूआईएन-डीआरआर के अंतर्गत शहरी समुत्थानशीलता से संबंधित ज्ञान के लिए एक केंद्रीकृत मंच स्थापित करना

घटक	गतिविधियाँ
	मुख्य उद्देश्य: • **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना:** सफल हस्तक्षेपों को उजागर करना, जैसे बाढ़ मानचित्रण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आदि। • **सहयोग को प्रोत्साहित करना:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में नवाचार के लिए शहरी स्थानीय निकायों, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को जोड़ना। • **क्षमता निर्माण:** प्रशिक्षण मॉड्यूल, केस स्टडीज और नीतिगत रूपरेखाएँ उपलब्ध कराना। • **अनुसंधान में सहयोग देना:** प्रकृति आधारित समाधानों, अवसंरचना समुत्थानशीलता और जलवायु अनुकूलन पर आधारित अध्ययनों का प्रसार करना।

प्रभाव एवं भविष्य के कदम

- मानव संसाधन क्षमता निर्माण: विजयवाड़ा, गुवाहाटी और कोयंबटूर में आयोजित परियोजना अध्ययनों के अंतर्गत 140 से अधिक अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया गया।
- ज्ञान वर्टिकल: एक महीने के भीतर 100 से अधिक हितधारक पंजीकृत हुए, और वर्ष 2025 तक इसे 50 से अधिक शहरों तक विस्तारित करने की योजना है।
- सततता: एनआईडीएम इस पोर्टल का रखरखाव करेगा, सामग्री को अद्यतन करेगा और इसे भारत आपदा संसाधन नेटवर्क जैसे राष्ट्रीय नेटवर्क से एकीकृत करेगा।
- आगे की दिशा: ज्ञान मंचों को निरंतर बनाए रखना, प्रकृति-आधारित समाधानों पर अनुसंधान को विस्तारित करना, अध्ययनों से प्राप्त शिक्षाओं को आगामी प्रशिक्षणों में सम्मिलित करना, तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को राष्ट्रीय शहरी मिशनों में एकीकृत करना।

4.8 भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (ईआरआर)

इस परियोजना का उद्देश्य प्रगति की समीक्षा करने, मौजूदा कमियों को दूर करने और सहयोगात्मक रूप से दूरदर्शी रणनीतियाँ विकसित करने हेतु प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर पूरे भारत में भूकंप प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएँ और तीन राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित करना है ताकि देश के विभिन्न भूकंपीय रूप से अस्थिर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और शहरी प्रणालियों के भूकंप जोखिम मूल्यांकन, शमन, जन स्वास्थ्य तैयारी और पुनर्निर्माण/पुर्नस्थापना जैसे मुद्दों की पहचान की जा सके। यह 120वीं कांगड़ा भूकंप वर्षगांठ और महान शिलांग भूकंप वर्षगांठ जैसी प्रमुख भूकंप वर्षगांठों के उपलक्ष्य में जागरूकता और तैयारी के प्रयासों को सुदृढ़ करता है।

परियोजना के प्रमुख उद्देश्य:

- भूकंप की तैयारी और समुत्थानशीलता के संबंध में प्रमुख हितधारकों के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाना
- क्षेत्रीय दौरों, अभ्यासों और व्यावहारिक प्रदर्शनों सहित प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से अनुभवनात्मक शिक्षण के अवसर प्रदान करना।
- गुजरात भूकंप-पश्चात् पुनर्निर्माण कार्यक्रम से सीखे गए सबक पर एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण को एकीकृत करना।

परियोजना में शामिल गतिविधियाँ

- तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएँ और तीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, संबंधित विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और इंजीनियरिंग, नगर नियोजन और शहरी विकास पृष्ठभूमि के प्रमुख हितधारकों के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि जोन IV और V क्षेत्रों के लिए प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण हेतु नीति, अभ्यास और अनुसंधान के बीच की खाई को पाटा जा सके। (विषय: स्वास्थ्य तैयारीय आपदा-पश्चात् पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम; शहरी अवसंरचना समुत्थानशीलता; आदि)
- लातूर भूकंप, ग्रेट शिलांग भूकंप, और कांगड़ा भूकंप जैसे प्रमुख भूकंपों का स्मरण समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही, एक भूकंपरोधी भविष्य के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, ताकि जागरूकता और तैयारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

मार्च 2025 तक की उपलब्धियाँ

- भूकंप जोखिम न्यूनीकरण (ईआरआर) के लिए 4 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक दिवसीय पूर्वावलोकन कार्यशाला का आयोजन।
- धर्मशाला में 2-4 अप्रैल, 2025 को ''भूकंप जोखिम न्यूनीकरण'' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और 120वीं कांगड़ा भूकंप वर्षगांठ का आयोजन।
- ''उठो और जवाब दो: भूकंपरोधी भविष्य के लिए युवाओं का आह्वान'' पर 16-17 अप्रैल, 2025 तक दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसे ईकोथॉन-2025 के नाम से भी जाना जाता है।

वित्त पोषण एजेंसी: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

4.9 बाल केन्द्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण

- **सीसीडीआरआर परियोजना**

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत् अनुमोदित एनआईडीएम के बाल केंद्रित डीआरआर केंद्र को एनआईडीएम

और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया है। यह केन्द्र वर्तमान में बाल रक्षा भारत (विश्व स्तर पर सेव द चिल्ड्रन के रूप में जाना जाता है) और चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) द्वारा समर्थित है। यह केंद्र कार्यशील है और एनआईडीएम दक्षिण परिसर में स्थित है। केंद्र का विशेष ध्यान बच्चों के लिए बहु-खतरा संवेदनशीलता/पहचान करने और ऐसे खतरों से बच्चों को बचाने के लिए जीरो टॉलरेंस की दिशा में हितधारकों की क्षमताओं को विकसित करने पर है। सीसीडीआरआर केंद्र राज्यों को उनके अधिकारियों को जोखिम सूचित प्रोग्रामिंग, जीवन चक्र दृष्टिकोण, स्कूल सुरक्षा, बाल अधिकार, बाल जोखिम प्रभाव आकलन के बारे में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता निर्माण में सहायता कर रहा है और तद्नुसार बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने के लिए उनके नीति ढांचे को विकसित कर रहा है। सीसीडीआरआर केंद्र ने युवा और किशोरों के मुद्दों को शामिल करके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया है।

- **सीसीडीआरआर केन्द्र का लक्ष्य**

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति वकालत, परामर्श, नेटवर्किंग, साझेदारी, संसाधन जुटाना और नीति समर्थन, बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र के प्रमुख घटक हैं। इसका मुख्य ध्यान देश में आपात स्थितियों और आपदा स्थितियों के लिए बच्चों और महिलाओं से संबंधित क्षेत्रीय मुद्दों (अर्थात आवश्यकता आकलन, योजना, निगरानी और मूल्यांकन, स्वास्थ्य, पोषण, अधिकार एवं संरक्षण, शिक्षा; जल, स्वच्छता और सफाई; लैंगिक समानता और सशक्तिकरण, विकलांगता समावेशिता, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, किशोरों और युवाओं की भागीदारी आदि) को मुख्यधारा में लाने पर है। सीसीडीआरआर केंद्र की गतिविधियाँ बच्चों के लिए परिणामोन्मुखी मूल प्रतिबद्धताओं (सीसीसी) को सामने लाने के लिए डिजाइन की गई हैं।

मार्च 2025 तक की उपलब्धियां:

यह डेटा तालिका वित्तीय वर्ष (2024-2025) के दौरान आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशाला कार्यक्रमों का अवलोकन प्रस्तुत करती है। कुल 61 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) और एक दिवसीय कार्यशालाएँ शामिल थीं। सभी कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की कुल संख्या 3286 तक पहुँच गई, जो प्रशिक्षण पहलों में महत्वपूर्ण स्तर की भागीदारी को दर्शाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि प्रशिक्षण और कार्यशाला पहलों के लिए यह वर्ष सफल रहा है, जिसमें आमने-सामने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया।

वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2024-मार्च 2025) में पूर्ण हुए प्रशिक्षण/कार्यशालाएँ

कार्यक्रम का प्रकार	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
आमने-सामने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	42	2149
एक दिवसीय कार्यशालाएँ	19	1137
कुल	**61**	**3286**

विषयगत प्रशिक्षण/कार्यशाला आंकड़े (वर्ष 2024-2025)

यह डेटा वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित विषयगत प्रशिक्षण और कार्यशालाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की संख्या का विवरण दिया गया है।

प्रशिक्षण	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
सीसीडीआरआर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	13	686
आपदा जोखिम शमन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों की भागीदारी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	230
आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	7	317
आपदाओं में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	143
मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोइयों/सहायकों के साथ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला	1	80
आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में शिक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	127
आपदाओं में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मनो-सामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	105
आंध्र प्रदेश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	10	461
कुल	**42**	**2149**
कार्यशाला		
सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	8	501
आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों पर कार्यशाला	5	285
आपदा जोखिम शमन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं और किशोरों की भागीदारी पर कार्यशाला	1	75
आपदाओं में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर कार्यशाला	1	80
आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला	3	144
आपदाओं में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मनो-सामाजिक देखभाल पर कार्यशाला	1	52
कुल	**19**	**1137**

प्रशिक्षण मैनुअल और ई–लर्निंग मॉड्यूल

- आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण मैनुअल का प्रारूप तैयार किया गया
- आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर एक प्रशिक्षण नियमावली का मसौदा तैयार किया।

ई–लर्निंग मॉड्यूल विकसित किया गया

- स्कूल सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें
- संरचनाओं से परे स्कूल सुरक्षाः योजना और निवारण
- स्कूलों में एचआरवीसीए और संरचनात्मक सुरक्षा

वित्त पोषण एजेंसियां

बाल रक्षा भारत (बीआरबी), भारत

बाल अधिकार एवं आप (क्राई), भारत

*****

अध्याय 5

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियाँ

ज्ञान प्रबंधन और जागरूकता गतिविधियाँ

5.1 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन की शुरुआत गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार-यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003 में की गई थी। आईडीआरएन के राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को वर्ष 2008 से आईडीआरएन की निगरानी और रख-रखाव का दायित्व सौंपा है। आइडीआरएन एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह उपकरण, मानव संसाधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति के संबंध में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराता है, जो जिला स्तर पर संबद्ध विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध है।

आईडीआरएन पोर्टल को https://idrn.nidm.gov.in पर स्थानांतरित कर दिया गया है और जून 2020 से इसे नए डिजाइन और संवादात्मक रूप के साथ पुनर्निर्मित किया गया है। नया आईडीआरएन वेब पोर्टल नवीनतम वेब तकनीकों और प्लेटफॉर्म स्वतंत्रता, जैसी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जो समझने में आसान है। यह संवादात्मक, उपयोगकर्ताओं के अनुकूल, सुरक्षित और धीमे इंटरनेट कनेक्शन पर भी कार्य निष्पादन जैसी विशेषताओं से सुसज्जित है।

एनआईसी की भूमिका- आईडीआरएन पोर्टल एनआईसी सर्वर पर स्थापित किया गया है

आईडीआरएन की निगरानी और रखरखाव वर्तमान में एनआईडीएम द्वारा केंद्रीयकृत रूप से की जाती है। एनआईडीएम की भूमिका उपयोगकर्ता प्रशासक, विकास और तकनीकी रखरखाव, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता तक सीमित है। एनआईडीएम डेटा संग्रह या अद्यतनीकरण में शामिल नहीं है।

आई.डी.आर.एन कैसे कार्य करता है

राज्य प्राधिकारियों की भूमिका– राज्य राहत विभाग/आपदा प्रबंधन/एसडीएमए आईडीआरएन में आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए डीएम/डीसी के साथ समन्वय करते हैं।

जिला प्राधिकारियों की भूमिका–

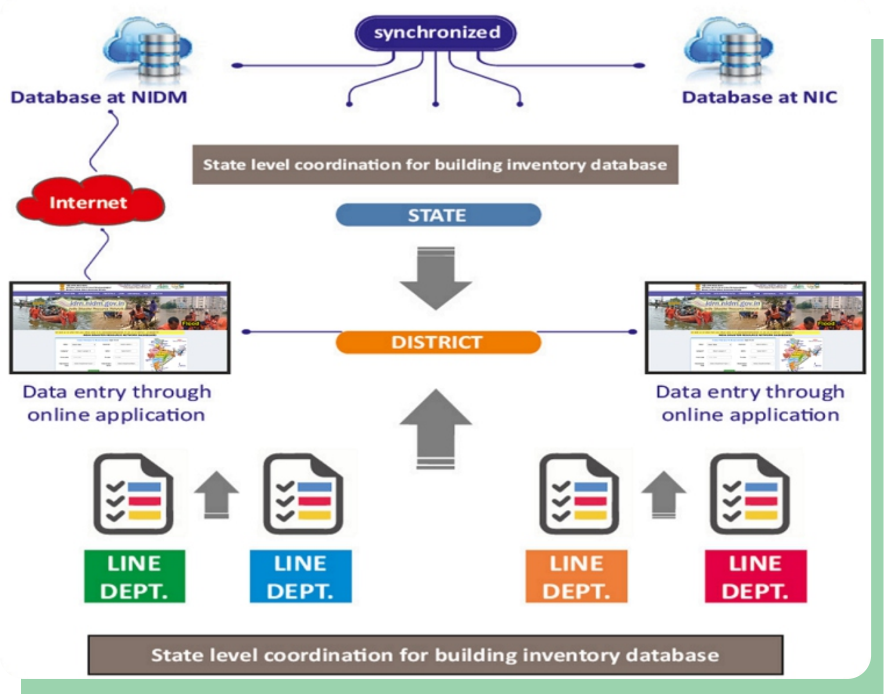

जिला स्तर पर आंकड़ों के संग्रह और उन्हें अद्यतन रूप देने के कार्य को सुगम बनाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। आंकड़ों के संग्रह का प्रारूप सभी सम्बद्ध विभागों और एजेंसियों को जिला प्रशासन द्वारा भेजना होता है और एक या दो सप्ताह में उसे एकत्र करना होता है। जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों द्वारा तकनीकी सेवाओं का उपयोग करते हुए जिला स्तर पर आंकड़ों की प्रविष्टियां की जानी चाहिए ।

आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग

सभी उपलब्ध संसाधनों की अद्यतन जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए कोई भी, किसी भी आपात स्थिति के दौरान आईडीआरएन पोर्टल का उपयोग कर सकता है, जो किसी भी आपात स्थिति के दौरान जानमाल की क्षति और संपत्ति तथा अन्य बुनियादी ढांचे की क्षति को कम करने में अत्यंत सहायक होगा। आईडीआरएन पर संसाधन मदों की सूची देखने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है।

राज्य एवं जिला स्तरीय आईडीआरएन उपयोगकर्ता

राज्य स्तरीय उपयोगकर्ता– आईडीआरएन पोर्टल पर कुल 36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पंजीकृत हैं

जिला स्तरीय उपयोगकर्ता– आईडीआरएन पोर्टल पर कुल 772 जिले पंजीकृत हैं

श्रेणियों की कुल संख्या– 36

वस्तुओं की कुल संख्या– 367

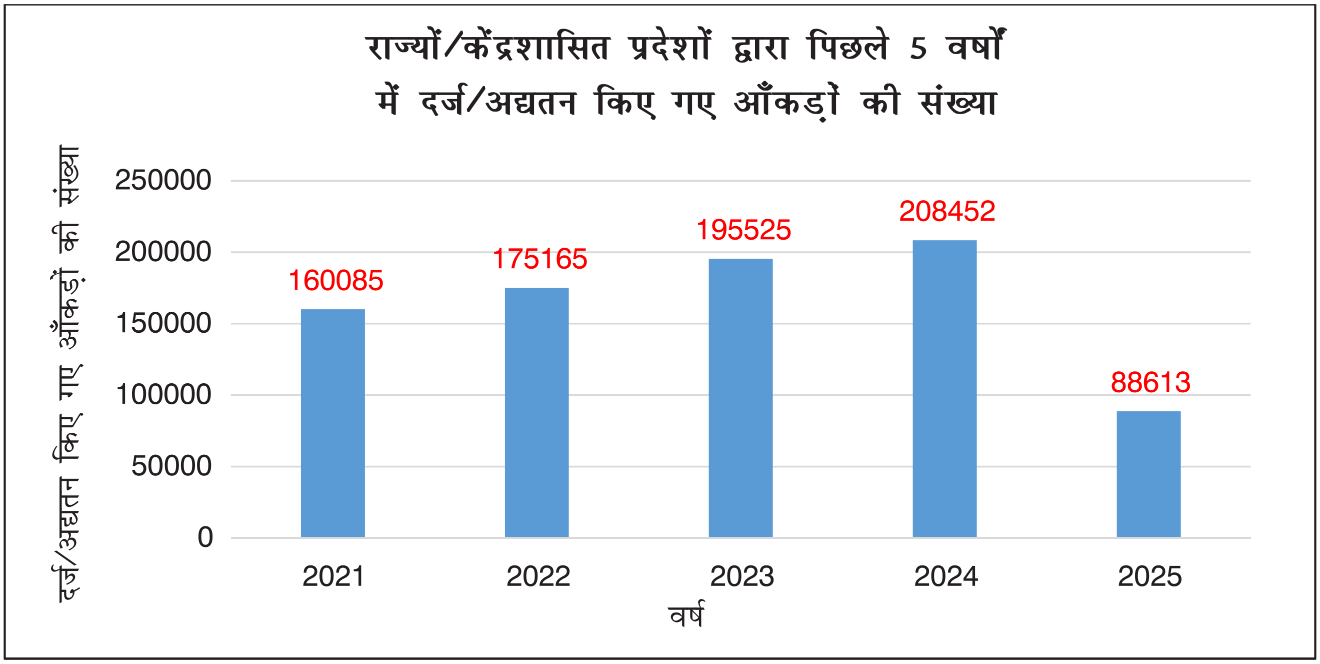

31 मार्च 2025 तक अद्यतन आँकड़े

जन संपर्क प्रयास

- डेटा संग्रह को सुगम बनाने और राज्यों एवं जिलों से नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिवों, राहत आयुक्तों और जिला अधिकारियों को त्रैमासिक पत्र भेजे जा रहे हैं।
- एनआईडीएम की आईडीआरएन टीम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सप्ताह के सातों दिन काम करती है।
- एनआईडीएम हर महीने एमएचए 2047 विजन दस्तावेज में आईडीआरएन डेटा की स्थिति अद्यतन करता है।
- माननीय गृह मंत्री द्वारा विजन-2024 कार्य योजना एवं कार्यक्रम (2019-2024) की समीक्षा बैठकों के दौरान दिए गए निर्देशों से एनडीएमए को अवगत करा दिया गया है, जिससे कि आपदा की स्थिति में निजी संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को अधिक बढ़ाने के प्रयास किए जा सकें। एनडीएमए, एनआईडीएम और गृह मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आपात स्थिति या आपदा की स्थिति में ऐसे स्थानीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाया जा सके।

आईडीआरएन एपीआई

- एनआईडीएम ने एक नई आईडीआरएन एपीआई सेवा विकसित की है जो आपदाओं के दौरान आईडीआरएन डेटाबेस को ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड में एक्सेस करने के लिए उपयोगी एपीआई सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। इसका यूआरएल है: http://idrnapi.nidm.gov.in/swagger/ui/index पर उपलब्ध है।
- केरल ने राज्य में आईआरएस अधिकारियों के लिए बहु-खतरा प्रबंधन के लिए एक प्रशासनिक-स्तरीय ऐप विकसित किया है। इसमें एकरुपता सुनिश्चित करने के लिए केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (केएसडीएमए) आईडीआरएन प्रारूप में एक ही मास्टर दस्तावेज रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

सभी सूचीबद्ध आईआरएस अधिकारियों को एक ही जानकारी उपलब्ध हो।

- **नोटः** आईडीआरएन एपीआई वास्तविक समय में आईडीआरएन डेटाबेस से संसाधन संबंधी जानकारी को स्थानीय सर्वरों तक पहुँचाकर अद्यतन सूची (इन्वेंटरी) उपलब्ध कराने में सहायक है। यह एपीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है ताकि वे आपदा प्रबंधन हेतु अपने स्वयं के संसाधन/इन्वेंटरी डाटाबेस प्रबंधन तंत्र विकसित कर सकें। केरल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पहले ही आईडीआरएन एपीआई का उपयोग करके अपने तंत्र विकसित कर चुके हैं।

5.2 एनआईडीएम प्रशिक्षु डाटाबेस

एनआईडीएम ने अधिकारियों और अन्य हितधारकों के लिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन प्रशिक्षणों, प्रशिक्षुओं और प्रतिभागियों का पूरा डेटाबेस ऑनलाइन रखा गया है ताकि सरकारों/हितधारकों को आपदा की तैयारी के लिए इन प्रशिक्षुओं का पता लगाने में मदद मिल सके। यह जानकारी 2009 से एनआईडीएम की वेबसाइट URL: https://nidm.gov.in/trainee.asp पर भी 2009 से उपलब्ध है।

5.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना एवं उद्देश्य

माननीय प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दस-सूत्री एजेंडे के एजेंडा 6 के अनुरूप, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत के विश्वविद्यालयों और संस्थानों का नेटवर्क (आईयूआई एनडीआरआर-एनआईडीएम) की स्थापना 2021 में एनआईडीएम द्वारा की गई है। यह नेटवर्क जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए), आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015-2030) और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसी वैश्विक पहलों के साथ संरेखित है।

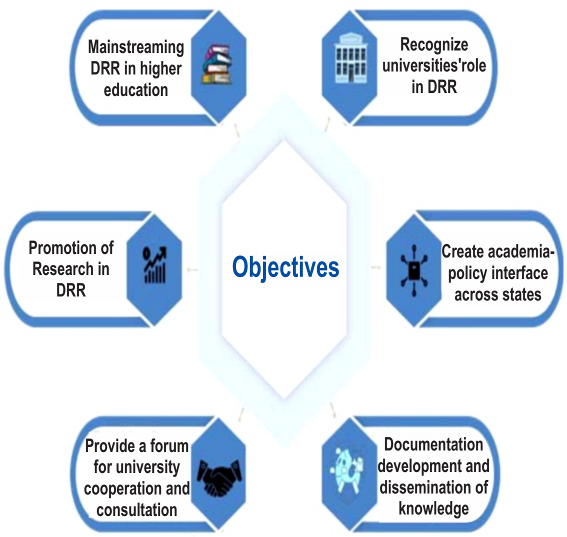

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम का लक्ष्य शिक्षा को बढ़ावा, नवीन तकनीकों को प्रोत्साहन, अनुसंधान का संवर्धन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में क्षमता विकास को सुगम बनाकर एक आपदा-प्रतिरोधी राष्ट्र और सशक्त समुदायों का निर्माण करना है। वर्तमान में, भारत के 325 से अधिक विश्वविद्यालय एवं संस्थान, जिनमें आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएँ शामिल हैं, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम से जुड़े हुए हैं।

मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा को एनआईडीएम डॉक्टोरल फेलोशिप एवं शोध अध्ययन/परियोजना अनुदान प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ थीसिस के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है और आवेदनों की जांच की जा रही है
2. दिसंबर 2024 सत्र से यूजीसी-नेट परीक्षा में आपदा प्रबंधन विषय को सम्मिलित किया गया।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर लघु फिल्म प्रतियोगिता, विशेष रूप से जागरूकता पैदा करने हेतु आयोजित की गई।
4. भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष: सबक, चुनौती एवं संभावनाएं विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया।
5. शिक्षा मंत्रालय के स्वयम पोर्टल पर आपदा प्रबंधन विषय को सम्मिलित करने के प्रस्ताव को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।
6. उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों हेतु यूजीसी रिफ्रेशर कोर्स में आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया।
7. आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम के 2 प्रतिष्ठित सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
8. ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया गया।
9. कुल 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 4 राष्ट्रीय एवं 2 राज्य स्तरीय कार्यशालाएँ/सेमिनार, 1 राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम, 1 क्षेत्रीय एवं 1 राज्य स्तरीय संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान लगभग 1000 संकायों एवं विद्यार्थियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया गया।

31.03.2025 तक की उपलब्धियां

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण शोध सुविधा

शैक्षणिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के लिए, इस सुविधा के अंतर्गत एनआईडीएम डॉक्टोरल फेलोशिप 4 शोधार्थियों को तथा शोध अध्ययन/परियोजना अनुदान 3 परियोजनाओं को प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ''हिमनद झील विस्फोट (जीएलओएफएस) एवं संबंधित मुद्दों'' विषय पर शोध अनुदान हेतु कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। एनआईडीएम डॉक्टोरल फेलोशिप हेतु इस वर्ष 50 आवेदन प्राप्त हुए। रासायनिक एवं औद्योगिक आपदाएँ'' विषय पर सर्वश्रेष्ठ शोध-प्रबंध पुरस्कार हेतु कुल 17 नामांकन प्राप्त हुए।

अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर 'जागरूकता सृजन के लिए विशेष रूप से तैयार आपदा जोखिम न्यूनीकरण' विषय पर लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण, विशेष रूप से जागरूकता निर्माण' विषय पर लघु फिल्म प्रतियोगिता आमंत्रित की। प्रतियोगिता में दो श्रेणियों में लघु फिल्में आमंत्रित की गईं, जिसमें श्रेणी I में कुल 67 लघु फिल्में और श्रेणी II में 13 लघु फिल्में प्राप्त हुईं। श्रेणी-I में सर्वश्रेष्ठ तीन लघु फिल्मों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दूसरी श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ तीन फिल्मों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए, जिन्हें आगे चलकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर लोगो-साझाकरण के आधार पर जन-जागरूकता पहलों में उपयोग किया गया।

भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष: सबक, चुनौतियां एवं संभावनाएं

भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से, 3 दिसंबर 2024 को एक स्मृति कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एनडीएमए, शैक्षणिक संस्थानों और विषय विशेषज्ञों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने इस घटना की 40वीं वर्षगांठ को स्मरण करने के लिए एक व्यापक कार्यवाही

प्रकाशित की है। यह कार्यवाही खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालती है और रासायनिक एवं औद्योगिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नियमों और क्षमता निर्माण को मजबूत करने का आह्वान करती है।

यूजीसी के साथ सहयोगात्मक प्रयास

उच्च शिक्षा संस्थानों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम यूजीसी के सहयोग से काम कर रहा है। इसके लिए प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

i. आपदा प्रबंधन विषय के लिए पहली यूजीसी-नेट परीक्षा दिसंबर 2024 सत्र में आयोजित की गई है।

ii. आपदा प्रबंधन विषय को शिक्षा मंत्रालय के स्वयम पोर्टल पर एकीकृत कर दिया गया है। इसके कार्यान्वयन हेतु परामर्श कार्य अभी चल रहा है।

iii. आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा संस्थानों के संकायों के लिए यूजीसी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में एकीकृत किया गया है।

समझौता ज्ञापन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से सहयोग किया गया है। इनमें शामिल हैं:

1. श्री श्री विश्वविद्यालय, ओडिशा (10 सितंबर, 2024)
2. दिल्ली विश्वविद्यालय (30 अप्रैल, 2024)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार की शुरुआत की है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव डीकन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग के माध्यम से स्थापित किया गया। आशय पत्र पर 15 अक्टूबर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए। वैश्विक सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक ने गोलमेज चर्चा की सह-अध्यक्षता की, **जिसमें सहयोगात्मक आपदा प्रबंधन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच रणनीतिक संवाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।**

अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन

क्र.सं.	सम्मेलन	सम्मेलन का स्तर	सहयोगी विश्वविद्यालय/ संस्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	जलवायु प्रभाव-जलवायु और स्थिरता पर एक दिवसीय सम्मेलन (30 अप्रैल, 2024)	राज्य स्तरीय	दिल्ली विश्वविद्यालय (सरकारी)	174
2.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग पर जन-जागरूकता कार्यक्रम (03 मई, 2024)	राष्ट्रीय	दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय (सरकारी)	129
3.	जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन एवं समुत्थानशीलता: एक समग्र दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (25-26 जुलाई, 2024)	अंतर्राष्ट्रीय	जेएसएस अकादमी, कर्नाटक	150
4.	भूकंप जोखिम शमन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (11-15 नवम्बर, 2024)	राज्य स्तरीय	उत्तरी क्षेत्र के राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली)	20
5.	भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष: सबक, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं विषय पर कार्यशाला (03 दिसम्बर, 2024)	राष्ट्रीय	इंडियन हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली	78
6.	राष्ट्रीय क्रिटिकल केयर नर्सिंग सम्मेलन (एनसीएनसीओएन) (14-15 फरवरी, 2025)	राष्ट्रीय	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	170
7.	हिमालयी क्षेत्र एवं उससे आगे आपदा समुत्थानशीलता बढ़ाने पर सम्मेलन (27-28 मार्च, 2025)	राष्ट्रीय	16वाँ वित्त आयोग एवं लद्दाख विश्वविद्यालय	81
			कुल	802

राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय संकाय विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	संकाय विकास कार्यक्रम	एफडीपी का प्रकार/स्तर	सहयोगी विश्वविद्यालय/ संस्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	आपदा जोखिम प्रबंधन पर एफडीपी (2024 मई, 2024)	राज्य स्तरीय	दिल्ली विश्वविद्यालय (कालिंदी कॉलेज) (सरकारी)	40
2.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए लोगों को प्रेरित करने पर एफडीपी कार्यक्रम (03-07 जून, 2024)	क्षेत्रीय	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (सरकारी)	60
3.	लैंगिकता एवं आपदा प्रबंधन पर एफडीपी (27-31 मई, 2024)	राष्ट्रीय	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	67
			कुल	167

5.4 सूचना प्रसार

5.4.1 पुस्तकालय- एनआईडीएम रोहिणी, दिल्ली परिसरः

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का पुस्तकालय अपने संकाय/कर्मचारियों, भारत और विदेश के शोधार्थियों, एनआईडीएम द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों के प्रतिभागियों और अन्य विजिटिंग फैकल्टी और उपयोगकर्ताओं की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन और शिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है।

यह सर्वश्रेष्ठ संदर्भ पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में से एक है, जिसमें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पुस्तकों, जिल्दबंद जर्नल्स, सरकारी रिपोर्टों, केस स्टडीज और प्रकाशनों का विशाल भंडार है। संस्थान के पुस्तकालय के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपैक) लिंक इंट्रा एनआईडीएम पर उपलब्ध है।

एनआईडीएम पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:-

1. पुस्तकों, जर्नलों और अन्य पठन सामग्री का अधिग्रहण
2. संदर्भ और संप्रेषण कार्य
3. परिसंचरण कार्य
4. पुस्तकालय स्वचालन
5. मुद्रण एवं प्रकाशन
6. राजभाषा संबंधी कार्य
7. स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कार्य

5.4.2 पुस्तकालय- एनआईडीएम दक्षिणी परिसर, विजयवाड़ा

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर स्थित पुस्तकालय संस्थान के अनुसंधान, प्रशिक्षण और शैक्षिक गतिविधियों को सहयोग देने वाले एक प्रमुख शैक्षणिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह आपदा प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में संकाय, शोधकर्ताओं, प्रशिक्षुओं, सलाहकारों और अतिथि पेशेवरों की शैक्षणिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, सूचनात्मक शिक्षण और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुस्तकालय एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है, और संस्थान के क्षमता निर्माण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में अनुसंधान के मिशन में सार्थक योगदान दे रहा है।

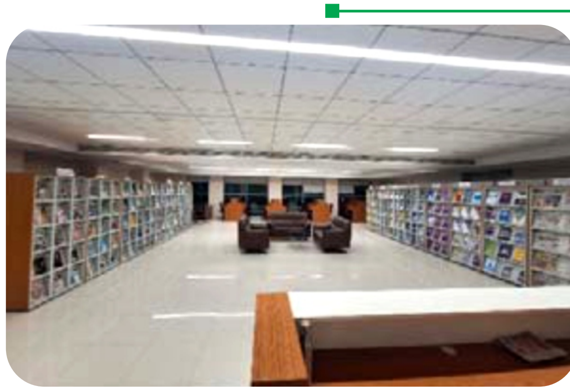

पुस्तकालय में पुस्तकों का एक समृद्ध और विविध संग्रह उपलब्ध है, जिसमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, लोक नीति, पर्यावरण और विकास अध्ययन जैसे आवश्यक विषयों के साथ-साथ व्यक्तिगत विकास को प्रेरित करने और अवकाश के समय पढ़ने के लिए सामग्री भी शामिल है। इसमें एनआईडीएम प्रकाशनों, प्रशिक्षण नियमावलियों, संस्थागत

रिपोर्टों और संदर्भ संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्पित भंडार भी है। उपयोगकर्ताओं को समसामयिक घटनाओं और क्षेत्रीय विकासों से अवगत रखने के लिए, पुस्तकालय चुनिंदा पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की सदस्यता लेता है, जिससे अद्यतन जानकारी तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है। एक समर्पित पठन क्षेत्र एक शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करता है, जो एकाग्रचित होकर अध्ययन और शोध में सहयोग करता है।

5.4.3 दस्तावेजीकरण और प्रकाशन

सूचना को एक संसाधन के रूप में माना जाता है, जो संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देता है। एक परिसंपत्ति के रूप में सूचना के मूल्य को इसके प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से सर्वोच्च स्तर तक लाया जाता है। प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आपदा प्रबंधन और विकास संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए निरंतर आधार पर ठोस प्रयास करना एनआईडीएम के अधिदेशों में से एक है।

5.4.4 सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री

संस्थान को आपदा प्रबंधन और संबंधित पहलुओं पर जानकारी प्रसारित करने का अधिदेश प्राप्त है। इस अधिदेश को पूरा करने के लिए, संस्थान नियमित रूप से एक त्रैमासिक समाचार पत्र (टाइडिंग्स) और विभिन्न प्रकाशन प्रकाशित करता है। विभिन्न आपदाओं और उनके प्रबंधन पर जानकारी और जागरूकता पैदा करने के लिए, एनआईडीएम नियमित रूप से विभिन्न जागरूकता सृजन संदेशों के साथ आईईसी सामग्री प्रकाशित करता है, जिन्हें विभिन्न वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। ये उपकरण एनआईडीएम की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें http://nidm.gov.in-/iec.asp पर देखा जा सकता है। एनआईडीएम द्वारा विकसित आईईसी सामग्री का उपयोग, एनआईडीएम को उचित श्रेय देते हुए, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न हितधारकों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है और व्यापक प्रसार के लिए इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान एनआईडीएम द्वारा मुद्रित प्रकाशनों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

5.5 प्रकाशन

प्रशिक्षण मॉड्यूल

(i) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन संगठनों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु पुस्तिका

यह पुस्तिका एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में संगठनों की समुत्थानशील क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। जोखिम मूल्यांकन और क्षमता संवर्धन के माध्यम से, सभी संगठन अपनी कमजोरियों को न्यूनतम कर सकते हैं तथा विभिन्न आपदा परिस्थितियों में शमन, तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह पुस्तिका संगठनों को उनके विशेष कार्य परिसरों और संवेदनशीलताओं के अनुरूप एक अनुकूलित आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है।

यह पुस्तिका आपदा की तैयारी, प्रतिक्रिया एवं पुनर्प्राप्ति की जटिलताओं को समझने के लिए संगठनों हेतु एक समग्र मार्गदर्शक का प्रतीक है। इसे इस प्रकार से तैयार किया

गया है कि यह सभी संबंधित हितधारकों को ऐसा ज्ञान, उपकरण एवं रणनीतियाँ प्रदान करे, जिससे वे एक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन योजना विकसित कर सकें जो श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की रक्षा करती है तथा आपदा के पश्चात् संचालन की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

(ii) आपातकालीन परिचालन केंद्र (ईओसी)/जन स्वास्थ्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (पीएचईओसी) विकास पैकेज

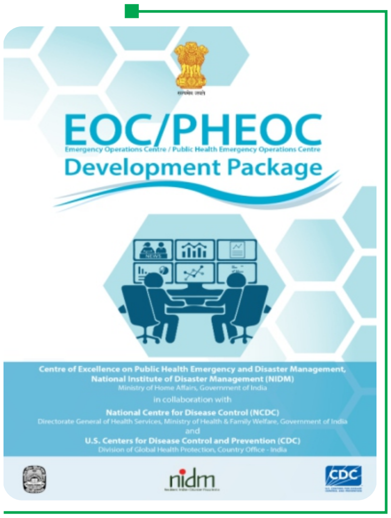

ईओसी/पीएचईओसी विकास पैकेज जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं के लिए सामूहिक तैयारी और प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए एक सहयोगी पहल है। इस दस्तावेज का लक्ष्य समुदायों को आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करना है, जिससे समुदाय की तैयारी को सशक्त बनाने में मदद मिले। पीएचईओसी विकास पैकेज केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह भारत में जन स्वास्थ्य आपातकालीन और आपदा प्रबंधन प्रयासों की नींव रखने वाली अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने का व्यावहारिक रोडमैप है। यह पीएचईओसी के डिजाइन, विकास, प्रबंधन और संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

यह दस्तावेज जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) में व्यापक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देता है।

(iii) चक्रवात आपदाओं के प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

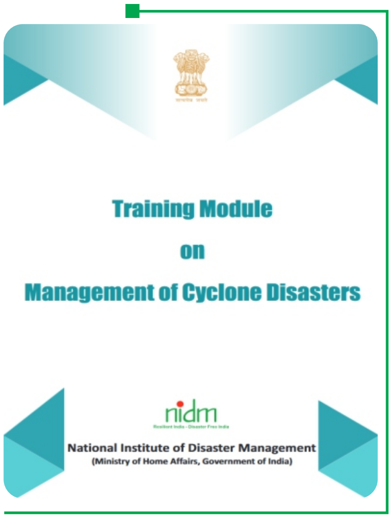

यह मॉड्यूल चक्रवात आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य उन समुदायों/समूहों को सशक्त बनाना है जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रशिक्षण का लक्षित समूह सरकारी अधिकारी, जैसे सीडब्ल्यूसी, आईएमडी, आईएनसीओआईएस, इग्नू आदि हैं। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना और संचार प्रणाली से संबंधित कौशल, ज्ञान और जानकारी प्रदान करके सूचित, कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। यह दस्तावेज इस आवश्यकता पर प्रकाश डालता है कि प्रभावित समुदायों को जागरूक, सूचित और तैयार बनाया जाए, ताकि वे संभावित या आने वाली आपदा जोखिमों का आकलन कर सकें, जोखिमों को कम कर सकें और संभावित खतरों के प्रति खुद को तैयार कर सकें।

(iv) आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान बाल अधिकारों और बाल संरक्षण पर प्रशिक्षण मैनुअल

यह मैनुअल आपदा के समय बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने में दूसरों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से व्यक्तियों को लैस करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में

काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बाल-केंद्रित दृष्टिकोण से आपदा और आपातकालीन योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य न केवल ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि बाल संरक्षण के प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता और समावेशिता की मानसिकता को बढ़ावा देना भी है।

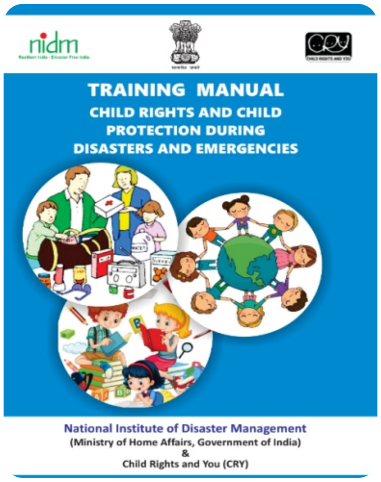

यह प्रशिक्षण मॉड्यूल विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनर्स, बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और स्वयं बच्चों के सहयोग से विकसित किया गया है। इस मैनुअल का अंतिम लक्ष्य ''जोखिम में बच्चों के लिए शून्य सहिष्णुता'' का सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना है, ताकि संकट के समय कोई भी बच्चा पीछे न छूटे।

केस स्टडी

(i) आपदा के बाद की स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

केस स्टडी में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों, नीतियों और दस्तावेजों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर साहित्य की व्यापक समीक्षा की गई है। यह वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा के बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों और केस स्टडीज की व्यापक साहित्य समीक्षा का परिणाम है। आपदा के बाद के परिदृश्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के मुद्दों, चुनौतियों और रणनीतियों को समझने के लिए दो भागों में एक व्यापक साहित्य समीक्षा की गई है।

पहले भाग में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), जापान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा विकसित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है।

दूसरे भाग में, नेपाल, जापान, केरल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और गुजरात के केस स्टडीज की समीक्षा की गई है। इसके अलावा, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान विकसित करने की दिशा में विभिन्न संगठनों द्वारा विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव समाधानों की समीक्षा की गई है।

(ii) चक्रवात बिपरजॉयः गुजरात में शून्य हताहत की जीत

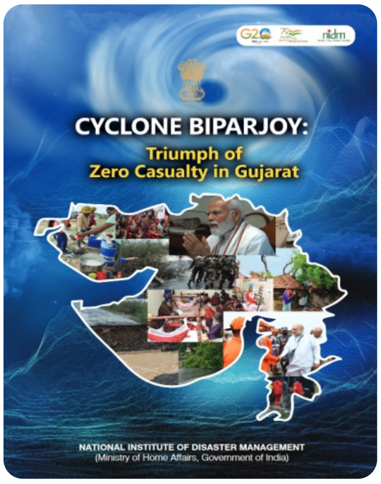

यह केस स्टडी एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी राष्ट्र के लिए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया रणनीतियों को बढ़ाने में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह भारत सरकार के समग्र समन्वय के तहत चक्रवात के प्रभाव को कम करने में शामिल विभिन्न एजेंसियों की कुशल योजना, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित प्रयासों को सामने लाता है। दस्तावेज में समुदाय, जन प्रतिनिधियों और संबंधित विभागों के अधिकारी, और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पदाधिकारियों द्वारा शून्य हताहत लक्ष्य

को प्राप्त करने के लिए एक टीम के रूप में समन्वित तरीके से उठाए गए सक्रिय उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अलावा, यह दस्तावेज आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, आपदा प्रबंधकों, क्षेत्र पदाधिकारियों और समुदायों से विभिन्न स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा।

(iii) भारत में कुछ सामाजिक-आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बाढ़ों के अभिलेखीय रिकॉर्ड (2000-2021)

यह रिपोर्ट वर्ष 2000 से 2021 तक भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आई महत्वपूर्ण बाढ़ों के अभिलेखीय रिकॉर्ड के रूप में कार्य करती है। डेटा को कई स्रोतों से एकत्र किया गया है और इसका उद्देश्य यात्रियों द्वारा भविष्य के संदर्भ के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनना है। यह डेटाबेस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, निर्णयकर्ताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और समुदायों के लिए बेहद उपयोगी होगा।

अभिलेखीय रिकॉर्ड तथ्यात्मक जानकारी, डेटा और पत्रों, रिपोर्टों, नोट्स, ज्ञापनों, तस्वीरों और अन्य प्राथमिक स्रोतों से एकत्रित साक्ष्यों पर आधारित है। यह बाढ़ के पैटर्न, प्रकार, आर्थिक नुकसान और इन घटनाओं की गंभीरता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निष्कर्ष आवश्यक योजना और तैयारी के उपायों पर भी प्रकाश डालते हैं, जिसमें चेतावनियाँ शामिल हैं जो जीवन बचाने, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर सकती हैं।

अध्ययन में पिछले 22 वर्षों में आई महत्वपूर्ण बाढ़ों को शामिल किया गया है और यह संकेत दिया गया है कि असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे नदी तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की आवृत्ति विशेष रूप से अधिक है। इसके अतिरिक्त, उपनगरीय और उपनगरीय क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान अधिक होता है।

कार्यवाही

(i) जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) पर राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही

यह दस्तावेज छप्क्ड द्वारा आयोजित जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) पर राष्ट्रीय सम्मेलन में अग्रणी विशेषज्ञों द्वारा साझा किए गए मुख्य भाषणों और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि को प्रभावी ढंग से उजागर करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करना है।

कार्यवाही जागरूकता बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को संस्थागत बनाने और PHEDM से संबंधित सूचना, ज्ञान और नवाचार के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। भाषणों का संकलन तकनीकी सत्रों के दौरान प्रतिष्ठित वक्ताओं के व्यापक

अनुभव, विशेषज्ञता और ज्ञान से समृद्ध है। चर्चाओं में भारत की G20 अध्यक्षता के विषय पर जोर दिया गया: ''वसुधैव कुटुम्बकम,'' जिसका अर्थ है ''एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य।''

(ii) जुलाई 2023 की घटना पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली में यमुना शहरी बाढ़ पर हितधारकों की एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला

यह दस्तावेज यमुना शहरी बाढ़ के दौरान दिल्ली में आने वाली समस्याओं और इसे रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताता है। यह दिल्ली की शहरी बाढ़ भेद्यता, शहरी बाढ़ (जोखिम) प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ के कारणों और बाढ़ के प्रभावों पर भी प्रकाश डालता है। यह कार्यशाला जुलाई 2023 में आई बाढ़ पर आधारित है। प्रख्यात वक्ताओं ने दिल्ली और अन्य महानगरों में बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना, बाढ़ से पहले और बाद में की जाने वाली कार्रवाइयों और प्रस्तावित समाधानों और आगे की राह के बारे में चर्चा की।

यह कार्यशाला की प्रमुख चर्चा, प्रस्तुतियों और परिणामों को समाहित करता है, जो दिल्ली में भविष्य की बाढ़ शमन रणनीतियों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और अग्रिम पंक्ति के उत्तरदाताओं की अंतर्दृष्टि बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया प्रयासों में बेहतर समन्वय, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बुनियादी ढांचे के विकास और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। इसमें बाढ़ की तैयारी के उपायों, बाढ़ प्रतिक्रिया योजना के साथ-साथ समन्वय, संसाधन आवंटन और बाढ़ प्रतिक्रिया प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी पर विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों की प्रस्तुति शामिल है।

(iii) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अनुकूलन, समुत्थानशीलता और स्थिरता ज्ञान नेटवर्क पर उच्च स्तरीय परामर्श कार्यशाला रिपोर्ट

यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रख्यात विशेषज्ञों की सिफारिशों और मूल्यवान अंतर्दृष्टि का संकलन है। यह आपदा लचीलापन और क्रॉस-कटिंग मुद्दों में रणनीतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में एकीकृत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य मौजूदा चुनौतियों, उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता, संभावित सहयोगियों और योगदानकर्ताओं की पहचान करके और नेटवर्क के लिए दायरे और संरचनात्मक विकल्पों को समझकर जलवायु अनुकूलन और लचीलापन ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क के एक नेटवर्क की अवधारणा बनाना है। यह पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (इको-डीआरआर) जैसे अभिनव तरीकों को बढ़ावा देता है।

(iv) जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) पर उच्च स्तरीय शासन और नेतृत्व शिखर सम्मेलन

जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) पर उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों की खोज करता है, जिसका उद्देश्य स्थायी आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है।

इसका उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी, बहुस्तरीय, अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-अनुशासनात्मक हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए मानव क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बढ़ाना और भौतिक और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समृद्धि और स्थिरता की संस्कृति के पोषण के लिए स्थायी प्रक्रियाओं, प्रक्रियाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और प्रोटोकॉल को संस्थागत बनाना है। यह PHEDM के ढांचे में टियर-1 और टियर 5 की निजी भूमिका, प्रभावी तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करने में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है।

(v) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस-2024 – सशक्त युवा सुरक्षित भविष्य

अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (आईडीडीआरआर)-2024, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा 23 अक्टूबर, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसका विषय था ''सशक्त युवा, सुरक्षित भविष्य''। भारत में क्षमता निर्माण के सर्वोच्च संस्थान के रूप में, एनआईडीएम हर साल इस दिवस को मनाता है। यह प्रकाशन डीआरआर दिवस के दौरान हुई प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालता है। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जलवायु संकट का समाधान बच्चों और युवाओं के कंधों पर है।

इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार; श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार; श्री गोविंद मोहन, आईएएस, केंद्रीय गृह सचिव; श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य एवं प्रमुख, एनडीएमए और कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम शामिल थे। उन्होंने एक सुदृढ़ भविष्य के निर्माण पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए।

इस प्रकाशन में एनआईडीएम द्वारा आयोजित एक लघु फिल्म प्रतियोगिता से चयनित फिल्मों के प्रदर्शन का भी विवरण दिया गया है, जिसका उद्देश्य समुदायों को आपदा संबंधी जोखिमों को समझने और उन्हें कम करने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त, इसमें गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रस्तुत 12 स्टॉलों की तस्वीरें भी शामिल हैं, जो आपदा सिमुलेशन के माध्यम से आपदा प्रबंधन को प्रदर्शित करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम ''काला सांझ'' में प्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति और पंडित अभिमन्यु लाल और सुश्री वर्षा दास गुप्ता द्वारा मनमोहक कथक गायन प्रस्तुत किया गया।

(vi) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) का तीसरा सत्र

यह कार्यवाही 10, 11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित ''बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशीलता का निर्माण'' विषय पर एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में किया। यह दस्तावेज बैठक में तैयार की गई कार्ययोजना पर प्रकाश डालता है, जिसमें संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराकर स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को और मजबूत बनाने तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एनबीएस के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने और एनडीएमए, एनआईडीएम, एमओईएफसीसी, डीएसटी, डीएम विभाग आदि के समन्वय से डीआरआर योजनाओं और कार्य रूपरेखाओं के साथ उन्हें एकीकृत करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की जाएगी। मंत्रिस्तरीय सत्र में जिन प्रमुख बिंदुओं पर विशेष रूप से बल दिया गया, उनमें तटीय क्षेत्रों में आपदा-रोधी भवनों के निर्माण को प्राथमिकता देना; नदी कटाव, आंधी-तूफान, बिजली गिरने तथा हीट वेव जैसी घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित करना; जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सुदृढ़ एवं समग्र प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना; भूस्खलन की संभावनाओं को कम करने के लिए ढलानों की कटाई में नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना; बीमा को शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बनाना तथा स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व में निवेश कर उसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता पर बल देना शामिल है। इस दस्तावेज में सेंदाई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) की प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न विषयों पर आयोजित 19 कर्टेन रेजर कार्यक्रमों/पूर्व-कार्यक्रमों का विवरण एवं उनके चित्र सम्मिलित किए गए हैं।

आपदा और विकास

(i) आपदा और विकास (खंड 12 अंक 02 जुलाई से दिसंबर 2023)

संस्थान ''आपदा और विकास'' नामक एक अर्धवार्षिक जर्नल प्रकाशित करता है। वर्तमान अंक (जुलाई-दिसंबर 2023, खंड 12, अंक 02) केरल में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों की आजीविका पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की पड़ताल करता है। यह सियांग नदी संकट के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सफलता की कहानी पर भी प्रकाश डालता है, हिमाचल प्रदेश में भूकंपीय क्षेत्रों का भू-स्थानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और जोखिम संचार और सामुदायिक जुड़ाव रणनीतियों पर चर्चा करता है।

यह अंक शिक्षाविदों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के विविध दृष्टिकोणों, प्रत्यक्ष अनुभवों और शोध निष्कर्षों को एक साथ लाता है। यह पाठकों को कोविड-19 के प्रकोप के कारण समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं, उनकी प्रबंधन रणनीतियों, संबंधित जोखिमों और तैयारी के उपायों, जिनमें निवारक और शमन विधियाँ भी शामिल हैं, के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

(ii) आपदा और विकास (खंड 13 अंक 1, जनवरी से जून 2024)

''आपदा और विकास'' शीर्षक से प्रकाशित यह इस वर्ष का पहला अर्धवार्षिक जर्नल है। इसका यह अंक (जनवरी–जून 2024, खंड 13, अंक 01) विविध लेखों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और संबंधित विकासात्मक विषयों के विस्तारित क्षेत्र को दर्शाता है। यह समुदाय-आधारित आपदा समुत्थानशीलता रणनीतियों, नवीन तकनीकी हस्तक्षेपों और विभिन्न नीतिगत ढाँचों का विश्लेषण करता है। लेखक आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया में असुरक्षित समुदायों और आदिवासी समाज के महत्व पर जोर देते हैं। ये लेख दर्शाते हैं कि समुदाय की भागीदारी आपदा प्रबंधन प्रथाओं को कैसे बदल सकती है।

इसके अतिरिक्त, वे अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं में उल्लिखित नीतियों, जैसे कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई रूपरेखा, और जमीन पर उनके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। यह मुद्दा इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकारों, संस्थानों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों से निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

(iii) आपदा एवं विकास (खंड 13, अंक 02, जुलाई से दिसंबर 2024)

''आपदा और विकास'' शीर्षक से प्रकाशित यह अर्धवार्षिक जर्नल का दूसरा अंक है। 2024 का यह अंक (जुलाई-दिसंबर 2024, खंड 13, अंक 02) दुनिया भर में आई विनाशकारी आपदाओं की श्रृंखला का विवरण प्रस्तुत करता है। यह अवधि भारत के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रही, जहां अनेक विनाशकारी आपदाओं ने जनजीवन, आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्रों को गहराई से प्रभावित किया। इस अंक में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भूस्खलन संभाव्यता मानचित्रण (Landslide Susceptibility Mapping) और सिक्किम हिमालय में भूस्खलनों के कारणों और प्रभावों के आकलन के माध्यम से भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही, उत्तराखंड स्थित पश्चिमी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वनाग्नि की तीव्रता के आकलन हेतु भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलन क्षमता जैसे विषयों पर भी इस पत्रिका में प्रकाश डाला गया है।

न्यूजलेटर: टाइडिंग्स

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रकाशित न्यूजलेटर ''टाइडिंग्स'' एक त्रैमासिक प्रकाशन है। यह न्यूजलेटर संस्थान द्वारा नियमित रूप से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं से प्राप्त सुझावों और सिफारिशों को उजागर करता है। यह प्रकाशन आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पूर्व सूचना प्रदान करने के साथ-साथ संकाय विकास, सफलता की कहानियाँ, विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों और संस्थान में होने वाली महत्त्वपूर्ण यात्राओं से संबंधित समाचारों को भी सम्मिलित करता है।

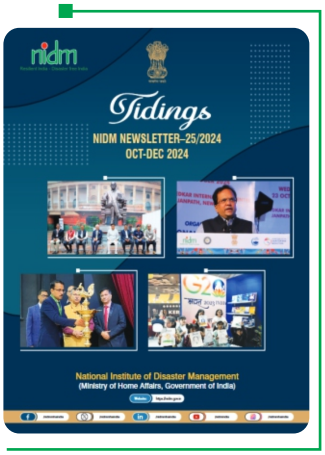

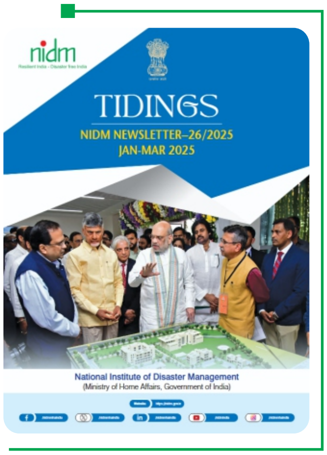

वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन 2023–24 अंग्रेजी एवं हिन्दी–दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन संस्थान के दृष्टिकोण, मिशन, दायित्व, संरचना, कार्यों एवं प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करता है। यह प्रतिवेदन आठ अध्यायों में विभाजित है: परिचय, संगठनात्मक संरचना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परियोजनाएँ, ज्ञान प्रबंधन एवं जन–जागरूकता गतिविधियाँ, सम्मेलन/कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/आमने–सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्य पहल तथा वित्त एवं लेखा, जिसमें लेखा परीक्षण रिपोर्ट एवं बजट सम्मिलित है। संस्थान की उपलब्धियों को मानचित्रों, चार्टो एवं आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो भौगोलिक, प्रतीकात्मक एवं कालगत प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में छह परिशिष्ट शामिल हैं, जिनमें संस्थान द्वारा आयोजित ऑन–कैंपस एवं ऑफ–कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची तथा एनआईडीएम की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सूची दी गई है।

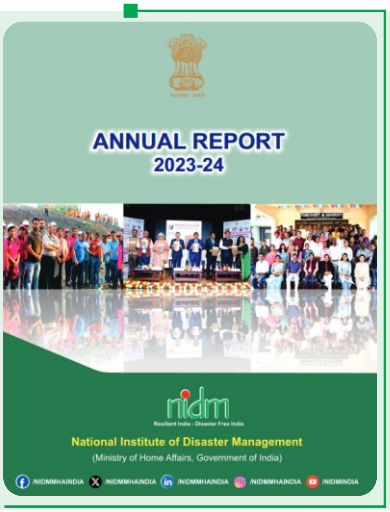

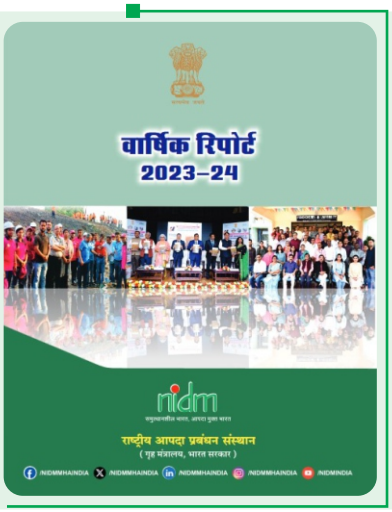

आईईसी सामग्री

(i) स्थानीय भाषाओं में क्या करें और क्या न करें की उपलब्धता

एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ''सामान्य आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें'' शीर्षक से एक गाइड प्रकाशित की है। यह दस्तावेज भूकंप, चक्रवात, शीत लहर, गर्मी की लहर, सुनामी, बाढ़, आग, भूस्खलन, सूखा, महामारी, आंधी, बिजली और जंगल की आग सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के बारे में बताता है। यह गाइड आपदा प्रबंधन में शामिल संस्थानों, संगठनों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है।

सुरक्षा मैनुअल ''सामान्य आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें'' अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ कन्नड़, मलयालम, ओडिया, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली और गुजराती जैसी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।

(ii) ब्रेल लिपि में आम आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें

एनआईडीएम ने दृष्टिबाधित छात्रों को आपदा प्रबंधन के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए ''ब्रेल लिपि में आम आपदाओं के लिए क्या करें और क्या न करें'' शीर्षक से एक गाइड प्रकाशित की है। इस दस्तावेज में ब्रेल लिपि के पृष्ठ हैं जो भूकंप, चक्रवात, शीत लहर, गर्मी की लहर, सुनामी, बाढ़, आग, भूस्खलन, सूखा, महामारी, आंधी, बिजली और जंगल की आग सहित विभिन्न आपदाओं के दौरान आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ब्रेल दस्तावेज उन संस्थानों और संगठनों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र संचालित करते हैं।

(iii) एनआईडीएम पत्रक (अंग्रेजी)

एनआईडीएम के बारे में तीन-भाग वाला लीफलेट इसकी प्रबंधन संरचना, दृष्टि, मिशन, कार्यों और विभिन्न गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। यह लीफलेट एनआईडीएम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित करता है, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री के 10-सूत्री एजेंडे के एजेंडा 6 के हिस्से के रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएन डीआरआर) की स्थापना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) नेटवर्क से जोड़ना है। यह लीफलेट राज्यों को एनआईडीएम द्वारा दिए जाने वाले रणनीतिक समर्थन पर भी प्रकाश डालता है और इसके नियमित प्रकाशनों का विवरण देता है, जिसमें पत्रिकाएँ, त्रैमासिक समाचार पत्र ''टाइडिंग्स'', केस स्टडी, कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्ट और एनआईडीएम में उपलब्ध सुविधाएँ शामिल हैं।

(iv) एनआईडीएम पत्रक (हिंदी)

एनआईडीएम के बारे में एक तीन-भाग वाला पत्रक हिंदी में भी उपलब्ध है, जिससे संस्थान हमारे देश के हिंदी भाषी राज्यों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। यह इसके प्रबंधन ढांचे, विजन, मिशन, कार्यों और विभिन्न गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। पत्रक में एनआईडीएम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को रेखांकित किया गया है, जिसमें माननीय प्रधान मंत्री के 10-सूत्री एजेंडे के एजेंडा 6 के हिस्से के रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारत विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएन डीआरआर) की स्थापना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) नेटवर्क से जोड़ना है। पत्रक में एनआईडीएम द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले रणनीतिक समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया है और इसके नियमित प्रकाशनों का विवरण दिया गया है, जिसमें पत्रिकाएँ, त्रैमासिक समाचार पत्र ''टाइडिंग्स'', केस स्टडी, कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्ट और एनआईडीएम में उपलब्ध सुविधाएँ शामिल हैं।

(v) आईयूआईएनडीआरआर पत्रक (अंग्रेजी)

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर माननीय प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे के एजेंडा 6 के अनुसरण में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क की स्थापना की है। यह पहल जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर वैश्विक मुद्दों, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–2030) और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक कदम है। आईयूआईएनडीआरआर का लक्ष्य कई उद्देश्यों को पूरा करना है, जिसमें अन्य लक्ष्यों के अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना, राज्यों में एक अकादमिक नीति इंटरफेस की सुविधा प्रदान करना, डीआरआर के बारे में ज्ञान का प्रसार करना और उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर डीआरआर को बढ़ावा देना शामिल है।

(vi) एनआईडीएम पत्रक (तेलुगु)

एनआईडीएम के बारे में तीन-भाग वाला पत्रक (लीफलेट) एनआईडीएम के साउथ कैंपस द्वारा तेलुगु में अनुवादित और प्रकाशित किया गया था, ताकि तेलुगु-भाषी समुदाय की सेवा की जा सके। यह लीफलेट इसकी प्रबंधन संरचना, दृष्टि, मिशन, कार्यों और विभिन्न गतिविधियों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। यह लीफलेट राज्यों को एनआईडीएम द्वारा दिए जाने वाले रणनीतिक समर्थन पर प्रकाश डालता है और इसके नियमित प्रकाशनों का विवरण देता है, जिसमें पत्रिकाएँ, त्रैमासिक समाचार पत्र ''टाइडिंग्स'', केस स्टडी, कार्यवाही, वार्षिक रिपोर्ट और एनआईडीएम में उपलब्ध सुविधाएँ शामिल हैं।

*****

अध्याय 6

प्रमुख कार्यक्रम / कार्यशाला / सम्मेलन / सेमिनार और बैठकें

प्रमुख कार्यक्रम/कार्यशाला/ सम्मेलन/सेमिनार और बैठकें

1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के दौरान एनआईडीएम प्रशिक्षण कैलेंडर में सूचीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त, अन्य गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं:

6.1 एनआईडीएम दक्षिणी परिसर का उद्घाटन, 19 जनवरी 2025, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री (सहकारिता) श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), दक्षिणी परिसर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण, माननीय केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव, श्री गोविन्द मोहन, अतिरिक्त सचिव, गृह मंत्रालय, श्री संजीव कुमार जिंदल, सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, एनडीएमए, श्री राजेंद्र सिंह, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार, मानव संसाधन विकास मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री एन. लोकेश, माननीय गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रीमती वी. अनीता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में किया।

6.2 वेटलैंड नॉलेज नेटवर्क को संकल्पित करने के लिए राउंडटेबल चर्चा, 02 अप्रैल 2024, उत्तर प्रदेश

आईआईटी–रुड़की, ग्रेटर नोएडा परिसर के एकीकृत अनुकूलन, आपदा जोखिम समुत्थानशीलता और स्थिरता केंद्र (आईसीएआरएस) में एक गोलमेज चर्चा का आयोजन किया गया। इस संवाद में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आईआईटी रुड़की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (डब्ल्यूआईएसए), जीआईजेड–इंडिया के प्रतिनिधि सहित वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित कई एनजीओ और एजेंसियों ने भाग लिया, जिनमें डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन), ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसायटी (सीड्स), भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई), नेचर कंजरवेंसी (टीएनसी, गोरखपुर पर्यावरण कार्रवाई समूह (जीईएजी) और योजना और वास्तुकला स्कूल शामिल हुए।

श्री रवींद्र सिंह, निदेशक, भारत–जर्मन जैव विविधता कार्यक्रम, जीआईजेड–इंडिया ने एक स्व–संयमित ज्ञान नेटवर्क लागू करने का सुझाव दिया, जो वेटलैंड प्रबंधन के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित करेगा। प्रो. अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख, ईसीडीआरएम, एनआईडीएम ने ज्ञान और डाटा संसाधनों को समेकित करने और जलवायु अनुकूलन, समुत्थानशीलता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. रितेश कुमार, निदेशक, वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया (डब्ल्यूआईएसए) ने देश में वेटलैंड संरक्षण से संबंधित नीतिगत और कार्यक्रम स्तर पर हो रही प्रगति की जानकारी दी।

डॉ. रमेश एम, वैज्ञानिक 'एफ', पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सरकार के उन प्रयासों का विवरण दिया जिनमें अन्य मंत्रालयों जैसे पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर वेटलैंड संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने 'सेव वेटलैंड कैंपेन' के दौरान देश द्वारा प्राप्त उपलब्धियों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'अमृत धरोहर' पहल से परिचय कराया। इस प्रकार उन्होंने वेटलैंड संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। आईआईटी रुड़की के प्रो. आशीष पांडे ने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में संस्थान की भूमिका और आईसीएआरएस की स्थापना के उद्देश्य को उजागर किया, जो देश के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता निर्माण के प्रयासों को मजबूत करने का माध्यम है।

6.3 पर्यावरण अध्ययन के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अध्ययन–सह–शैक्षणिक भ्रमण, 19 अप्रैल 2024, दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण अध्ययन विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में जानकारी दी गई और तैयारियों में समुदाय की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त, छात्रों को यह बताया गया कि वे कैसे एनआईडीएम के साथ मिलकर आईयूआईएनडीआरआर के विश्वविद्यालय नेटवर्क के माध्यम से अनुसंधान

और विकास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें यह भी समझाया गया कि उनका शोध किस प्रकार आपदाओं को कम करने और समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में उपयोगी साबित हो सकता है। छात्रों को एनआईडीएम के इंटर्नशिप कार्यक्रमों, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मों और अन्य संसाधनों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिनके माध्यम से वे आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो छात्रों को भविष्य के निर्माण में योगदान देने के अनेक अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम में इस पर भी बल दिया गया कि समुदाय के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी न केवल उन्हें भविष्य के नेता के रूप में सशक्त बनाएगी, बल्कि एक सुरक्षित और अधिक समुत्थानशील समाज के निर्माण में भी सहायक सिद्ध होगी।

6.4 आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जिला स्तरीय विजेताओं के लिए अध्ययन-सह-शैक्षणिक भ्रमण, 25-28 अप्रैल 2024, दिल्ली

सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसएसडीएमए) के अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा चार दिवसीय अध्ययन-सह-शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। यह भ्रमण उन छात्रों के लिए आयोजित किया गया, जो एसएसडीएमए द्वारा आयोजित 2023 की जिला स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के विजेता रहे थे। चार दिवसीय दिल्ली भ्रमण के हिस्से के रूप में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर एक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन एनआईडीएम के रोहिणी परिसर में किया गया, जहां छात्रों के साथ संस्थान की विभिन्न गतिविधियों, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से संबंधित ''क्या करें और क्या न करें'', आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अवधारणाएं, संस्थागत ढांचा, स्कूल सुरक्षा आदि विषयों पर संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने कई प्रश्न पूछे जिन पर गहन चर्चा की गई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कार्यकारी निदेशक श्री राजेन्द्र रत्नू ने छात्रों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्र में अपने-अपने स्कूलों के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए प्रेरित किया और उनके अनेक जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल समाधान से संबंधित कई नवाचारों पर भी चर्चा की। डॉ. आमिर अली खान, प्रमुख, रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवीजन और कार्यक्रम संयोजक, ने कार्यशाला के दौरान विशेष रूप से सिक्किम में आने वाली आपदाओं, उनसे जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधानों पर चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि युवाओं को परिवर्तनकर्ता के रूप में कैसे जोड़ा जा सकता है। छात्रों को दिल्ली भ्रमण के दौरान राजधानी के कुछ ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थलों की सैर भी कराई गई। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर वर्तमान समय में आपदा जोखिम के दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विरासत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़ी पहलुओं को जाना। इस अनुभव ने उन्हें व्यावहारिक चुनौतियों और उनके समाधान की कल्पना करने में मदद की।

6.5 राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) अनुसंधान सुविधा की पहली अकादमिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) बैठक, 26 अप्रैल 2024, दिल्ली।

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम ने अपने रोहिणी परिसर में पहली अकादमिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) की बैठक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य एनआईडीएम डॉक्टरेट फेलोशिप, शोध परियोजना/अध्ययन और सर्वश्रेष्ठ थीसिस रैंकिंग के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण अनुसंधान सुविधा हेतु प्रस्तावों के लिए विज्ञापन देने से पहले अनुसंधान के लिए विषयगत क्षेत्रों को अंतिम रूप देना था। इसमें शामिल विशिष्ट सदस्यों में डॉ. संजीव चोपड़ा, पूर्व निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीय श्री पवन कुमार, निदेशक (डीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार; प्रो. आर.के. सिन्हा, कुलपति, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालयय प्रो. प्रतीक शर्मा, कुलपति, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय; प्रो. विनीता सहाय, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया; डॉ. के. श्रीनिवास, उप निदेशक, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी); श्री अभिनव वालिया, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए); डॉ. श्वेता बैद्य, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए); डॉ. प्रीति सोनी, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम थे।

श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से., ईडी, एनआईडीएम ने एआरसी बैठक की अध्यक्षता की और एआरसी के विशिष्ट सदस्यों को सम्मानित किया। श्री पी. एन. राय (सेवानिवृत्त आईपीएस) सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि थे। डॉ. आमिर अली खान, प्रमुख, आरआईडी, इस बैठक में विशेष आमंत्रित थे। डॉ. प्रीति सोनी ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) अनुसंधान सुविधा और एआरसी बैठक के एजेंडे पर चर्चा की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया और सभी एआरसी सदस्यों ने राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) अनुसंधान सुविधा के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने से पहले अनुसंधान के लिए विषयगत क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

6.6 डाक सेवाओं के ग्रुप ''बी'' अधिकारियों के लिए ''प्रशासन में उत्कृष्टता कार्यक्रम'' (प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम), 08 मई 2024, उत्तर प्रदेश

डाक सेवाओं के ग्रुप ''बी'' अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जीएमआरडी के प्रमुख प्रो. सूर्य प्रकाश ने आपदा प्रबंधन की मूल अवधारणाओं पर चर्चा की, जिसमें आपात स्थितियों और आपदाओं को कम करने, तैयारी करने, प्रतिक्रिया देने और उनसे उबरने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण शामिल है। इस प्रक्रिया में संभावित खतरों की पहचान, जोखिम का आकलन, और समुदायों और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपायों को लागू करना शामिल है।

प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकारी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों को शामिल किया जाता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक समुत्थानशीलता को बढ़ाना, जान-माल की हानि को कम करना और आपदा के बाद

तेजी से पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य करने में सक्षम बनाना था। इसके अलावा, अधिकारियों ने एचवीसीआर (हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी और रिस्क) गतिविधियों में भाग लिया, जिससे उन्हें सैद्धांतिक सत्रों को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली।

6.7 राजमार्ग और सड़क क्षेत्र में समुत्थानशील बुनियादी ढांचा प्रणाली पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम, 10 मई 2024, दिल्ली

राजमार्गों और सड़क बुनियादी ढांचे में समुत्थानशीलता की समझ और इसके क्रियान्वयन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका और प्राकृतिक व मानवजनित व्यवधानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर रहा। चर्चा के दौरान यह जोर दिया गया कि समुत्थानशील बुनियादी ढांचा तैयार करने में उन्नत शोध, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के एकीकरण की अत्यंत आवश्यकता है।

6.8 भूकंप जोखिम न्यूनीकरण पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, 07 जून 2024, दिल्ली

यह कार्यशाला श्री राजेन्द्र रत्नू, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम के संरक्षण और मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यशाला के संयोजक एवं समुत्थानशील अवसंरचना प्रभाग के प्रमुख डॉ. आमिर अली खान ने "शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय स्तर पर भूकंप की तैयार" विषय पर प्रस्तुति दी और प्रतिभागियों के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने परिवार, सहकर्मियों और समुदाय के भीतर भूकंप की तैयारियों और सुरक्षा पर चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया और एनआईडीएम के स्टाफ की आंतरिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने संस्थान के भीतर भूकंप जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन करने के विभिन्न तरीकों को विस्तार से समझाया और नियमित जोखिम मूल्यांकन तथा आपातकालीन तैयारी योजनाओं को अद्यतन करने के महत्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में संस्थान से बाहर भी जानकारी के प्रचार-प्रसार और जन-जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इस जागरूकता कार्यशाला में भूकंप के समय व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर सुरक्षा को प्रभावी बनाने और इस दौरान "क्या करें और क्या न करें" की व्यावहारिक पद्धति पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम ने भूकंप के दौरान संरचनात्मक क्षति के गंभीर मुद्दे को रेखांकित किया और संरचनाओं को सुरक्षित व सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपायों और सावधानियों पर मार्गदर्शन प्रदान किया।

6.9 राहत आयुक्तों/सचिवों (आपदा प्रबंधन) एवं राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की अग्निशमन सेवाओं का दो-दिवसीय वार्षिक सम्मेलन, 11-12 जून 2024, नई दिल्ली

राहत आयुक्तों/सचिवों (आपदा प्रबंधन) तथा राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), नागरिक सुरक्षा, होम गार्ड एवं अग्निशमन सेवाओं के प्रतिनिधियों का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा के बाद क्षति का आकलन, आपदा मोचन बल की भूमिका, तटीय आपदाएं, सूनामी, समुद्री तूफान और चक्रवात के लिए उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, डॉ. पी.के. मिश्रा ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए छह मंत्र प्रस्तुत किए। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अन्य देशों को आपदा के समय सहायता प्रदान करने में भी सक्षम है। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और जी20 के नए आपदा जोखिम प्रबंधन कार्य समूह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई है।

उद्घाटन सत्र में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सभी हितधारकों को एकजुट होकर कार्य करने और ज्ञान साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और प्रभावशीलता लाई जा सके।

6.10 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (डीएमपी-डीएफपीडी) के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी हेतु कार्य समूह की बैठक,14 जून 2024, दिल्ली

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण (डीएमपी-डीएफपीडी) के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी हेतु पहली कार्य समूह बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। यह बैठक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के मुख्यालय, दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में डीएफपीडी, एफसीआई, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी), भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) कानपुर, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (आईजीएमआरआई), वेयरहाउसिंग विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) सहित 15 से अधिक प्रतिष्ठित

विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को आपदाओं के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए सुदृढ़, समन्वित और व्यावहारिक रणनीतियों का निर्माण करना था, ताकि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

6.11 चक्रवात बिपरजॉय की पहली वर्षगांठ की स्मृति में चक्रवात जागरूकता एवं तैयारी पर कार्यशाला, 19 जून 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एनआईडीएम, रोहिणी परिसर में चक्रवात बिपरजॉय की पहली वर्षगांठ मनाई। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने प्रो. सूर्य प्रकाश, प्रमुख जीएमआर प्रभाग और श्री सुरेन्द्र ठाकुर, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम के साथ कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला में चक्रवात के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यशाला तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति की महत्ता को रेखांकित करता है और अवलोकन संबंधी आंकड़ों और पूर्वानुमान को एकीकृत प्लेटफार्म पर लाने की वकालत करता है। इस कार्यशाला की प्रमुख सिफारिशों में वास्तविक समय में आंकड़ों के संग्रह को बढ़ाना, चक्रवात प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का विकास और जल निकासी प्रणालियों में सुधार शामिल हैं। सत्र में सामुदायिक भागीदारी, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्वयंसेवकों को संगठित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात केंद्र की स्थापना, आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करने पर जोर दिया गया।

6.12 उत्तर प्रदेश अग्नि एवं सुरक्षा एक्सपो एवं सम्मेलन (यूपीएसईसी) का तीसरा संस्करण 5 जुलाई 2024, उत्तर प्रदेश

तीसरा उत्तर प्रदेश अग्नि एवं सुरक्षा एक्सपो एवं सम्मेलन (यूपीएसईसी) 2024 ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) और अन्य हितधारकों के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा पर सत्र आयोजित किए गए। एनआईडीएम में ईसीडीआरएम के प्रमुख प्रो. अनिल कुमार गुप्ता द्वारा संचालित एक सत्र में जोखिम, समुत्थानशीलता और सुरक्षा ऑडिट को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पैनलिस्टों ने अग्नि सुरक्षा के बुनियादी ढांचे और तैयारियों को बढ़ाने के लिए सरकारी निकायों और उद्योगों के बीच सहयोग पर चर्चा की। सम्मेलन का समापन अग्नि सुरक्षा और आपदा तैयारी सुनिश्चित करने में सामूहिक प्रयासों की भूमिका पर जोर देने के साथ हुआ।

6.13 हाईकैप परियोजना के लिए असुरक्षा आकलन ढाँचे के मापदंडों पर चर्चा हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटीआर, आईआईटीआई, आईआईटीकेजीपी, डीटीयू) के कंसोर्टियम भागीदारों के साथ ऑनलाइन कार्यशाला, 10 जुलाई 2024

एनआईडीएम ने एक शोध परियोजना शुरू की है, जिसमें भूस्खलन, भारी वर्षा और बाढ़, भूकंप, चक्रवात, अत्यधिक तापमान आदि जैसे खतरों के प्रति संवेदनशील राष्ट्रीय राजमार्गो का अध्ययन शामिल है ताकि एक जलवायु अनुकूलन नीति विकसित की जा सके और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के बुनियादी ढाँचे को जलवायु के प्रति समुत्थानशील बनाने के लिए मौजूदा डिजाइनों, संहिताओं और दिशा-निर्देशों को उन्नत करने हेतु सिफारिशें की जा सकें। इस परियोजना का शीर्षक ''राष्ट्रीय राजमार्ग अनुकूलन नीति और दिशा-निर्देशों का विकास'' (हाईकैप) है और यह शोध कंसोर्टियम मोड में किया जा रहा है। इस संबंध में असुरक्षा आकलन ढाँचे (वीएएफ) के मापदंडों पर चर्चा के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान, वीएएफ के डोमेन और उप-डोमेन पर चर्चा की गई और तीन डोमेनरू भौतिक, सामाजिक और प्रणालीगत के अंतर्गत मापदंडों का अध्ययन करने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला में एनआईडीएम की उच्च सीएपी टीम, कंसोर्टियम के प्रमुख अन्वेषक और सह-प्रमुख अन्वेषक-आईआईटी (रुड़की), आईआईटी (इंदौर), आईआईटी (खड़गपुर) और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भाग लिया।

6.14 जीआई (भौगोलिक संकेतक) उत्प्रेरक: इनसाइट टू इम्पैक्ट समिट,12 जुलाई 2024,

इस समिट में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें डॉ. काजल, सुश्री हिमानी पांडे, श्री राजेन्द्र रत्नू, भा.प्र.से (कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम), श्री अमित कपूर, श्री अनूप वधावन, और श्री राजेश कुमार सिंह शामिल थे। श्री राजेन्द्र रत्नू ने उद्घाटन भाषण देते हुए जीआई उत्पादों के उत्पादकों एवं निर्माताओं की आय बढ़ाने पर बल दिया।

6.15 समग्र कार्य योजना की समीक्षा बैठक 'राष्ट्रीय राजमार्ग जलवायु अनुकूलन नीति एवं दिशा-निर्देश' (हाईकैप) परियोजना, 23 जुलाई 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) की हाईकैप परियोजना की केंद्रीय टीम की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें कंसोर्टियम भागीदारों के साथ समग्र कार्य योजना की समीक्षा की गई।

बैठक में एनआईडीएम की हाईकैप टीम, साथ ही प्रमुख अन्वेषक और सह-अन्वेषक आईआईटी (रुड़की), आईआईटी (इंदौर), आईआईटी (खड़गपुर), और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पहचान किए

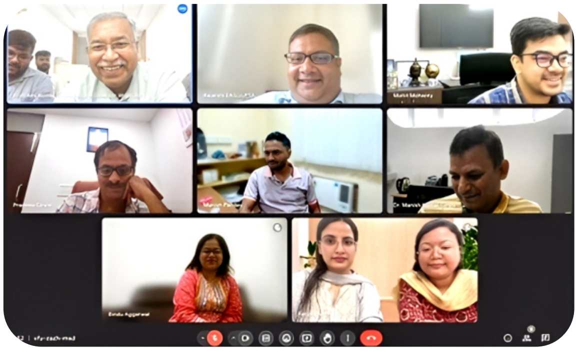

गए 2000 किलोमीटर के खंड के भीतर महत्वपूर्ण अध्ययन स्थलों को चिन्हित करने पर चर्चा की गई, ताकि उन स्थलों पर डेटा संग्रहण किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि:

पर्वतीय क्षेत्रों में 5 किलोमीटर का खंड, और मैदानी क्षेत्रों में 10 किलोमीटर का खंड प्रमुख अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त, आईआईटी रुड़की से अनुरोध किया गया कि वे इन खंडों से संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि पूर्व में घटित आपदाओं की जानकारी साझा करें, ताकि अध्ययन को अधिक तथ्यात्मक और सटीक बनाया जा सके। यह बैठक परियोजना की रणनीतिक प्रगति और क्षेत्रीय अनुकूलन के दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम रही।

6.16 तनाव प्रबंधन पर संवेदीकरण कार्यक्रम, 26 जुलाई 2024, दिल्ली

एनआईडीएम ने ''तनाव प्रबंधन'' पर एक संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व प्रशिक्षक एवं पैथोलॉजिस्ट डॉ. विनीत बंगा ने किया। यह सत्र श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया और इसमें श्री सुरेंद्र ठाकुर (जेडी, एनआईडी, दिल्ली), कर्नल पी.एस. रेड्डी (जेडी, एनआईडीएम साउथ कैंपस) और प्रो. सूर्य प्रकाश (प्रमुख, जीएमआरडी) सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से.), ईडी, एनआईडीएम ने तनाव और अवसाद के प्रमुख कारणों, जैसे पालन-पोषण की शैली, निर्भरता और जीवनशैली प्रबंधन के महत्व पर चर्चा की। डॉ. बंगा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तनाव अपरिहार्य है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। उन्होंने तनाव के लक्षणों, उससे निपटने की रणनीतियों और स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों पर चर्चा की। यह सत्र एक स्वस्थ, तनाव-मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

6.17 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) पर शहरों को सक्षम बनाने पर द्वितीय हितधारक परामर्श, 26 जुलाई 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और डॉयचे गेसेलशाफ्ट फ्यूर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बीट (जीआईजेड इंडिया) ने ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (सीसीए) पर शहरों के सशक्तिकरण'' पर अपने दूसरे हितधारक परामर्श का आयोजन किया। सतत् शहरी विकास स्मार्ट सिटीज ।। (एसयूडीएससी-।।) पहल के एक भाग के रूप में, इस कार्यक्रम ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास के रूप में एनआईडीएम-जीआईजेड

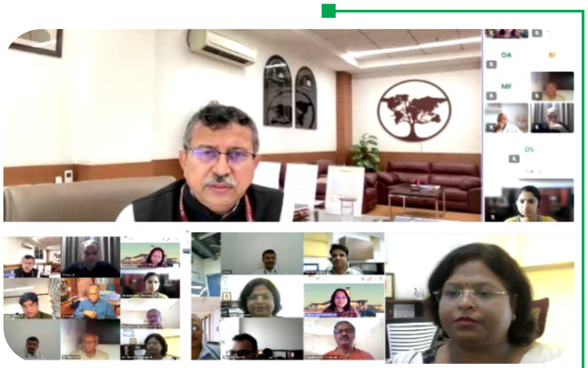

अनुदान समझौते के तहत चल रहे शोध की प्रगति और निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम ने ''जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण'' और असम में बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए बढ़ी हुई धनराशि जैसे नए प्रावधानों पर प्रकाश डाला। श्री किरण राजशेखरैया (तकनीकी सलाहकार) ने स्वागत भाषण दिया और एनआईडीएम की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. गरिमा अग्रवाल ने चर्चा की रूपरेखा तैयार की। कार्यक्रम में डॉ. रानित चटर्जी, डॉ. हरि कुमार और श्री विवेकानंद गुप्ता ने प्रस्तुतियाँ दीं, जिन्होंने अपने शोध के बारे में नवीनतम जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम में हितधारकों और विशेषज्ञों सहित लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, इस सत्र में बहुमूल्य विचारों और विशेषज्ञ सलाह के आदान-प्रदान का अवसर मिला। सुश्री तोरा सैकिया ने कुशलतापूर्वक इस कार्यक्रम का संचालन किया।

6.18 सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान (सीएसटीआई) सम्मेलन-2024, 12 अगस्त 2024, दिल्ली

क्षमता निर्माण आयोग ने राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (एनएससीएसटीआई) के तहत मान्यता प्राप्त सभी सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों (सीएसटीआई) को एक साथ लाने के उद्देश्य से विज्ञान भवन में सीएसटीआई सम्मेलन 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में, मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 144 मान्यता प्राप्त सीएसटीआई को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जो सिविल सेवा क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त सीएसटीआई और उनके सम्मानित सहयोगियों को हार्दिक बधाई दी। सम्मेलन के दौरान, माननीय राज्य मंत्री ने तीन महत्वपूर्ण पहलों का भी शुभारंभ किया: संकाय विकास कार्यक्रम, अमृत ज्ञान कोष और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, जो सीएसटीआई के बीच निरंतर सीखने और योग्यता-संचालित क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।

6.19 18वां भारतीय प्रेस संस्थान-अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (पीआईआई-आईसीआरसी) वार्षिक पुरस्कार, 30 अगस्त 2024, दिल्ली

श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, सुश्री नाजिया खान, आईपीआरओ, एनआईडीएम के साथ, नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित प्रतिष्ठित 18वें भारतीय प्रेस संस्थान - रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (पीआईआई-आईसीआरसी) वार्षिक पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह समारोह भारतीय प्रेस संस्थान और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मानवीय पत्रकारिता की मजबूती और प्रतिभा का जश्न मनाया गया। केदिर अवोल उमर और शशि नायर जैसे प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर उपस्थित रहे। पीआईआई-आईसीआरसी पुरस्कारों ने एक प्रकाश स्तंभ की तरह

काम किया और महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों को उठाने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन और उत्तराखंड एवं सिक्किम में प्राकृतिक आपदाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया। पुरस्कार समारोह में उत्कृष्ट पत्रकार और फोटोग्राफर शामिल थे। फोटोग्राफरों में शाहिद जज (स्क्रॉल.इन), अवंतिका भुइयां (मिंट लाउंज), पद्मजा जे (द टाइम्स ऑफ इंडिया, अजीश टी (मलयाला मनोरमा), मिथुन अनिला मिथ्रान (देशाभिमानी), अरुण कृष्णनकुट्टी (मातृभूमि), मुरली कृष्णन (मातृभूमि), और शांत कुमार (द टाइम्स ऑफ इंडिया) इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

6.20 आईयूआईएनडीआरआर-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और श्री श्री विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन, 10 सितंबर 2024, कर्नाटक

श्री श्री विश्वविद्यालय और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों का नेटवर्क-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (आईयूआईएनडीआरआर-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान) ने 10 सितंबर, 2024 को आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु में पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की उपस्थिति में एक मजबूत भारत के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग ने आपदाओं के प्रति भारत की समुत्थानशीलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से) और माननीय अध्यक्ष, प्रो. श्रीमती रजिता कुलकर्णी, माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) तेज प्रताप द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य आध्यात्मिकता, जागरूकता और आपदा जोखिम प्रबंधन की शक्ति का सम्मिश्रण करना है ताकि संकट के समय में राष्ट्र को बेहतर ढंग से तैयार किया जा सके और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक शक्ति की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस साझेदारी का उद्देश्य समुदायों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना शालीनता और मजबूती के साथ करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है।

6.21 श्री सुरेन्द्र ठाकुर को विदाई: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में नेतृत्व और सेवा का सम्मान, 11 सितंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के संयुक्त निदेशक श्री सुरेन्द्र ठाकुर के प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के समापन के उपलक्ष्य में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एनआईडीएम में उनके कार्यकाल के दौरान उनके अमूल्य योगदान और नेतृत्व के सम्मान में आयोजित किया गया। वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उनके समर्पण के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए। श्री ठाकुर को सम्मान स्वरूप एक गुलदस्ता और एक स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। कार्यक्रम का समापन श्री ठाकुर के भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाओं और संस्थान के प्रति उनकी सेवाओं को याद करने के साथ हुआ। कर्नल पलागानी श्रीनिवासुलु रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, दक्षिणी परिसर को एनआईडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

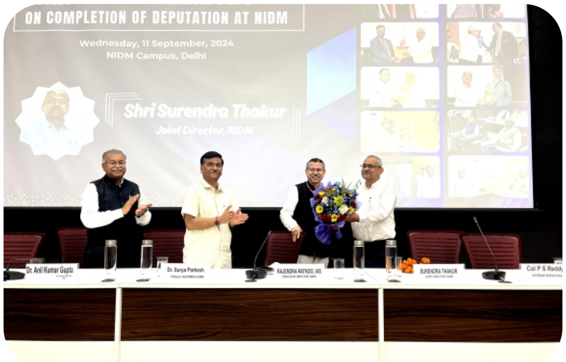

6.22 प्रभावी टीम वर्क के लिए नेतृत्व कौशल विकसित करने पर संवेदीकरण कार्यक्रम, 26 सितंबर 2024, दिल्ली

एनआईडीएम ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के प्रोफेसर एम. वेंकटेशन की सहायता से 'प्रभावी टीमवर्क के लिए नेतृत्व कौशल का विकास' विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एनआईडीएम दिल्ली परिसर में किया। कार्यक्रम में श्री राजेंद्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम, सुश्री नाजिया खान, आईपीआरओ, एनआईडीएम और एनआईडीएम के अन्य सभी संकाय सदस्यों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस सत्र में इंटरैक्टिव टीमवर्क गतिविधियों के माध्यम से नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रभावी टीमों का नेतृत्व करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ प्रदान की गईं। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने इस अवसर पर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और प्रकृति संरक्षण और मानव कल्याण के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर बल दिया। कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक., एनआईडीएम द्वारा समापन भाषण दिया गया और इसी के साथ नेतृत्व और टीम वर्क पर केंद्रित एक व्यावहारिक और उत्पादक सत्र का समापन हुआ।

6.23 एनआईडीएम ने दी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता को विदाई, आईआईटी रुड़की में करेंगे नए अध्याय की शुरुआत, 27 सितंबर 2024, दिल्ली

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने हाल ही में आईआईटी रुड़की में एक नई यात्रा शुरू की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) में एक समृद्ध विरासत छोड़ी है, जहाँ उन्होंने पर्यावरण आपदा जोखिम प्रबंधन प्रभाग (ईडीआरएम) के प्रोफेसर और प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनका काम केवल जोखिमों का प्रबंधन करना ही नहीं थाय बल्कि यह पुनर्कल्पना करना भी था कि समाज जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों का सामना कैसे कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और सतत् विकास में विशेषज्ञता के अनूठे मिश्रण के साथ, डॉ. गुप्ता ने लोगों की विकास आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए, कमजोरियों को कम करने के लिए लगातार नए तरीके खोजे। डॉ. गुप्ता ने जलवायु समुत्थानशीलता और विकास योजना के बीच की खाई को पाटने के लिए अथक प्रयास किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों साथ-साथ चलें। इन जटिल मुद्दों को एक साथ जोड़कर स्पष्ट, कार्यान्वियन योग्य रणनीतियाँ प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता ने उन्हें इस क्षेत्र में एक मार्गदर्शक शक्ति बना दिया। उनका जुनून और परिणामों पर उनकी पैनी नजर काफी प्रभावशाली थी, जिसने उनकी टीम और परियोजनाओं को सफलता की ओर अग्रसर किया। अब, जब वे आईआईटी रुड़की में नई

चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो दूरदर्शी समाधानों की उनकी विरासत और इस क्षेत्र पर उनका प्रभाव उन लोगों को प्रेरित करता रहेगा जिनके साथ उन्होंने काम किया और जिन परियोजनाओं को उन्होंने आकार दिया।

6.24 पारिस्थितिकी–संवेदनशील तटीय बस्तियों की योजना हेतु तकनीकी–पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर सम्मेलन– 2024, 27 सितंबर 2024, आंध्र प्रदेश

पारिस्थितिकी–संवेदनशील तटीय बस्तियों की योजना हेतु तकनीकी–पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर 2024 सम्मेलन में सतत तटीय विकास के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के एकीकरण पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम में स्वदेशी वास्तुकला और सिविल इंजीनियरिंग प्रथाओं का लाभ उठाने के महत्व पर चर्चा की गई, जो प्राकृतिक लचीलेपन और पारिस्थितिक सामंजस्य को प्राथमिकता देती हैं, जैसे स्थानीय सामग्रियों और स्थानीय निर्माण तकनीकों और जल संचयन तकनीकों का उपयोग। विशेषज्ञों ने बेहतर आपदा तैयारी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पारंपरिक तटीय प्रबंधन प्रणालियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीक के साथ मिलाने वाले एक संकर दृष्टिकोण की वकालत की। सम्मेलन में लचीली और पारिस्थितिकी–संवेदनशील तटीय बस्तियों के निर्माण में सामुदायिक भागीदारी, जलवायु अनुकूलन और ज्ञान–साझाकरण को महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में रेखांकित किया गया। सम्मेलन में 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.25 स्वच्छता पखवाड़ा 02 अक्टूबर 2024, दिल्ली

एनआईडीएम रोहिणी परिसर, दिल्ली और दक्षिणी परिसर, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश ने गर्व के साथ स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, एक ऐसी पहल जिसने स्वच्छता और सफाई के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। एनआईडीएम का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों और पहलों के माध्यम से एक स्वच्छ और हरित वातावरण को बढ़ावा देना और एक स्वस्थ भविष्य के लिए स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। आइए, हम सब मिलकर एक स्वच्छ वातावरण बनाए रखें और स्वच्छ भारत की दिशा में काम करें!

6.26 सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर संवेदीकरण कार्यक्रम, 28 अक्टूबर– 03 नवंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने अपने रोहिणी परिसर, दिल्ली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। इस सत्र का नेतृत्व श्री अभय सिंह, निदेशक (सी एंड पी), मुख्यालय, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने किया, जिसमें श्री राजेन्द्र रत्नू (भा.प्र. से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएमय डॉ. सूर्य प्रकाश (प्रोफेसर, एनआईडीएम); श्री शेखर चतुर्वेदी (सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम); और श्री शिव नारायण सिद्ध (सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम) शामिल हुए। प्रतिभागियों ने अपने कर्तव्यों के प्रति

ईमानदारी और प्रतिबद्धता बनाए रखने की शपथ ली और एक सतर्क एवं नैतिक कार्य वातावरण के प्रति एनआईडीएम के समर्पण को सुदृढ़ किया।

6.27 भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम–क्योटो भूस्खलन प्रतिबद्धता (आईसीएल–केएलसी) 2024 सम्मेलन, 04 नवंबर 2024, जापान

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भूस्खलन पर अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम (आईसीएल) का एक सदस्य संगठन है और इसे भूस्खलन आपदा न्यूनीकरण पर विश्व उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश को आईसीएल के बोर्ड सदस्य और 2024 आईसीएल केएलसी सम्मेलन के लिए एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। आईसीएल और क्योटो भूस्खलन प्रतिबद्धता के महासचिव प्रोफेसर क्योजी सासा ने उन्हें आमंत्रित किया था। एनआईडीएम के अलावा, विभिन्न अन्य संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को), अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (आईयूजीएस), आपदा जोखिम पर एकीकृत अनुसंधान (आईआरडीआर) आदि ने भी सम्मेलन में भाग लिया। यूनेस्को अध्यक्ष डॉ. मिकोस ने आईसीएल और यूनेस्को आईएचपी की प्रमुख पहल, अंतर्राष्ट्रीय तलछट पहल (आईएसआई) के बीच सहयोग के विषय पर गहन चर्चा की। प्रस्तुतियों और विशेषज्ञों ने आईसीएल परियोजनाओं और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों पर भी चर्चा की गई, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/मशीन लैंग्वेज (एमएल) का उपयोग और भूस्खलन की संवेदनशीलता, खतरा, जोखिम, मलबे का प्रवाह, चट्टान गिरना, स्थलाकृति, भूस्खलन से प्रेरित सुनामी, बहु–खतरा और भूकंप से प्रेरित भूस्खलन, भूस्खलन की पूर्व चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक भागीदारी, सड़क गलियारों में शमन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, मानचित्रण, सहयोग आदि में बेहतर कार्यप्रणाली।

6.28 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली और भारत आपदा संसाधन नेटवर्क पर सत्र का आयोजन, 07–08 नवंबर 2024, महाराष्ट्र

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईआरडीएन) गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा भारत सरकार–यूएनडीपी आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) कार्यक्रम के अंतर्गत आपातकालीन प्रतिक्रिया हेतु उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और महत्वपूर्ण आपूर्तियों की सूची के प्रबंधन हेतु शुरू किया गया एक वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य निर्णयकर्ताओं को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए उपकरणों और मानव संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना और प्रतिभागियों को यह समझने में सहायता करना था कि आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों, कुशल कर्मियों और महत्वपूर्ण आपूर्तियों की सूची का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे किया जाए। यह न केवल सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, बल्कि आपदा प्रतिक्रिया के दौरान समन्वय को भी बढ़ाता है। इस सत्र में कुल 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.29 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 14-27 नवंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने 14-27 नवंबर 2024 के बीच भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में अपने प्रकाशनों की प्रदर्शनी प्रस्तुत की। यह मंडप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। आईआईटीएफ में वैश्विक व्यापार और नवाचार में भारत के गतिशील विकास को प्रदर्शित किया गया। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा किया गया था और इसका विषय 'विकसित भारत/2047' था। इस मेले ने अत्याधुनिक नवाचारों, क्षेत्रीय विशिष्टताओं और वैश्विक व्यावसायिक संबंधों को जानने का अवसर प्रदान किया। यह वार्षिक प्रदर्शनी भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उद्योगों के उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। प्रदर्शनी के दौरान, एनआईडीएम ने अपने कई प्रकाशनों का प्रदर्शित किया, जिसमें प्रशिक्षण मॉड्यूल, केस स्टडी रिपोर्ट, कार्यवाही, आईईसी सामग्री (क्या करें और क्या न करें), ब्रेल लिपि में क्या करें और क्या न करें आदि शामिल थी। एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में बच्चों के बीच पहेलियाँ/क्रॉसवर्ड हल करना, ड्राइंग और स्केचिंग जैसे खेलों की नवीन अवधारणाएँ भी प्रस्तुत की। डीआरआर के लिए खेलों को शुरू करने का उद्देश्य उनकी समझ को बढ़ाना और आपदा तैयारी और उसके शमन उपायों के बारे में बच्चों और वयस्कों को जागरूक करना था।

6.30 'टिप्पणियाँ और प्रारूपण' पर गैर-डोमेन प्रशिक्षण सत्र, 29 नवंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 'टिप्पणियाँ और प्रारूपण' पर एक गैर-डोमेन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस सत्र का नेतृत्व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के निदेशक (परियोजना मौसम) डॉ. अजीत कुमार ने किया, जिन्होंने कार्यालय प्रक्रिया नियमावली और ई-ऑफिस के महत्व पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इस सत्र में आधिकारिक पत्राचार में स्पष्ट और संक्षिप्त संचार के महत्व पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को प्रशासनिक और प्रभावी नोटिंग बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

6.31 प्रथम पूर्व-शिखर सम्मेलन 'आपदा प्रबंधन पर विश्व शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएम)' का उद्घाटन, 17 दिसंबर 2024, दिल्ली

श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर प्रथम पूर्व-शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसडीएम) का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 'हिमालयी क्षेत्र में जलवायु समुत्थानशीलता और आपदा प्रबंधन' विषय पर केंद्रित था। यह कार्यक्रम आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु समुत्थानशीलता पर चर्चाओं और नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन

प्राधिकरण (यूएसडीएमए), उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूसीओएसटी) और आपदा प्रबंधन पहल एवं कन्वर्जेंस सोसाइटी (डीएमआईसीएस) द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन-पूर्व पहल ने देहरादून में मुख्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (डब्ल्यूएसडीएम) के समक्ष आने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रयास की शुरुआत की।

6.32 'राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष' पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम, 13 जनवरी 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शमन कोष के अंतर्गत परियोजनाओं के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्घाटन एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से) ने किया, जिन्होंने संरचित आपदा वित्तपोषण और क्षमता निर्माण के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र का नेतृत्व एनडीएमए के सदस्य श्री कृष्ण एस. वत्स ने किया, जिन्होंने भारत में एक विविध और विश्वसनीय आपदा जोखिम वित्तपोषण (डीआरएफ) प्रणाली के निर्माण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने 15वें वित्त आयोग द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण सुधारों, जैसे संशोधित आवंटन सूत्र, नई वित्त पोषण विंडो, और बेहतर पूर्वानुमान और पारदर्शिता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आगे प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिनमें सीमित बीमा पहुँच, निधियों का कम उपयोग और जिला-स्तरीय निधियों की गैर-संचालन स्थिति शामिल है। इस सत्र में सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें जोखिम सूचकांक, निधि संवितरण और स्तरित निधि संरचनाओं के पीछे के तर्क के बारे में प्रश्न पूछे गए, जिससे प्रतिभागियों के लिए व्यापक शिक्षण अनुभव की प्राप्ति हुई।

6.33 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का 150वाँ वर्षगांठ समारोह 14 जनवरी 2025, दिल्ली

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 जनवरी, 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की महासचिव प्रोफेसर सेलेस्टे साउलो के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एनआईडीएम की आपदा सुरक्षा में योगदान करने वाली पहलों के बारे में उन्हें जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की अध्यक्षता में आयोजित तीसरे पैनल चर्चा में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए मौसम और जलवायु सेवाओं' की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। इस सत्र में आपदा के प्रभावों को कम करने और जीवन की सुरक्षा में पूर्व चेतावनी प्रणालियों की शक्ति पर जोर दिया गया।

6.34 'अनुवादिनी की विशेषताएँ और संचालन' पर जागरूकता, 30 जनवरी 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 'अनुवादिनी की विशेषताएँ और संचालन' पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। अनुवादिनी एक उन्नत एआई अनुवाद उपकरण है जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा विकसित किया गया है।

इस सत्र का नेतृत्व मुख्य अतिथि डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर, मुख्य समन्वय अधिकारी, एआईसीटीई और अनुवादिनी फाउंडेशन के सीईओ ने किया। उनके साथ अनुवादिनी फाउंडेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बालाजी अरथिला भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, प्रमुख, जीएमआरडी, एनआईडीएम; कर्नल पी. एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम और श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम भी शामिल हुए। इसका समन्वयन एस.के. तिवारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, एनआईडीएम, सुप्रीता एमके, परामर्शदाता, प्रकाशन, एनआईडीएम ने किया। इस सत्र में अनुवादिनी उपकरण के महत्व पर जोर दिया गया, जो भाषा अनुवाद और संचार की प्रक्रिया को बेहतर और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉ. बुद्ध चंद्रशेखर ने इस उपकरण की अनुवाद क्षमताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भाषाओं से जुड़ने और सहजता से वैश्विक संचार करने में सक्षम बना सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यह उपकरण न केवल भाषा अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि भाषा संबंधी बाधाओं को तोड़कर और अंतर-सांस्कृतिक संवाद को सुगम बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संचार पर एआई के सकारात्मक प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है।

6.35 'प्रभावी संचार कौशल' पर जागरूकता, 31 जनवरी 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने 'प्रभावी संचार कौशल' पर एक विचारोत्तेजक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि मानसिक स्वास्थ्य संचार को कैसे प्रभावित करता है और दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विशेषज्ञ डॉ. वंदना गंभीर (सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय) ने किया। इस कार्यक्रम की शोभा श्री राजेंद्र रत्नू भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएमय कर्नल पी.

एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएमय श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम और सुश्री नाजिया खान, आईपीआरओ, एनआईडीएम ने बढ़ाई। इस सत्र में प्रभावी संवाद के माध्यम से संचार बाधाओं को दूर करने, स्पष्टता बढ़ाने और प्रभावी संवाद के माध्यम से सुरक्षा सृजन पर जोर दिया गया। एनआईडीएम के संकाय और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए और पेशेवर एवं व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी संचार रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए एक संवादात्मक चर्चा में भाग लिया।

6.36 'सीबीआरएन सम्मेलनः भविष्य की सुरक्षा', 01 फरवरी 2025, दिल्ली

श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 'सीबीआरएन सम्मेलनः भविष्य की सुरक्षा' में विशेष अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में सम्मिलित हुए।

यह शिखर सम्मेलन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जहाँ उन्होंने रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) खतरों के विरुद्ध समुत्थानशीलता और तैयारी को मजबूत करने और इन जटिल आपात स्थितियों के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से सहयोग करने के तरीकों पर गुणात्मक चर्चा की।

श्री रत्नू ने जोखिमों को कम करने और समुदायों की सुरक्षा के लिए सक्रिय रणनीतियों, क्षमता निर्माण और बहु-एजेंसी समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बहुमूल्य अंतदृष्टि प्रदान की, जिसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आगे बढ़ाने और उभरती हुई सीबीआरएन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एनआईडीएम की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

6.37 'कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल और सचेत सिस्टम' पर जागरूकता 07 फरवरी 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एनआईडीएम परिसर में 'कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल (कैप) और सचेत सिस्टम' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस सत्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के वरिष्ठ सलाहकार (संचार) कर्नल अनुज दयाल माथुर (सेवानिवृत्त) ने कैप और सचेत सिस्टम के बारे में गहन जानकारी प्रदान की और आपदा संचार में उनके महत्व पर प्रकाश डाला। श्री सुमित कुमार झा, टीम लीडर, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट) ने अलर्ट तंत्र को बेहतर बनाने में सी-डॉट के योगदान पर विस्तार से बताया। इस कार्यशाला में संकाय और अन्य कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और चर्चाओं में भाग लिया, जिससे आपदा संचार और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। यह कार्यशाला अत्यधिक जानकारीयुक्त और प्रभावशाली साबित हुई, जिसने प्रतिभागियों को अलर्ट प्रोटोकॉल और संचार तकनीकों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया, जो प्रभावी आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक हैं।

6.38 कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 16 फरवरी 2025, उत्तर प्रदेश

श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने प्रयागराज में पर्यावरण, स्थिरता और प्रौद्योगिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच (आईफॉरेस्ट) द्वारा आयोजित कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। उनकी अंतदृष्टि ने आस्था, संस्कृति और जलवायु कार्रवाई के बीच गहरे संबंध को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी और समावेशी पर्यावरणीय समाधानों को प्रेरित कर सकता है। सम्मेलन में धार्मिक नेताओं और आस्था-आधारित संगठनों की भूमिका को एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य के रूप में जलवायु कार्रवाई को प्रेरित करने में रेखांकित किया गया। प्रतिभागियों ने इन प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प लिया और स्थिरता, एकता और आध्यात्मिक उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। महाकुंभ घोषणा ने नीति निर्माताओं, नागरिक समाज, वैज्ञानिकों और व्यक्तियों से भावी पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिकता को स्थिरता के साथ एकीकृत करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया।

6.39 'समुत्थानशील समुदाय, मजबूत राष्ट्रः आपदा प्रबंधन में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोगात्मक दृष्टिकोण' पर गोलमेज सम्मेलन, 07 मार्च 2025, दिल्ली

श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम, ने श्री संजीव कुमार जिंदल, अतिरिक्त सचिव, आपदा प्रबंधन, भारत सरकार के साथ 'समुत्थानशील समुदाय, मजबूत राष्ट्रः आपदा प्रबंधन में भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोगात्मक दृष्टिकोण' पर गोलमेज चर्चा में भाग लिया, जो मर्रे हैरिस हॉल, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

यह चर्चा नीति निर्धारकों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों और विचारशील नेताओं को भारत और ऑस्ट्रेलिया से एकत्रित करने का एक अवसर था, जहाँ उन्होंने आपदा सुरक्षा में समन्वित और स्केलेबल रणनीतियों का अन्वेषण किया, जो शासन, प्रौद्योगिकी और समुदाय-प्रेरित पहलों पर केंद्रित थीं। भारत-ऑस्ट्रेलिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस के माध्यम से, दोनों राष्ट्र अनुसंधान, नीति विकास और कार्यान्वयन में अपने सहयोग को नया आयाम दे रहे हैं, ताकि एक सुरक्षित और समुत्थानशील भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

6.40 'पर्यावरण और आध्यात्मिक समुत्थानशीलता को मजबूत करने' पर कान्हा शांति वनम द्वारा ध्यान सत्र का आयोजन, 11 मार्च 2025, दिल्ली

कान्हा शांति वनम के एक प्रतिनिधिमंडल ने रोहिणी परिसर के लिए हरित पहलों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का दौरा किया। सत्र का नेतृत्व श्री वी. रमाकांत, आईएफएस (सेवानिवृत्त), श्री अशोक

भार्गव और श्री सरवनन ने किया। इस कार्यक्रम में औषधीय पौधों, देशी प्रजातियों, खाद्य वनों और हरित दीवारों के साथ वनस्पति आवरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका उद्देश्य वायु की गुणवत्ता में सुधार, तापमान को नियंत्रित करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना था। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से) ने प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया। इस यात्रा में एक इंटरैक्टिव सत्र भी शामिल था, जहाँ एनआईडीएम संकाय ने आध्यात्मिकता, तनाव प्रबंधन और पारिस्थितिक बहाली पर विचार मंथन किया।

6.41 व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 17–28 मार्च 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 'व्यायपक आपदा जोखिम प्रबंधन' विषय पर प्रतिष्ठित आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेलीज देश के प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संस्थागत ढांचे, तैयारी एवं शमन रणनीतियाँ, नीतिगत एवं विधिक प्रावधान, वित्तपोषण तंत्र तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्रीय एकीकरण जैसे विषय शामिल थे।

कार्यक्रम को विशिष्ट विशेषज्ञों की सहभागिता ने और समृद्ध बनाया, जिनमें श्री राजेन्द्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; श्री प्रदीप कुमार जेना (पूर्व मुख्य सचिव, ओडिशा); श्री लॉय रेगो (पूर्व एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (एडीपीसी,) बैंकॉक) और कई अन्य प्रतिष्ठित वक्ता शामिल थे।

शैक्षणिक सत्रों के साथ-साथ प्रतिभागियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का अनुभव भी कराया गया। इसके अंतर्गत ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला और इंडिया गेट जैसी ऐतिहासिक स्थलों की शैक्षणिक यात्रा आयोजित की गई। सांस्कृतिक अनुभव को और भी आकर्षक बनाने के लिए एक जीवंत सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात् डायरेक्टर डिनर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित अभिमन्यु लाल और वर्षा लाल एंसेंबल द्वारा प्रस्तुत मनमोहक कथक नृत्य ने सभी को भारत की कलात्मक परंपरा से अभिभूत कर दिया।

श्री राजेन्द्र रत्नू, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम की अध्यक्षता में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम तथा श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम भी उपस्थित थे। इस प्रकार यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक परिवर्तनकारी शिक्षण यात्रा के सफल समापन का प्रतीक बन गया।

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार (एनआईडीएम दिल्ली परिसर)

6.42 आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, 21–22 अप्रैल 2024, उत्तर प्रदेश।

आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आईआईटी–बीएचयू), वाराणसी के सहयोग से एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में प्रो. अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख, ईसीडीआरएम, एनआईडीएमय प्रो. कल्याण चंदेल, प्रमुख, विस्तार शिक्षा, कृषि विज्ञान, बीएचयू; प्रो. एस.के. शुक्ला, निदेशक, सीयूपी इनक्यूबेशन सेल, बीएचयू; प्रो. सुनील गोयल, आयोजन सचिव, बीएचयू; जे.पी. राय, संयोजक और कृतिका पांडे, युवा पेशेवर, एनआईडीएम उपस्थित थे। प्रमुख हस्तियों ने आज के जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपने विचार साझा किए, ताकि एक समुत्थानशील वातावरण बनाया जा सके, आपदा जोखिम को कम किया जा सके और प्रतिभागियों को समुत्थानशीलता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रतिभागियों ने खतरों और आपदा जोखिमों के बहुपक्षीय क्षेत्र के बारे में सीखा, जिसमें उनके गुण, व्यक्तियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, साथ ही उनके पहचान और पता लगाने के लिए उन्नत विधियाँ शामिल थीं।

इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस वैज्ञानिक नवाचार और प्रौद्योगिकी समाधानों के संयोजन पर था, जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप से जीवन, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार ने जोखिम मूल्यांकन विधियों की व्यापक जांच की, जिससे उपस्थित लोगों को आपदा जोखिमों और घटनाओं के संभावित परिणामों का विश्लेषण करने के उपकरण प्राप्त हुए और प्रभावी जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को तैयार करने का अवसर मिला। इस सेमिनार में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के निदेशक, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य शिक्षक शामिल थे।

6.43 'ग्रह बनाम प्लास्टिक' पृथ्वी दिवस कार्यक्रम, 22 अप्रैल 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), दिल्ली और भारतीय भू-वैज्ञानिक सोसायटी (जीएसआई), बैंगलोर ने "ग्रह बनाम प्लास्टिक" विषय पर केंद्रित एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दिल्ली भर के विभिन्न विभागों और शैक्षणिक संस्थानों के सम्मानित अतिथि प्लास्टिक प्रदूषण के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने और स्थायी समाधानों की वकालत करने के लिए एकत्रित हुए। एनआईडीएम के प्रोफेसर सूर्य प्रकाश ने पृथ्वी दिवस की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और प्रकृति संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। प्रोफेसर हर्ष गुप्ता ने भूकंप प्रतिरोधक क्षमता पर जोर दिया, जबकि श्री

राजेंद्र रत्नू ने तमिलनाडु में '6 E's' मॉडल का उपयोग करते हुए सफल एंटी-प्लास्टिक अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की: परीक्षण (Experimental), मूल्यांकन (Evaluation), शिक्षा (Education), उन्मूलन (Eradication), सशक्तिकरण (Empowerment) और प्रवर्तन (Enforcement)। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने सतत् अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के महत्व पर बल दिया। पद्मश्री प्रो. हर्ष गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय भू-वैज्ञानिक सोसायटी, बैंगलोर ने नागरिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत में भूकंप दिवस मनाने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के कुलपति प्रो. प्रतीक शर्मा ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और समुदायों को सार्थक बदलाव लाने के लिए सशक्त बनाने में मानवीय गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में प्लास्टिक उत्पादन से संबंधित चौंकाने वाले आंकड़ों पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने दैनिक जीवन में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और खपत को कम करने के महत्व पर बल दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के प्रो. आर. भास्कर ने महासागरों में सूक्ष्म प्लास्टिक के गंभीर मुद्दे और समुद्री जीवन पर उनके व्यापक प्रभाव पर गहन चर्चा की। इसके अलावा, प्लास्टिक-मुक्त पहलों की सफलता की कहानियों पर चर्चा की गई और कार्यक्रम में जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का समापन केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के एक संवाद सत्र के साथ हुआ। पृथ्वी दिवस कार्यक्रम ने प्लास्टिक मुक्त भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की और सभी हितधारकों से आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा में एकजुट होने का आग्रह किया।

6.44 'जलवायु प्रभाव: जलवायु और स्थिरता' पर सम्मेलन, 30 अप्रैल 2024, दिल्ली

श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने दिल्ली विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. विकास गुप्ता ने किया। कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय के समर्पण को रेखांकित किया। आईयूआईएनडीआरआर की वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार डॉ. प्रीति सोनी ने सभी प्रतिभागियों, वक्ताओं और आयोजकों के अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

6.45 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण में संस्थानों की भूमिकाः अनुसंधान और व्यवहार पर अंत-दृष्टि' पर कार्यशाला, 03 मई 2024, दिल्ली

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों एवं सस्थानों का नेटवर्क-एनआईडीएम और ईसीडीआरएम प्रभाग ने दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन के बाद पहला कार्यक्रम था। दयाल सिंह कॉलेज के प्राचार्य प्रो. वी.के. पालीवाल ने सेमिनार का उद्घाटन किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डाला जो संस्थान डीआरआर में निभा सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम थे, जिन्होंने मुख्य भाषण दिया। प्रो. अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख, ईसीडीआरएम प्रभाग ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में उभरते रुझानों पर अपनी विशेषज्ञता और नवोन्मेषी विचार साझा किए। अतिथि वक्ताओं में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पर्यावरण विज्ञान संकाय के प्रो. पी. के. जोशी, दिल्ली विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के डॉ. पंकज कुमार और आईजीयू के सहायक सचिव और डॉ. रवींद्र नाथ तिवारी, सीटीओ, नेत्र भू-सूचना विज्ञान, प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईजीएमटी) फाउंडेशन, नई दिल्ली शामिल थे। प्रो. पी. के. जोशी ने आपदा अध्ययन में जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) की भूमिका पर प्रकाश डाला और आपदा प्रबंधन में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी प्रदान की। डॉ. पंकज कुमार ने हिमालय में ग्लेशियल झील विस्फोट से आने वाले बाढ़ (जीएलओएफ) के एक केस स्टडी के माध्यम से आपदा अध्ययन में जीआईएस के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी साझा की।

डॉ. सुषमा गुलेरिया, सहायक प्रोफेसर, ईसीडीआरएम, एनआईडीएम ने आपदा प्रबंधकों के रूप में परिप्रेक्ष्य पर अपनी विशेषज्ञता साझा की और आपदा प्रबंधन में नेतृत्व की भूमिकाओं पर बहुमूल्य अंतदृष्टि प्रदान की। डॉ. प्रीति सोनी, वरिष्ठ कार्यक्रम सलाहकार, आईयूआईएनडीआरआर- एनआईडीएम ने आपदा अध्ययन कार्यक्रम और आपदा प्रबंधन में करियर के बारे में बहुमूल्य अंतदृष्टि साझा की और डीआरआर क्षेत्र में आपदा समुत्थानशीलता और करियर के अवसरों को बढ़ावा देने में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया। डॉ. रवींद्र नाथ तिवारी ने ड्रोन प्रौद्योगिकी और बदलते अनुसंधान आयाम पर एक सूचनात्मक सत्र का नेतृत्व किया और आपदा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

6.46 'शहरी समुत्थानशीलता' पर हितधारक परामर्श, 21 मई 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने एक हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता डॉ. शैलेश कुमार अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक, भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) ने की और सह-अध्यक्षता श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम ने की। कार्यशाला का उद्देश्य जीआईजेड के अनुदान समझौते के तहत एनआईडीएम द्वारा किए जा रहे शोध अध्ययनों की कार्यप्रणाली, प्रक्रियाओं और निष्कर्षों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह परियोजना सतत् शहरी विकास स्मार्ट सिटीज II (एसयूडीएससीआईआई) की एक उप-परियोजना है, जिसे जीआईजेड (ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनार्बेट) और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

एनआईडीएम की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. गरिमा अग्रवाल ने कार्यशाला का संचालन किया। चर्चाओं में तेजी से हो रहे विकास और बदलती जलवायु परिस्थितियों और शहरी क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए ढाँचों, नीतियों और रणनीतियों के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में मापदंड, कौशल और गति के संदर्भ में शहरी समुत्थानशीलता के उपायों की व्यावहारिकता और महत्व पर चिंताओं को शामिल किया गया। लगभग 40 संबंधित हितधारकों, विषय विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने कार्यशाला में भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।

6.47 आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, 27-28 मई 2024,

मेघालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एनईएसएसी), अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से 'आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी' पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। एनआरएससी के निदेशक, डॉ. प्रकाश चौहान ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। एनईएसएसी पूर्वोत्तर भारत में आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह बाढ़ की चेतावनी, जंगल की आग की चेतावनी, भूस्खलन सूची और यूएवी मानचित्रण प्रदान करता है। कार्यशालाओं में खतरों की परस्पर क्रिया, एनडीईएम और स्मार्ट एक्सोम जैसी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और भू-खतरों के प्रभावों का पता लगाया जाता है। उत्तर पूर्वी स्थानिक डेटा रिपोजिटरी (एनईएसडीआर) और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय नोड (एनईआर-डीआरआर) डेटाबेस व्यापक संसाधन प्रदान करके आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई विविध क्षमताएँ प्रदान करते हैं। कार्यशाला ने एनईआर-डीआरआर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी-आधारित सहायता प्रदान करके अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। कार्यशाला के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत को एक आपदा-प्रतिरोधी देश बनाना था।

6.48 जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन – व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम–पीडीपी) टियर–III, 28 मई 2024, महाराष्ट्र

'जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन' पर एक दिवसीय व्यावसायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) की श्रीमती श्रावणी कुलकर्णी के स्वागत भाषण से हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के डॉ. सौरभ गोयल ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं के प्रबंधन में पेशेवरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसीइंडिया) के डॉ. राजीव शर्मा ने सत्र का अवलोकन और उद्देश्य प्रस्तुत किए। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉ. जुगल किशोर ने मेंटरिंग की कला पर चर्चा की, इसके बाद डॉ. सुजीत के. सिंह, पूर्व निदेशक, एनसीडीसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मेंटरिंग के गुणों और प्रभावी मेंटरिंग की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। मेंटर्स को रिडक्शन (एनईआर–डीआरआर) डेटाबेस के माध्यम से और अधिक संवेदनशील बनाया गया, जो व्यापक संसाधन प्रदान करके आपदा तैयारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई विभिन्न क्षमताएँ प्रदान करता है। कार्यशाला ने एनईआर–डीआरआर के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी–आधारित सहायता प्रदान कर अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। कार्यशाला के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आपदाओं की भविष्यवाणी के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के महत्व पर भी जोर दिया गया। मुख्य उद्देश्य भारत को एक आपदा–प्रतिरोधी देश बनाना था। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय के सहायक निदेशक डॉ. बिमलेश जोशी ने अपने अनुभव साझा किए। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पूर्व सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद ने पीएचईडीएम में मेंटर्स की भूमिका पर जोर दिया। कार्यशाला का समापन मेंटरशिप कार्यक्रमों से अपेक्षित परिणामों पर चर्चा के साथ हुआ।

6.49 युवा नेताओं का सम्मेलन 2024, 4–5 जून 2024, दिल्ली

युवा नेता सम्मेलन 2024, विश्व पर्यावरण दिवस समारोह: भारत ग्रीन विजन 2047 पर जलवायु क्रियाओं, एनबीएस, स्वास्थ्य और सुरक्षा को डीआरआर के साथ एकीकृत करने पर कार्यशाला का आयोजन आईआईटी इंदौर, आईआईटी रुड़की, आईसीएआरएस–आईआईटी रुड़की नोएडा परिसर, लद्दाख विश्वविद्यालय, डब्ल्यूआईएसए, यूथ4वाटर, और यूथ फॉर रेसिलिएंस और स्फीयर इंडिया के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में पर्यावरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के बीच संबंधों में वर्तमान ज्ञान और कमियों की समीक्षा की गई। इसने शोधार्थियों को अपने शोध को आगे बढ़ाने और प्रस्तुत करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी

निदेशक, एनआईडीएम ने मुख्य भाषण दिया। वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया के निदेशक श्री रितेश कुमार ने आर्द्रभूमि के महत्व पर प्रकाश डाला। यूथ4वाटर के संयोजक श्री रंजन पांडा ने वाश और जलवायु संकट से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

6.50 रासायनिक एवं औद्योगिक सुरक्षा पर सम्मेलनः आपदा जोखिम न्यूनीकरण, 06–07 जून 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) भारत के सहयोग से दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उद्योग विशेषज्ञों और पेशेवरों को रासायनिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाया गया। सुरक्षा प्रथाओं, निवेश अनुकूलन और औद्योगिक दुर्घटनाओं के मूल कारण विश्लेषण पर तकनीकी सत्रों में गहन चर्चा की गई। इसके अलावा, ज्ञान और साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों में प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई।

6.51 "1897 के महान शिलांग भूकंप की 127वीं वर्षगांठः क्या हम तैयार हैं?" पर राष्ट्रीय सेमिनार 12 जून 2024, मेघालय

1897 के महान शिलांग भूकंप की 127वीं वर्षगांठ पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; आपदा प्रबंधन, पहल और अभिसरण सोसायटी, हैदराबाद; भू-विज्ञान विभाग, उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (एनईएचयू), शिलांग और भारतीय भू-वैज्ञानिक सोसायटी, बेंगलुरु द्वारा किया गया। देश भर के गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, जिसमें कर्नल ओंकार सिंह, रजिस्ट्रार, नेहू, शिलांग ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मुख्य अतिथि के रूप प्रोफेसर हर्ष के. गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय भू-वैज्ञानिक सोसायटी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 1897 में शिलांग में आए 8.7 तीव्रता के भीषण भूकंप की 127वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक जागरूकता सह आउटरीच व्याख्यान शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईईएसओ)-2024 के लिए भारत की टीम की घोषणा, जो आईईएसओ-2024, बीजिंग, चीन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और एक सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम में भूकंपीय आपदा के दौरान जीवन बचाने के उपायों पर प्रकाश डाला गया, जिसके बाद भूकंप के लिए अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, शिलांगय उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग, परमाणु खनिज प्रभाग, शिलांग और भू-विज्ञान विभाग, नेहू, शिलांग द्वारा एक भू-प्रदर्शनी भी शामिल थी।

6.52 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर कार्यशाला, 20–21 जून 2024, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पेशेवरों के बीच प्रभावी आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए मानकों की भूमिका और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता पैदा करना था। इस कार्यक्रम में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, जोखिम आकलन, हितधारक समन्वय और तकनीकी प्रगति के लिए मानकों के महत्व को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में आपदाओं के विरुद्ध भवन की मजबूती बढ़ाने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों पर भी जोर दिया गया, अद्यतित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए रेट्रोफिटिंग और भवन स्थायित्व बढ़ाने के लिए मानकों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा, दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देना और विनाशकारी जोखिमों को कम करना भी इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था।

6.53 आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के समुत्थानशीलता को मजबूत करने पर कार्यशाला का आयोजन, 22 जून 2024, हरियाणा

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद के सहयोग से 'आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के समुत्थानशीलता को मजबूत करना' के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यशाला में चिकित्सा विशेषज्ञ, डॉक्टर, संकाय सदस्य और पैरामेडिक्स को आपदा तैयारी में अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक साथ लाया गया। प्रमुख सत्रों में आपदा प्रबंधन में चिकित्सा अधिकारियों की भूमिका, आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत करना, अस्पताल में अग्नि सुरक्षा, आपदा तैयारी में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करना और व्यापक अस्पताल आपदा प्रबंधन योजनाएँ विकसित करना शामिल था। इस कार्यक्रम ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के बीच बहुमूल्य चर्चाओं और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया।

6.54 जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला – व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी) टियर III, 25 जून, 2024, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर एक दिवसीय परामर्शदाता कार्यशाला का आयोजन किया। स्वागत भाषण एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के डॉ. प्रदीप

आवटे ने दिया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के डॉ. वर्मा ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों और आपदाओं के प्रबंधन में पेशेवरों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने में कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी इंडिया) के डॉ. राजीव शर्मा ने एक अवलोकन प्रस्तुत किया और सत्र के उद्देश्यों को रेखांकित किया। डॉ. जुगल किशोर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ने मार्गदर्शन पर चर्चा की, जिसके बाद डॉ. सुजीत के. सिंह, पूर्व निदेशक, एनसीडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्गदर्शन के गुणों और प्रभावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. बिमलेश जोशी, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तराखंड सरकार द्वारा अनुभव साझा कर मार्गदर्शकों को और अधिक संवेदनशील बनाया गया। डॉ. मुजफ्फर अहमद, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार ने पीएचईडीएम में मार्गदर्शकों की भूमिका पर बल दिया। अंत में, डॉ. राजीव शर्मा ने मार्गदर्शन कार्यक्रम के अपेक्षित परिणामों पर चर्चा की।

6.55 जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) टियर-III पर कार्यशाला, 23 जुलाई 2024, महाराष्ट्र

इस कार्यशाला में आपदा तैयारी और जन स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित पेशेवरों को एकत्रित किया गया। इसने अनुभवी परामर्शदाताओं को अपनी विशेषज्ञता साझा करने और पीएचईडीएम प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए एक आवश्यक मंच प्रदान किया। यह कार्यशाला एनआईडीएम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) महाराष्ट्र और सीडीसी इंडिया की एक सहयोगात्मक पहल थी। कार्यशाला में परामर्शदाताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और प्रभावी मार्गदर्शन रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में परामर्शदाताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और मार्गदर्शन संबंधों की प्रभावशीलता को बढ़ाने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा शामिल थी। इस सत्र का संचालन डॉ. मोहम्मद जुबेर, सलाहकार महामारी विज्ञानी, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई. जीएचएस) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार।; डॉ. मुजफ्फर अहमद, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार; डॉ. प्रदीप अवाटे, सहायक निदेशक स्वास्थ्य सेवा (एडीएचएस), लोक स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार; डॉ. बिमलेश जोशी, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तराखंड सरकार; डॉ. अलका शर्मा, संयुक्त निदेशक (डीएम), राजस्थान सरकार; डॉ. दीपा मीणा, राज्य महामारी विज्ञानी, राजस्थान सरकार; डॉ. राजीव शर्मा, लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (पीएचएस) और प्रमुख-आपातकालीन प्रबंधन (ईएम), वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभाग (डीजीएचपी), अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) - देश कार्यालय भारत; और डॉ. रजत गर्ग, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ (पीएचएस), वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभाग (डीजीएचपी), अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) - भारत स्थित कंट्री ऑफिस।

6.56 जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थानशीलता पर सम्मेलनः एक समग्र दृष्टिकोण, 25–26 जुलाई 2024, कर्नाटक

यूआईएनडीआरआर–एनआईडीएम ने जेएसएस उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, मैसूर, कर्नाटक के सहयोग से जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थानशीलताः एक समग्र दृष्टिकोण पर दो दिवसीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन ने एक व्यापक विचार–विमर्श के लिए मंच प्रदान किया, जिसमें जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थानशीलता के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से शामिल किया गया। इसमें उच्च शिक्षा की भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें हितधारकों/शिक्षाविदों के प्रयासों और भागीदारी का लाभ उठाकर जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और समुत्थानशीलता की दिशा में संभावित योगदान सुनिश्चित किया जा सके। देश के विभिन्न शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के प्रतिष्ठित लेखकों/शिक्षाविदों द्वारा लगभग 60 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन में 150 से अधिक संकाय सदस्यों और शोध विद्वानों ने भाग लिया।

6.57 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ ग्रामीण अवसंरचना का विकासः मुद्दे और चुनौतियाँ, 31 जुलाई – 1 अगस्त 2024, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से ''महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ ग्रामीण अवसंरचना का विकासः मुद्दे और चुनौतियाँ'' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जलवायु–रोधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया और नवीन अनुकूलन दृष्टिकोणों पर जोर दिया गया। तेलंगाना और ओडिशा के व्यावहारिक उदाहरणों ने सफल जलवायु–रोधी प्रयासों को प्रदर्शित किया जो अन्य क्षेत्रों के लिए आदर्श बन सकते हैं। ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में

जलवायु–समुत्थानशीलता को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक ढाँचे पर चर्चा की गई, जिसमें प्रभाव को अधिकतम करने के लिए पहलों के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यशाला में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ने, आर्थिक विकास को स्थायी आजीविका के साथ संतुलित करने और ग्रामीण परिवर्तन के लिए पर्यावरण–अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया गया।

ग्रामीण विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने को सुदृढ़ समुदायों के निर्माण के लिए आवश्यक बताया गया, जिसमें स्वच्छ, हरित और मजबूत गाँवों की अवधारणा को व्यापक स्थिरता लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया। समूह प्रस्तुतियों के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण ने प्रतिभागियों की समझ को और समृद्ध किया और जलवायु–रोधी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को लागू करने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियाँ प्रदान कीं।

6.58 आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला, 09 अगस्त 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के सहयोग से ''आपदा प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी'' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ निर्णय–निर्माता, वैज्ञानिक, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद् एक साथ आए, जिनके मुख्य भाषणों में आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एकीकरण और सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। तकनीकी सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें जोखिम मूल्यांकन, फसल बीमा और आपदा प्रतिक्रिया में जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली), एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और मशीन लर्निंग का उपयोग शामिल था। मुख्य वक्ताओं ने एसएआर (सिंथेटिक अपर्चर रडार) तकनीक में प्रगति और बेहतर आपदा तैयारी के लिए उन्नत डेटा संग्रह और एआई उपकरणों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, इस कार्यक्रम में उभरते अंतरिक्ष स्टार्ट–अप्स की पोस्टर प्रस्तुतियाँ भी शामिल थीं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रतिक्रिया में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया और गहरी समझ और भविष्य के सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

6.59 आगामी फनफेयर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रण और भगदड़ पर कार्यशाला, 20–21 अगस्त 2024, गुजरात

इस कार्यशाला की शुरुआत भीड़ प्रबंधन, भगदड़ से बचाव के महत्व और घटना प्रतिक्रिया प्रणालियों (आईआरएस) के उपयोग पर एक गहन सत्र के साथ हुई, जिसे प्रो. सूर्य प्रकाश, जीएमआर प्रमुख, सीबीआरएन, औद्योगिक एवं साइबर डीआरआर प्रभाग, एनआईडीएम द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सत्र में आपातकालीन स्थितियों में जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए रणनीतिक भीड़ नियंत्रण उपायों और आईआरएस के एकीकरण की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर

प्रकाश डाला गया। इसके बाद भीड़ प्रबंधन और भगदड़ से बचाव के लिए नीति और योजना पर एक उच्च-स्तरीय पैनल चर्चा हुई, जिसमें प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन राजकोट फनफेयर में एक ऑन-साइट फील्ड इंटरेक्शन और चर्चा के साथ हुआ, जहाँ प्रतिभागियों को प्रो. सूर्य प्रकाश (एनआईडीएम), डॉ. पवन कुमार सिंह (एनडीएमए), श्री अनिल सिन्हा (पूर्व कुलपति बीएसडीएमए), और जीएसडीएमए, ओएसडीएमए और गुजरात अग्निशमन सेवा के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिला। इस चर्चा में व्यावहारिक भीड़ प्रबंधन तकनीकों की आवश्यकता पर जोर दिया गया और भगदड़ रोकने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई।

6.60 जलवायु कार्रवाई के लिए युवाओं पर राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन, 02-04 सितंबर 2024, तमिलनाडु

जलवायु कार्रवाई के लिए युवाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके दूरगामी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रतिभागियों की समझ को गहरा करना था। इसका उद्देश्य युवाओं को जलवायु कार्रवाई पहलों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना है। कार्यक्रम ने लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन नवाचारों और जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चिंताओं और नवीन विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम ने सामाजिक कार्य हस्तक्षेपों को प्रोत्साहित किया, जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया, और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों के माध्यम से, इसका उद्देश्य प्रोंतिक संसाधनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए नवीन समाधानों को आगे बढ़ाना था।

6.61 एनआईडीएम, एनसीडीसी, सीडीसी, गूंदपुर पंचायत द्वारा सामुदायिक आपातकालीन प्रबंधन दल (सीईएमटी) और सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) पर सामुदायिक पीएचईडीएम टियर-I के संचालन हेतु जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, 05 सितंबर 2024, राजस्थान

सामुदायिक आपातकालीन प्रबंधन दल (सीईएमटी) और सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) की सूचना और संचालनात्मक भूमिकाओं के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित था। इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय के सदस्य, ग्राम पंचायत के नेता, स्वयंसेवक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और प्रमुख हितधारक शामिल थे। कार्यशाला में सीईएमटी और सीईआरटी सदस्यों की जिम्मेदारियों को दर्शाया गया: सीईएमटी स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व

करेगा, जबकि सीईआरटी सदस्यों को बचाव अभियान चलाने, प्राथमिक उपचार प्रदान करने और आश्रयों का प्रबंधन करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में औद्योगीकरण की जटिलताओं, उद्योग से संबंधित आपदाओं के जोखिमों और रासायनिक संयंत्रों कृषि पर प्रभाव पर चर्चा की गई और प्रभावी तैयारी और प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

6.62 झारखंड में जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (PHEDM) टियर-III प्रशिक्षण कार्यशाला, 10 सितंबर 2024, झारखंड

जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) पर कार्यशाला - टियर-III प्रशिक्षण में व्यावसायिक क्षमता विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएमपीडीपी) की शुरुआत की गई, जो एनआईडीएम और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की साझेदारी से विकसित एक अनूठी पहल है, जिसमें रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। यह नवोन्मेषी पाँच स्तरीय कार्यक्रम जन स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पेशेवरों की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें टियर-III प्रशिक्षण प्रतिभागियों को जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करने पर केंद्रित था। कार्यशाला में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे संरक्षक की विश्वसनीयता प्रतिबद्धता और रचनात्मक प्रतिक्रिया देने की क्षमता जैसे गुणों से प्रभावित होती है। इस कार्यक्रम में आगे बताया गया और चर्चा की गई कि कैसे मेंटर एक सहायक और गैर-आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, जो मेंटरिंग संबंध को मजबूत करता है और मेंटीज के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को सुगम बनाता है। इस कार्यशाला में आपातकालीन प्रबंधन में व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने और मजबूत नेतृत्व के निर्माण में प्रभावी मेंटरशिप के महत्व पर भी जोर दिया गया।

6.63 स्वास्थ्य खतरों, जोखिम प्रबंधन और संचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला, 18-20 सितंबर, 2024, गोवा

स्वास्थ्य खतरों, जोखिम प्रबंधन और संचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला उन्नत प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) ओएनजीसी दक्षिण गोवा में आयोजित की गई। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय द्वारा एटीआई ओएनजीसी, गोवा और राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम) के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और जोखिम संचार रणनीतियों, आपदा प्रतिक्रिया, मीडिया की भूमिका, व्यावहारिक प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक अभ्यासों को कवर करने वाले विभिन्न सत्र शामिल थे। कार्यशाला में आपदाओं के संदर्भ में स्वास्थ्य खतरों, जोखिम प्रबंधन और संचार पर चर्चा की गई, संचार रणनीतियों, आपातकालीन

चेतावनी प्रणालियों और अग्निशामक यंत्रों के उपयोग और स्मोक हाउस निकासी अभ्यास पर व्यावहारिक सत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्र तट सफाई अभियान चलाया गया, जिसके बाद रासायनिक उद्योगों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, सीपीआर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यावहारिक अभ्यासों पर सत्र आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को आपदा परिदृश्यों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

6.64 विकास योजना में डीआरआर और सीसीए उपायों को मुख्यधारा में लाने पर कार्यशाला– ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित, 27 सितंबर, 2024, बिहार

एनआईडीएम ने केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार (सीयूएसबी) और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बीएसडीएमए) के सहयोग से 'विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को मुख्यधारा से जोड़ने एवं ग्रामीण क्षेत्र पर केन्द्रित' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की, जो सीयूएसबी परिसर, गया में आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह और गया के अपर जिलाधिकारी (आपदा प्रबंधन) श्री कुमार पंकज ने की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्रामीण क्षेत्र में डीआरआर और सीसीए उपायों को मुख्यधारा में लाना था। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि शिक्षा जगत और राज्य प्राधिकरणों को कार्योन्मुखी अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इस संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया कि सीयूएसबी और बीएसडीएमए ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण हेतु मिलकर काम करने हेतु एक रोडमैप तैयार करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं को मुख्यधारा में लाने में सहायता मिल सके। कार्यशाला का संचालन एनआईडीएम की डॉ. गरिमा अग्रवाल और सीयूएसबी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मंजीत ने किया।

6.65 अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर कार्यशाला, 23 अक्टूबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस (डीआरआर) समारोह आयोजित करता है। इस अवसर पर, एनआईडीएम ने डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली में 'सशक्त युवा, सुरक्षित भविष्य' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में, एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक, श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से) ने इस बात पर जोर दिया कि एनआईडीएम आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय एवं संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएनडीआरआर-एनआईडीएम) की पहल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से 318 विश्वविद्यालयों को जोड़ा गया है। केंद्रीय गृह सचिव, श्री गोविंद मोहन (भा.प्र.से) ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन और बदलते मौसम के मिजाज के कारण आपदाएँ और खतरे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह ने एक सुदृढ़ भविष्य के निर्माण हेतु शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर बल दिया। भारत सरकार के माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत ने आपदा न्यूनीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, (भा.प्र.से), उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री के. संजय मूर्ति ने अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यशाला में दो पूर्ण सत्र शामिल थे जिनमें प्रोफेसर योगेंद्र सिंह (आईआईटी रुड़की), डॉ. अनिल कुमार पंडित, पूर्व विशेष महानिदेशक, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), सुश्री अमरप्रीत दुग्गल, संयुक्त आईपीओएस सचिव, समन्वय एवं मीडिया प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और अन्य लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों और क्षेत्रीय चुनौतियों में आपदा प्रबंधन के बारे में अपना ज्ञान साझा किया।

श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी), श्री टी.डी. धारियाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ, श्री संजीव कुमार जिंदल, अतिरिक्त सचिव (डीएम), गृह मंत्रालय, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और कई अन्य लोगों ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

भारत सरकार के माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात पर जोर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने ''मिशन लाइफ'' की शुरुआत की है जो भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए स्थायी जीवन और सचेत जीवनशैली में बदलाव को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम का समापन एनआईडीएम के संयुक्त निदेशक कर्नल पी.एस. रेड्डी के समापन भाषण के साथ हुआ।

इसके अतिरिक्त, एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि समुदायों को आपदाओं से जुड़े जोखिमों को समझने और उन्हें कम करने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा, एनआईडीएम ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट्स द्वारा 12 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें आपदा सिमुलेशन, आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन मैपिंग, स्व-चमकते निकासी मानचित्र, उन्नत प्राथमिक चिकित्सा किट आदि के रूप में आपदा जोखिम न्यूनीकरण में नवाचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का समापन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ''कला सांझ'' के साथ हुआ, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर ने मनमोहक प्रस्तुतियाँ दीं और पंडित अभिमन्यु लाल और सुश्री वर्षा दासगुप्ता का मनमोहक कत्थक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया।

6.66 जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन – व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम–पीडीपी) टियर–III, 19 नवंबर, 2024, गुजरात

पीएचईडीएम–पीडीपी टियर–III कार्यशाला ने उन पेशेवरों को एक साथ लाया जो आपदा तैयारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। यह सहयोगात्मक पहल, जिसका आयोजन एनआईडीएम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) गुजरात, और सीडीसी–इंडिया द्वारा किया गया, अनुभवी मेंटर्स को अपना ज्ञान साझा करने और जन स्वास्थ्य आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) प्रथाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

कार्यशाला में मेंटर्स की अहम भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया, उनके कर्तव्यों और मेंटरिंग संबंधों को सुधारने की रणनीतियों का अन्वेषण किया गया, तथा स्थानीय आपदा प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, कार्यशाला में मेंटरिंग कला पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें मेंटर्स को गाइड किया गया कि वे कैसे मेंटीज का समर्थन कर स्थानीय क्षमताएं जैसे स्टाफिंग, सिस्टम और अवसंरचना जो पीएचईडीएम के लिए आवश्यक हैं, का विकास कर सकें।

कार्यशाला में थ्रेट और हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट (टीएचआईआरए), रिस्क कम्युनिकेशन, और जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों (पीएचईओसी) की स्थापना पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर, इस कार्यशाला ने सहयोग को प्रोत्साहित किया, प्रतिभागियों की पीएचईडीएम भूमिकाओं की समझ को गहरा किया, और प्रभावी मेंटरशिप तथा तैयारी प्रयासों के माध्यम से अधिक सुदृढ़ समुदायों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा।

6.67 सिल्क्यारा सुरंग बचाव की प्रथम स्मृति वर्षगांठ पर कार्यशाला, 28 नवंबर, 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय – भारत और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राजेंद्र रत्नू भा.प्र.से, ईडी, एनआईडीएम; श्री भास्कर खुल्बे, आईएएस, विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी), उत्तराखंड सरकार, पीएमओ; श्री राजेंद्र सिंह, सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, एनडीएमएय लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन, सदस्य, एनडीएमए; श्री आर.के. धीमन, एडी (सेवानिवृत्त), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) एवं अध्यक्ष, टनलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडियाय कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम; और डॉ. सूर्य प्रकाश, परियोजना निदेशक, हाईकैप, एनआईडीएम ने किया। इस कार्यशाला में 'जलवायु एवं आपदा–रोधी

सुरंगों' पर नीति एवं दिशा-निर्देशों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और सिल्क्यारा सुरंग दुर्घटना एवं अन्य सुरंग आपदाओं से प्राप्त मूल्यवान सबक पर प्रकाश डाला गया। इसका उद्देश्य आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया के लिए कार्यान्वयन योग्य रणनीतियाँ विकसित करना था।

6.68 प्रैक्टिस कम्युनिटीज (सीओपी) पर राष्ट्रीय कार्यशाला- भारत में सतत शहरी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर शहरों को सक्षम बनाना, 28 नवंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) रोहिणी परिसर, नई दिल्ली में 'प्रैक्टिस कम्युनिटीज- भारत में सतत् शहरी विकास के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पर शहरों का सशक्तिकरण' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिनमें श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; डॉ. टेरेसा केर्बर, परियोजना निदेशक, एसयूडीएससी-II, जीआईजेड इंडिया; श्री पी जयपाल, वरिष्ठ सलाहकार, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण (सीडीएमए); श्री पी.एस. रेड्डी, जेडी, एनआईडीएम; डॉ. आमिर अली खान, एसोसिएट प्रोफेसर, एनआईडीएम; और डॉ. गरिमा अग्रवाल, जीआईजेड-एनआईडीएम परियोजना प्रमुख एवं वरिष्ठ सलाहकार शामिल थे। श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से ने स्थायी शहरों के निर्माण और शहरी समुत्थानशीलता पर ध्यान देने के महत्व पर जोर दिया। कार्यशाला में दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जहाँ विशेषज्ञों ने एनआईडीएम-जीआईजेड परियोजना के परिणामों और शहरी समुत्थानशीलता पर सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। इसके अलावा, शहरी मजबूती पर एक ऑनलाइन ज्ञान वर्टिकल का शुभारंभ किया गया और 'आपदा के बाद की स्थितियों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम का समापन श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; सुश्री तोरा सैकिया, जीआईजेड, और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. मोनिका विज के समापन भाषण के साथ हुआ। डॉ. गरिमा अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

6.69 भोपाल गैस त्रासदी के चालीस वर्ष: सबक, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, 03 दिसंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय ने इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 'भोपाल गैस त्रासदी के चालीस वर्ष: सबक, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं शीर्षक से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नीति निर्माताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के नेताओं ने भोपाल गैस त्रासदी के दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार-विमर्श किया और भारत में औद्योगिक सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन किया। उद्घाटन सत्र में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें श्री कृष्ण

वत्स, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), श्री दीपांकर एरन, संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम, प्रो. (डॉ.) अतुल गोयल, डीजीएचएस एवं निदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार शामिल थे।

तकनीकी सत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने भाग लिया, जैसे श्री डी. पी. नंदा, मुख्य महाप्रबंधक (एचएसई) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (इंडिया) लिमिटेड, डॉ. ओ. बी. कृष्णा, सुरक्षा इंजीनियरिंग एवं विश्लेषण उत्कृष्टता केंद्र (सीओई–एसईए), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, डॉ. मीरा धुरिया (जेडी) प्रमुख– जन स्वास्थ्य तैयारी एवं एनसीडी और जैव रसायन एवं विष विज्ञान विभाग– राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, प्रो. प्रतीक शर्मा (वीसी– दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पूर्व में डीसीई)), श्री उमेश ढाके, सह निदेशक, रासायनिक प्रक्रिया सुरक्षा केंद्र (सीसीपीएस) और डॉ. सुजीत सिंह–वरिष्ठ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, विश्व स्वास्थ्य संगठन। समापन सत्र में, श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम ने भारत में अधिक सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया।

6.70 राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (एनएटीसी), 13 दिसंबर 2024, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एकत्रित करके वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (एनएटीसी) का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रमुख दूरदर्शी व्यक्तियों द्वारा किया गया, जैसे श्री राजेश गुप्ता, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन); डॉ. कृष्ण वत्स, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)' श्री अमित प्रोथी, महानिदेशक, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई); श्री राजेंद्र रत्नू भा.प्र.से, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम; कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम; और डा़. सूर्य प्रकाश, प्रोफेसर एवं प्रमुख, जीएमआर प्रभाग, एनआईडीएम।

तकनीकी सत्र–I की अध्यक्षता डॉ. अजिंदर वालिया, प्रमुख जीआईडीआरआर, एनआईडीएम ने की। इस सत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण और मंत्रालयों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और केंद्रीय संस्थानों के बीच सहयोग पर जागरूकता फैलाई गई। तकनीकी सत्र II की अध्यक्षता डॉ. सूर्य प्रकाश ने की और संचालन श्री शिव नारायण सिद्ध, सहायक प्रोफेसर, एनआईडीएम ने किया। इस सत्र में राज्यों, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और राहत आयुक्तों (आरसी) के बीच सहयोग पर चर्चा की गई। समापन सत्र का समापन श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम द्वारा डॉ. कृष्ण वत्स के समापन भाषण और कर्नल पी.एस. रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने समुत्थानशीलता योजना को बेहतर बनाने पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की।

6.71 गूंदपुर ग्राम पंचायत में समुदाय-आधारित जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन (सीबी-पीएचईडीएम) टियर-I पर कार्यशाला, 07-08 जनवरी 2025, राजस्थान

यह कार्यक्रम राजस्थान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय (एमएचए); राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी); स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीटीई-जीएचएस), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार; चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राजस्थान सरकार; और अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी), कंट्री ऑफिस-भारत के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों को आवश्यक कौशलों से लैस करके जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी और जन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को मजबूत करना था।

इस कार्यक्रम में समावेशी सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया गया, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को आपदा नियोजन और प्रतिक्रिया में शामिल किया गया और समुत्थानशील बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी गई। स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक आपदा प्रबंधन रणनीतियों के साथ एकीकृत करके एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि पारंपरिक प्रथाएँ वैज्ञानिक प्रगति के पूरक बनें। प्रो. सूर्य प्रकाश ने पीएचईडीएम ढाँचे की शुरुआत की, जो समुदाय से लेकर राष्ट्रीय प्राधिकरणों तक, पाँच प्रशासनिक स्तरों पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। यह संरचित दृष्टिकोण लचीलापन, तैयारी और प्रतिक्रिया प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिसमें स्थानीय भागीदारी आपदा प्रबंधन की नींव का काम करती है। इसके अलावा, प्रतिभागियों को आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और उनका जवाब देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। पायलट कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित किया और इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने और राज्य एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचों में एकीकृत करने की वकालत की।

6.72 जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला (पीएचईडीएम-पीडीपी) टियर-III, 15 जनवरी 2025, झारखंड

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) झारखंड, और सीडीसी-इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा तैयारी और जन स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पेशेवरों को एक साथ लाया गया। प्रमुख संसाधन व्यक्तियों में डॉ. सुजीत के. सिंह (जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एनसीडीसी के पूर्व निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) (भारत सरकार), डॉ. शुभांगी कुलसंगे (संयुक्त निदेशक, आईडीएसपी), डॉ. रविशंकर सिंह, क्षेत्रीय निदेशक,

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओएचएफडब्ल्यू), पटना, डॉ. जुगल किशोर (सामुदायिक चिकित्सा के निदेशक प्रोफेसर, वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल), और डॉ. रजत गर्ग (पीएचएस, डीजीएचपी, सीडीसी-इंडिया) शामिल थे। कार्यशाला में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में मेंटरशिप की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इसमें बहु-क्षेत्रीय समन्वय, जोखिम मानचित्रण और व्यापक तैयारी, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के तरीकों के माध्यम से पीएचईडीएम क्षमताओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। चर्चाओं ने प्रभावी तैयारी ढाँचे बनाने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की, साथ ही पीएचईडीएम के लिए महत्वपूर्ण स्टाफिंग, प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे में स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

6.73 राष्ट्रीय क्रिटिकल केयर नर्सिंग सम्मेलन (एनसीएनसीओएन) पर कार्यशाला, 14-15 फरवरी, 2025, चंडीगढ़

आईयूआईएनडीआर-एनआईडीएम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के सहयोग से, पीजीआईएमईआर के भार्गव ऑडिटोरियम में 'आपातकालीन, शल्यक्रिया के बाद और गहन देखभाल में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा' विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत भर से नैदानिक नर्सों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रशासकों सहित 1,150 चिकित्सा पेशेवरों ने भाग लिया। दो दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों के नेतृत्व वाले सत्र, इंटरैक्टिव कार्यशालाएँ, पैनल चर्चाएँ और आपातकालीन देखभाल, शल्यक्रिया के बाद की प्रक्रियाओं और गहन देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रगति पर केंद्रित व्यावहारिक प्रदर्शन शामिल थे। जीवन रक्षक प्रणाली, वेंटिलेटर प्रबंधन और दर्द प्रबंधन पर व्यावहारिक सत्रों ने प्रतिभागियों को आवश्यक नैदानिक कौशल प्रदान किया। कार्यशाला में अंत:विषयक स्वास्थ्य सेवा टीमों में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया और निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसने नेटवर्किंग, ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोगात्मक पहलों की खोज के लिए एक मंच भी प्रदान किया, जिससे स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में रोगी-केंद्रित देखभाल में सुधार के लिए साझा प्रतिबद्धता को बल मिला।

6.74 प्राकृतिक आपदाओं और आपदा प्रबंधन में उन्नत भू-कम्प्यूटेशनल तकनीकों पर कार्यशाला सुदृढ़ समाज और स्थिरता के लिए, 27-28 फरवरी, 2025, उत्तर प्रदेश

'प्राकृतिक आपदाओं और आपदा प्रबंधन में उन्नत भू-कम्प्यूटेशनल तकनीकों' पर दो दिवसीय कार्यशाला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जियोइन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग (AIGIRS), एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। कार्यशाला का उद्देश्य भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल

इंटेलीजेंस-संचालित दृष्टिकोणों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग जगत के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यशाला में अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया गया। बैठक में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशील (डीआरआरएवंआर) अवधारणाओं, आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढाँचे और खतरा, संवेदनशीलता, क्षमता और जोखिम (एचवीसीआर) मूल्यांकन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई, जिसमें बहु-खतरा मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया प्रतिभागियों ने आपदा तैयारी में भू-स्थानिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों का अन्वेषण किया, विशेष रूप से बाढ़ अध्ययन, सुदूर संवेदन और डेटा संग्रहण के क्षेत्रों में। उन्होंने बाढ़ जलप्लावन मानचित्रण के लिए गूगल अर्थ इंजन (GEE) तथा वन अग्नि मॉडलिंग के लिए भू-सूचना विज्ञान के उपयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। कार्यशाला में एआई-संचालित आपदा जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से छत-आधारित सामुदायिक संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए और नीति और शहरी नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों के एकीकरण पर बल दिया गया।

भू-स्थानिक विज्ञानों के लिए डेटा विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर सत्रों ने आपदा पूर्वानुमान और जोखिम न्यूनीकरण हेतु उभरती प्रौद्योगिकियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान की। अंततः, यह कार्यशाला उन्नत भू-कम्प्यूटेशनल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित तकनीकों के माध्यम से आपदा तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और सतत् विकास को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

6.75 भूकंप जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर एक दिवसीय पूर्वावलोकन कार्यशाला, 04 मार्च, 2025, दिल्ली

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से 'भूकंप जोखिम न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर एक दिवसीय पूर्वावलोकन कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य कमियों की पहचान करना और भूकंप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के समाधानों पर सहयोग करना था। यह क्षेत्रीय कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए भी मंच तैयार करता है, जिसमें गुजरात भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य रणनीतियों और शहरी बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ता में हाल के विकासों से प्राप्त अंतर्दृष्टि का परीक्षण किया जाएगा। यह पहल भुज भूकंप के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी, जिसमें गुजरात के पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण प्रयासों से महत्वपूर्ण सबक प्राप्त करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और सम्मेलनों की सामूहिक अनुशंसाएँ एक राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना में योगदान देंगी - जो देश भर में समुत्थानशीलता और तैयारी को मजबूत करने के लिए एक आवश्यक रोडमैप है। यह कार्यक्रम प्रो. सी.वी.आर. मूर्ति (आईआईटी मद्रास), श्री संजीव कुमार जिंदल (अतिरिक्त सचिव, आपदा प्रबंधन), श्री राजेंद्र सिंह (सदस्य एवं विभागाध्यक्ष, एनडीएमए) जैसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और अन्य प्रतिष्ठित नेताओं की उपस्थिति से और समृद्ध होगा, जो भारत में भूकंप के जोखिम को कम करने पर अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। अपने ज्ञान, अनुभवों और अनुशंसाओं को साझा करके, ये विशेषज्ञ भूकंप के जोखिमों को कम करने, तैयारियों को बढ़ाने और देश

भर में एक सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए एक अधिक मजबूत और व्यापक रणनीति का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करते हैं।

6.76 आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर क्षेत्रीय कार्यशाला 10-11 मार्च 2025, केरल

'आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), इसरो द्वारा संयुक्त रूप से भूमि एवं आपदा प्रबंधन संस्थान (आईएलडीएम), केरल में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलता बढ़ाना था। यह क्षेत्र भर के आपदा प्रबंधन पेशेवरों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। कार्यशाला में अंतरिक्ष-आधारित उपकरणोंजैसे उपग्रह इमेजरी, सुदूर संवेदन और भू-स्थानिक डेटोंकी परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने, जोखिम मूल्यांकन में सुधार लाने और वास्तविक समय में आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का समर्थन करने में सहायक है। इसका एजेंडा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) ढाँचों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ावा देना था। कुल मिलाकर, यह कार्यशाला आपदा तैयारी, जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत् विकास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

6.77 सामुदायिक आधारित जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (सीबी-पीएचईडीएम) टियर-I और II पर कार्यशाला, 18 मार्च 2025, राजस्थान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) और सीडीसी इंडिया के तकनीकी सहयोग से सामुदायिक आधारित जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (सीबी-पीएचईडीएम) पर प्रशिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक समुत्थानशीलता को मजबूत करना था। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, स्थानीय आपदा तैयारियों को बढ़ाने के लिए सामुदायिक आपातकालीन प्रबंधन दल (सीईएमटी) और सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी) को नामित किया गया था। प्रतिभागियों को बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा, खोज और बचाव, और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया कौशल में प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर सकें और एक अधिक सुदृढ़ समुदाय में योगदान दे सकें। इस कार्यक्रम में डॉ. प्रवीण असवाल, अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान सरकार; डॉ. सौरभ गोयल, संयुक्त निदेशक, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), एनसीडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), भारत सरकार; डॉ. कौशल गुप्ता, आरओएचएफडब्ल्यू, एमओएचएफडब्ल्यू; और डॉ. मुकेश विजयवर्गीय, अकाल एवं संयुक्त निदेशक, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान सरकार, प्रो. सूर्य प्रकाश, प्रमुख जीएमआरडी, एनआईडीएम

(ऑनलाइन) और डॉ. रजत गर्ग, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ, सीडीसीइंडिया (ऑनलाइन) की उपस्थिति रही। राजस्थान के 34 विभिन्न जिलों से कुल 85 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके अलावा, कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन (पीएचईडीएम) टियर-III मेंटीज की भी भागीदारी थी, जैसे कि महामारी विज्ञानियों, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (डिप्टी सीएम एंड एचओ) और कई जिलों के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ) आदि। इन सब की उपस्थिति ने प्रशिक्षण में बहुमूल्य जानकारी और व्यावहारिक अनुभव जोड़े।

6.78 दूसरा विजन जीरो शिखर सम्मेलन: सुदृढ़ शहरीकरण और सुरक्षित गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 26-28 मार्च 2025, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) और भारतीय नगर नियोजक संस्थान (आईटीपीआई) ने मिलकर दूसरा विजन जीरो शिखर सम्मेलन, सुदृढ़ शहरीकरण और सुरक्षित गतिशीलता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और हितधारक एक साथ आए। इसमें भारत में सड़क सुरक्षा पर केंद्रित 6 पूर्ण सत्र आयोजित किए गए। प्रमुख परिवहन सुरक्षा मुद्दों और चुनौतियों की पहचान, परिवहन सुरक्षा में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा, सर्वोत्तम प्रथाओं और केस स्टडीज को साझा करने और परिवहन सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुझाव देने पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन के दौरान, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, परियोजना निदेशक, हाईकैप और सुश्री बिंदु अग्रवाल, परियोजना प्रबंधक, हाईकैप द्वारा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में राजमार्गों की संवेदनशीलता और समुत्थानशीलता का विश्लेषण करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य आपदाओं, आर्थिक मंदी और सामाजिक चुनौतियों जैसे झटकों और तनावों का सामना करते हुए निरंतरता बनाए रखने के लिए रणनीतियों और समाधानों के विकास पर विचार-विमर्श करना था।

6.79 आपदा जोखिम न्यूनीकरण: हिमालयी आपदा प्रतिरोधक क्षमता पर केन्द्रित सम्मेलन, 27 मार्च, 2025, लद्दाख

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और भारत सरकार के 16वें वित्त आयोग द्वारा तकनीकी भागीदार के रूप में लद्दाख विश्वविद्यालय के सहयोग से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसके बाद लद्दाख के मुख्य सचिव, डॉ. पवन कोटवाल (भा.प्र.से) ने मुख्य भाषण दिया। श्री राजेंद्र रत्नू (भा.प्र.से), ईडी, एनआईडीएम ने चर्चाओं का संदर्भ प्रस्तुत किया। प्रो. डॉ. साकेत कुशवाहा, कुलपति, लद्दाख विश्वविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया और सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया। सम्मेलन में विशिष्ट वक्ताओं और पैनलिस्टों द्वारा गहन चर्चा की गई, जिनमें श्री श्रवण प्रभु, ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईडब्ल्यू); श्री आकाश मिश्रा, आपदा

प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा गठबंधन (सीडीआरआई); श्री पी.जी. धर चक्रवर्ती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान; डॉ. रूपम शुक्ला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की; श्री प्रदीप कुमार जेना भा.प्र.से, पूर्व मुख्य सचिव एवं मुख्य विकास आयुक्त, ओडिशा; सुश्री शशांक आला, भा.प्र.से, प्रशासनिक सचिव,

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख; प्रो. दीवान सिंह रावत, कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय, उत्तराखंड; डॉ. सोनम लोटस, प्रमुख, भारत मौसम विज्ञान विभाग, लेह और डॉ. प्रीति सोनी, एनआईडीएम सम्मिलित थीं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रमुख हितधारकों, जिनमें नीति निर्माता, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल थे, ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और एक सुरक्षित एवं सुदृढ़ भविष्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के समापन सत्र में श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, सदस्य, 16वें वित्त आयोग के समापन भाषण दिए गए। सम्मेलन ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट कमजोरियों के अनुरूप मजबूत जोखिम शमन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

सम्मेलन/कार्यशाला/सेमिनार (एनआईडीएम दक्षिण परिसर)

6.80 युवाओं और किशोरों को डीआरआर और सीसीए में शामिल करने पर कार्यशाला, 03 मई 2024, बिहार

सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), बाल रक्षा भारत और क्राई – बाल अधिकार और आप (क्राई) के सहयोग से दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) में युवाओं और किशोरों को डीआरआर और सीसीए में शामिल करना के विषय पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यशाला के विशेषज्ञों में शामिल थे डॉ. कुमार राका (वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम), प्रो. प्रणव कुमार (विभागाध्यक्ष, सीयूएसबी), प्रो. आतिश पाराशर (सीयूएसबी), प्रो. वेंकटेश सिंह (आईक्यूएसी समन्वयक, सीयूएसबी), श्री मिंटू देबनाथ (प्रमुख-पीआईयू, बीआरबी), डॉ. शाहीन अंसारी (क्राई), सुश्री देबद्रिता सेनगुप्ता (बीआरबी), श्री. दिलीप कुमार (पूर्व बीएसडीएमए, बिहार सलाहकार), डॉ. पल्लव कुमार (यूनिसेफ) और डॉ. बुधेंद्र सिंह (सीयूएसबी), माननीय कुलपति, सीयूएसबी, प्रो. के.एन. सिंह ने कार्यशाला की नीतिगत सिफारिश की घोषणा की। श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से, (ईडी, एनआईडीएम) ने इस पहल का नेतृत्व और समर्थन किया, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को इसमें सफलतापूर्वक भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एक समाधान-उन्मुख संवाद को प्रारंभ करना था।

6.81 आपदाओं एवं आपात स्थितियों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार पर कार्यशाला, 10 मई 2024, मणिपुर

राज्य प्रशिक्षण अकादमी (एसएटी), मणिपुर में बाल रक्षा भारत (बीआरबी) और बाल अधिकार एवं आप (सीआरवाई) के सहयोग से एक राज्य स्तरीय नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री राजेंद्र रत्नू, आईएएस, (कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम); श्री कीसम प्रदीप कुमार, अध्यक्ष, मणिपुर बाल अधिकार संरक्षण आयोग; श्री एम.एच. खान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मणिपुर (राहत एवं आपदा प्रबंधन); श्री एम.डी.एस.दौलत खान, अतिरिक्त निदेशक (एसएटी); श्री हमोम बर्लिन सिंह (एसएटी); सुश्री दीपा, सहायक निदेशक, मणिपुर सरकार और डॉ. बालू आई, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम, सुश्री कृतंजलि कश्यप और सुश्री देबद्रिता सेनगुप्ता, बाल रक्षा भारत शामिल थे। कार्यशाला में मणिपुर राज्य के वरिष्ठ प्रतिनिधियों – सुश्री लीशांगथेम कमला, सुश्री ग्रेस जोजो, डॉ. कोइजाम सोबिता देवी, श्री मैबाम रोबिंद्रो सिंह और सुश्री डॉली देवी

लाइपुबम ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में आपदाओं के प्रति बाल-केंद्रित समुत्थानशीलता बनाने की नवीन रणनीतियों पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए, चुनौतियों का विश्लेषण किया और आपदाओं के प्रति बाल-केंद्रित समुत्थानशीलता बनाने की नवीन रणनीतियों पर चर्चा की।

6.82 आपदाओं एवं आपात स्थितियों में बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण पर कार्यशाला, 07 जून 2024, आंध्र प्रदेश

इस कार्यशाला में देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री सचिन शर्मा (जम्मू-कश्मीर), श्री एन. आर.ठाकुर (हिमाचल प्रदेश), सुश्री लेखा चाको (केरल), ई. खरपुरी (मेघालय), सुश्री चित्रा (पुडुचेरी), डॉ. मीना चंदराना (दादरा एवं नगर हवेली), श्री बीरेंद्र कुमार (झारखंड) और श्री देबाशीष भट्टाचार्य (त्रिपुरा)। विशेषज्ञ वक्ताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों ने मिलकर एक गतिशील शिक्षण वातावरण का निर्माण किया, जहाँ उन्होंने नवीन रणनीतियों की खोज की और अपने अनुभव साझा किए जिसके परिणामस्वरूप मसौदा नीति सिफारिशें तैयार हुईं। इस कार्यशाला के संरक्षक श्री राजेंद्र रत्नू, भा.प्र.से, ईडी, एनआईडीएम और कर्नल पी.एस. रेड्डी, जेडी, एनआईडीएम थे। डॉ. कुमार राका (वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम) को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए, साथ ही श्री नवीन शुक्ला (बाल रक्षा भारत), डॉ. बालू आई, श्री रंजन कुमार और सुश्री नाजिया शेख को सीसीडीआरआर से सम्मानित किया गया।

6.83 ''बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण'' पर कार्यशाला, 14 जून 2024, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई), शिमला में 'बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण' पर एक राज्य स्तरीय नीति कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य CCDRR पर बेहतर परिणामों के लिए विभागीय और अन्य हितधारकों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला में जिलों के विशेषज्ञों ने बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हितधारकों की तैयारी और न्यूनीकरण हेतु क्षमता निर्माण में चुनौतियों और कमियों पर चर्चा की। कार्यशाला में राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गईं- श्री विजेंद्र चौहान (शिक्षा), श्री राजिंदर शर्मा (पंचायती राज), सुश्री नवीता शर्मा (होमगार्ड), मोहम्मद शमीम (बाल संरक्षण), डॉ. ओमेश भारती (स्वास्थ्य) और श्री सुदेश बेदी (युवा प्रतिनिधि)। कार्यशाला में बाल-केंद्रित लचीलेपन को बढ़ावा देने के रचनात्मक तरीकों पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन राज्य के विशेषज्ञों द्वारा सीसीडीआरआर पर प्रमुख नीतिगत सिफारिशों के साथ हुआ।

6.84 शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला, 14 जून 2024, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने एनआईडीएम, दक्षिण परिसर (विजयवाड़ा) में 'शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन' पर एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एसडीएमए/डीडीएमए, शहरी स्थानीय निकायों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के बीच एक व्यापक चर्चा हुई, जिन्होंने शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया। कार्यशाला का एजेंडा सुदृढ़ शहरों के लिए शहरी बाढ़ प्रबंधन कार्य योजना विकसित करना (एनआईडीएम-जीआईजेड के समझौते के अनुसार) और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) और एनडीएमए के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावों की तैयारी पर चर्चा करना था। कार्यशाला में शहरी बाढ़ जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और सतत् विकास के लिए शहरी नियोजन में बाढ़ जोखिम प्रबंधन के एकीकरण पर जोर दिया गया। चर्चाओं में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण द्वारा शहरी समुत्थानशीलता बढ़ाने में प्राकृतिक-आधारित समाधानों (एनबीएस) और पारिस्थितिक संरक्षण की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के शहरी बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कोष (यूएफआरएमएफ) के अंतर्गत शहरी बाढ़ से बचाव के उपाय बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, कार्यशाला में बाढ़ के बाद जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रभावित क्षेत्रों में द्वितीयक आपदाओं को रोकने के लिए कुशल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर बल दिया गया। इन अंतर्दृष्टियों ने रणनीतिक योजना और नवीन समाधानों के माध्यम से बाढ़-प्रतिरोधी शहरों के निर्माण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित किया। विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने एनडीएमए के दिशा-निर्देशों और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का पालन करते हुए अपने शहरों के लिए मसौदा कार्य योजनाओं का योगदान दिया।

6.85 आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला, 28 जून 2024, आंध्र प्रदेश

बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर), एनआईडीएम ने बाल रक्षा भारत (बीआरबी) और बाल अधिकार एवं आप (क्राई) के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में अंतर और चुनौतियों का पता लगाना था। एनआईडीएम, दक्षिण परिसर के संयुक्त निदेशक कर्नल पी.एस. रेड्डी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉ. कुमार राका, डॉ. बालू आई, श्री रंजन कुमार, डॉ. तन्वी (बीआरबी), सुश्री नाजिया शेख (सीसीडीआरआर) भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के विशेषज्ञ अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, मणिपुर, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से आए थे।

6.86 आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला, 12 जुलाई 2024, आंध्र प्रदेश

एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा में 'आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के लिए मौजूदा कमियों और चुनौतियों को समझना और आपात स्थितियों में बच्चों के लिए समुत्थानशीलता बनाने हेतु रणनीतियाँ और सुझाव तैयार करना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्य चर्चा बाल संरक्षण और बाल अधिकारों को आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और स्थानीय स्तर की संस्थाओं की क्षमता को मजबूत करने के साथ एकीकृत करने पर हुई। कर्नल पी. एस. रेड्डी (संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम एससी) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रारंभिक भाषण दिया। श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, निदेशक, आदिवासी कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश, ने अपने विशेष संबोधन से प्रतिभागियों को अवगत कराया और अपने अनुभव साझा किए। डॉ. कुमार राका (वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम) ने बाल संरक्षण और बाल अधिकार मुद्दों के महत्व पर प्रकाश डाला और आपात स्थितियों में बाल-केंद्रित आपदा जोखिम को कम करने के लिए बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों पर बल दिया।

6.87 आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला, 26 जुलाई 2024, आंध्र प्रदेश

सीसीडीआरआर एनआईडीएम ने एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभागीय और अन्य हितधारकों की क्षमताओं को मजबूत करना था ताकि सीसीडीआरआर पर बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकें। कार्यशाला में जिलों के विशेषज्ञों को बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए हितधारकों की तैयारी और शमन हेतु क्षमता निर्माण में चुनौतियों और कमियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया। इसमें जमीनी स्तर की आवाजों के उपयोग के माध्यम से राज्य की नीति और कार्यक्रम संबंधी निर्णयों में बच्चों के दृष्टिकोण को शामिल किया गया।

कार्यशाला में राज्य के प्रतिनिधियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दीं जिनमें श्री एम राजेश्वर राव, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी), (संरचनात्मक न्यूनीकरण), श्री बी प्रसाद, आंध्र प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल (एपीएसडीआरएफ), (गैर-संरचनात्मक न्यूनीकरण) श्री राहुल गुप्ता, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ), समाज कल्याण विभाग (एसडब्ल्यूडी) (अवसंरचनात्मक न्यूनीकरण) श्री दुर्गेश्वर सैकिया, वरिष्ठ व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी); (पर्यावरण न्यूनीकरण) और श्री राज कुमार भराली, व्याख्याता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं

प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) (व्यक्तिगत एवं सामाजिक न्यूनीकरण) आदि शामिल थे। कार्यशाला में बाल-केंद्रित समुत्थानशीलता को बढ़ावा देने के रचनात्मक तरीकों पर गहन चर्चा की गई। सीसीडीआरआर पर राज्य के विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई प्रमुख नीतिगत सिफारिशों के साथ कार्यशाला का समापन किया गया।

6.88 आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला, 09 अगस्त 2024, लद्दाख

आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा और लद्दाख विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस कार्यक्रम में लद्दाख पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और वक्ता एक साथ आए। उद्घाटन समारोह की शुरुआत सुश्री नरगिस बानो, सहायक प्रोफेसर, और सामाजिक कार्य विभाग द्वारा एक गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण के साथ हुई। डॉ. बालू आई, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने कार्यशाला की संक्षिप्त रूपरेखा और उद्देश्यों के साथ-साथ चर्चाओं के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान की। उद्घाटन भाषण लद्दाख विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के डीन डॉ. जिग्मेट डेचेन ने दिया। उन्होंने कार्यशाला के महत्व पर अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इसके बाद श्री शरीफ भट, डॉ. तन्वी चौहान और श्री नवीन शुक्ला सहित सम्मानित अतिथियों ने विशेष भाषण दिए और अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा किए। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने मुख्य भाषण दिया और विषय का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया। कार्यशाला का उद्देश्य आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के लिए राज्यों में मौजूद कमियों, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना और प्रमुख नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना था।

6.89 आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला, 23 अगस्त 2024, आंध्र प्रदेश

बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने बाल रक्षा भारत (बीआरबी) और बाल अधिकार एवं आप (क्राई) के सहयोग से कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उद्घाटन सत्र की शुरुआत प्रतिभागियों और सरकारी अधिकारियों के गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई। बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण केंद्र (सीसीडीआरआर) के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कुमार राका ने आपदाओं और आपात स्थितियों से उत्पन्न बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों के सामने आने वाली विविध कमजोरियों और जोखिमों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया आवश्यकताओं (स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा) को समझने की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला। एनआईडीएम दक्षिण परिसर के संयुक्त निदेशक कर्नल पी. एस. रेड्डी ने कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला और शिक्षा की निरंतरता और आपदाओं एवं आपात स्थितियों में शून्य दिवस क्षति के लिए कार्य करने हेतु समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर बल दिया। कार्यशाला में श्री मोहम्मद आसिफ, सहायक प्रबंधक, बीआरबी, श्री रंजन कुमार, सुश्री नाजिया शेख और सुश्री झांसी भी उपस्थित थीं।

6.90 आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला, 06 सितंबर 2024, आंध्र प्रदेश

बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) केंद्र, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने बाल रक्षा भारत (बीआरबी) और बाल अधिकार एवं आप (क्राई) के सहयोग से एनआईडीएम दक्षिण परिसर में 'आपदाओं और

आपात स्थितियों में शिक्षा' पर कार्यशाला का आयोजन किया। एनआईडीएम दक्षिण परिसर के संयुक्त निदेशक कर्नल पी. एस. रेड्डी ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने शिक्षा की निरंतरता के लिए आपात स्थितियों में बच्चों के सामने आने वाली विविध कमजोरियों और जोखिमों का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया और अन्य देशों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं पर भी चर्चा की। डॉ. बालू आई, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम, श्री रंजन कुमार, सुश्री नाजिया शेख और सुश्री झांसी ने भी कार्यशाला में अपने अनुभव साझा किए।

6.91 बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर कार्यशाला, 13 सितंबर 2024, आंध्र प्रदेश

सीसीडीआरआर, एनआईडीएम द्वारा एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा में 'बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा और आपात स्थितियों में कमियों और चुनौतियों का पता लगाना और बच्चों के लिए राज्य में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत करना था। कार्यशाला की शुरुआत सुश्री नाजिया शेख के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद डॉ. बालू आई, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने उद्घाटन भाषण दिया। मोहम्मद आसिफ, सहायक प्रबंधक, बाल रक्षा भारत (बीआरबी) ने अपने विशेष संबोधन से प्रतिभागियों को जागरूक किया और अपनी विशेषज्ञता साझा की। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने सीसीडीआरआर के महत्व पर प्रकाश डाला और आपात स्थितियों में बाल-केंद्रित आपदा जोखिम को कम करने के लिए बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों पर जोर दिया। सीसीडीआरआर और बीआरबी दोनों टीमों ने प्रश्नावली सत्र में भी भाग लिया। श्री रंजन कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

6.92 बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर कार्यशाला, 27 सितंबर 2024, केरल

बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भूमि आपदा प्रबंधन संस्थान (आईएलडीएम), केरल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती गीता (भा.प्र.से), आईएलडीएम की कार्यकारी निदेशक द्वारा किया गया, जिसमें श्री ई. मुहम्मद सफीर, प्रशासन निदेशक; श्री वी. जयमोहन, शिक्षा निदेशक; डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी; श्री मिंटू देबनाथ, प्रमुख, मानवीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई उत्तर; श्री अविनाश सिंह, कार्यक्रम कार्यान्वयन निदेशक, बाल रक्षा भारत); श्री नवीन शुक्ला, सहायक प्रबंधक (बाल रक्षा भारत); डॉ. अमलराज, सहायक प्रोफेसर और डॉ. बालू आई. ने योगदान दिया। इस कार्यक्रम में केरल के 14 जिलों के महिला एवं बाल विकास विभाग

के लगभग 60 बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में बाल-केंद्रित बढ़ाने के लिए नवीन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ज्ञानवर्धक बातचीत और समृद्ध चर्चाओं को बढ़ावा दिया गया, जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए एक मजबूत उत्साह को दर्शाती है।

6.93 बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यशाला, 11 अक्टूबर 2024, आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के दक्षिणी परिसर में 'बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर)' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अधिकारियों और नीति निर्माताओं को बच्चों की भलाई के लिए नीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बाल-केंद्रित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए जागरूक करना था। सुश्री नाजिया शेख ने विशिष्ट प्रतिभागियों का स्वागत किया। डॉ. आई. बालू, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने अपने उद्घाटन भाषण के साथ संदर्भ प्रस्तुत किया और आपदा परिदृश्यों में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में बाल-केंद्रित दृष्टिकोणों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विशिष्ट जोखिमों को बच्चों की आयु और लिंग-संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास और कार्यक्रम निर्माण पर केंद्रित किया जाना चाहिए। बच्चों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समाधान उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों के लिए प्रासंगिक हों। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि कार्यशाला के परिणाम बच्चों के अधिकारों की रक्षा और आपदाओं में समुत्थानशीलता के लिए जागरूकता, सहयोग और सक्रिय रणनीतियों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। कार्यशाला का समापन श्री रंजन कुमार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। पुलिस, पंचायत राज, महिला एवं बाल कल्याण, राजस्व और रेड क्रॉस के लगभग 55 अधिकारी प्रमुख प्रतिभागियों में शामिल थे।

6.94 'आपदा एवं आपात स्थितियों में शिक्षा' पर कार्यशाला, 29 नवंबर 2024, जम्मू एवं कश्मीर

सीसीडीआरआर, एनआईडीएम केंद्र ने कश्मीर विश्वविद्यालय में 'आपदा एवं आपात स्थितियों में शिक्षा' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा एवं आपात स्थितियों में शिक्षा की निरंतरता के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू एवं कश्मीर के संकाय सदस्य श्री जावेद राशिद के स्वागत भाषण से हुई। डॉ. बालू आई, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने आपात स्थितियों के दौरान बच्चों के कल्याण के लिए सुदृढ़ और सुरक्षित वातावरण के महत्व पर बल दिया। इसके अलावा, बाल रक्षा भारत (बीआरबी) के क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद शरीफ भट ने विशेष

भाषण दिया और देश में बच्चों के कल्याण के लिए अपने संगठन की पहलों को साझा किया। मुख्य भाषण कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा दिया गया, जिन्होंने आपदा में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बहुमूल्य जानकारी और मार्गदर्शन दिया और शिक्षा की निरंतरता में विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम समन्वयक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा विभाग के लगभग 52 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.95 बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (सीसीडीआरआर) पर कार्यशाला, 06 दिसंबर 2024, आंध्र प्रदेश

सीसीडीआरआर एनआईडीएम ने एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की शुरुआत सुश्री नाजिया शेख के स्वागत भाषण से हुई। डॉ. बालू आई, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने उद्घाटन भाषण दिया। कर्नल पीएस रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य भाषण डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर-एनआईडीएम ने दिया, जिन्होंने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की असुरक्षा पर प्रकाश डाला। कार्यशाला का उद्देश्य विशेषज्ञों और हितधारकों को बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा और साझा करने के लिए एक साथ लाना था। इस कार्यशाला में स्कूली शिक्षा, पुलिस, महिला एवं बाल कल्याण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) विभागों से लगभग 73 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.96 आपदा और आपात स्थितियों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल पर कार्यशाला, 13 दिसंबर 2024, आंध्र प्रदेश

सीसीडीआरआर एनआईडीएम ने विजयवाड़ा स्थित एनआईडीएम दक्षिण परिसर में 'आपदा और आपात स्थितियों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य आपदा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करने के लिए हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना था। डॉ. बालू आई, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने कार्यशाला का संदर्भ प्रस्तुत किया। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर-एनआईडीएम ने आपदाओं से प्रभावित बच्चों को समय पर मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे दीर्घकालिक मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारियों की संभावना कम हो सकती है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग से लगभग 47 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

6.97 बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यशाला, 20 दिसंबर 2024, कर्नाटक

एटीआई, मैसूर में बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई) में आपदा प्रबंधन केंद्र (सीडीएम) के प्रमुख डॉ. अशोक एस. संगनाल ने इस कार्यशाला में प्रतिभागियों का स्वागत किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्यों में कमियों, चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की

पहचान करना था। इसने विभिन्न हितधारकों को बच्चों के कल्याण के लिए सिफारिशें विकसित करने में मदद की। श्री रंजन कुमार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने उद्घाटन भाषण दिया और बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य भाषण एनआईडीएम के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. कुमार राका ने दिया, जिन्होंने बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। उद्घाटन सत्र का समापन एटीआई के सीडीएम प्रमुख डॉ. अशोक एस. संगनाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। स्कूल शिक्षा विभाग से लगभग 56 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

6.98 'आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार' पर कार्यशाला 10 जनवरी 2025, आंध्र प्रदेश

एनआईडीएम दक्षिण परिसर, विजयवाड़ा में 'आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार' पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन कर्नल पीएस रेड्डी, संयुक्त निदेशक, एनआईडीएम ने किया। कार्यशाला की शुरुआत सुश्री नाजिया शेख, संयुक्त सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद डॉ. बालू आई, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने कार्यशाला के उद्देश्यों का अवलोकन प्रस्तुत किया। डॉ. कुमार राका, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम ने मुख्य भाषण दिया और बच्चों के अधिकारों की रक्षा और आपदा स्थितियों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। सत्र का समापन श्री रंजन कुमार, सलाहकार, सीसीडीआरआर, एनआईडीएम द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस कार्यशाला में आंध्र प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल कल्याण, स्कूली शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, समाज कल्याण विभाग से लगभग 48 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

6.99 संकाय विकास कार्यक्रम, 17 जनवरी 2025, आंध्र प्रदेश

एनआईडीएम दक्षिणी परिसर ने एनआईडीएम, रोहिणी और एनआईडीएम, विजयवाड़ा के कर्मचारियों के लिए एक संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। एनआईडीएम के संयुक्त निदेशक कर्नल पी.एस. रेड्डी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने आपदा प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो आपदाओं के बाद जानमाल के नुकसान में कमी के रूप में प्रकट होती है। विशेषज्ञ डॉ. सत्यगोपाल कोरलापति, सेवानिवृत्त भा.प्र.से, विशेषज्ञ सदस्य- राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी क्षेत्रपीठ, चेन्नई ने जलवायु रोधी कृषि (सीआरए) तकनीक पर एक गहन प्रस्तुति दी, जिसमें जल संरक्षण करने वाली जड़ क्षेत्र सिंचाई तकनीक को न्यूनतम जल उपयोग के साथ वृक्षों और फसलों की वृद्धि बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान के रूप में प्रस्तुत

किया गया। कार्यक्रम में डॉ. बंदी वेंकटेश्वरलू ने भी भाग लिया। सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, विजयवाड़ा, डॉ. सविता पी. गोपोड़ अनुसंधान अधिकारी (आयु), आरएआरआई, विजयवाड़ा, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, प्रोफेसर, एनआईडीएम, श्री रणदीप कुमार राणा, वरिष्ठ सलाहकार, एनआईडीएम और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया।

अध्याय 7

वित्त और लेखा

लेखाकार की संकलन रिपोर्ट

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सदस्यों हेतु

आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (जिसे आगे ''एनआईडीएम'' कहा जाएगा) के संलग्न वित्तीय विवरण संकलित किए हैं। इन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान और पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) का बैलेंस शीट, उस समय समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय और प्राप्तियां एवं भुगतान खाते का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और खातों पर टिप्पणियाँ (जिन्हें आगे ''वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा) शामिल हैं।

हमने यह संकलन कार्य संबंधित सेवाओं पर मानक 4410 (संशोधित), संकलन कार्यों के अनुसार किया।

हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण में आपकी सहायता हेतु लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है। हमने संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पूर्णत: पालन किया है।

ये वित्तीय विवरण और उन्हें संकलित करने में प्रयुक्त जानकारी की सटीकता और पूर्णता आपकी जिम्मेदारी है।

चूँकि संकलन कार्य कोई आश्वासन कार्य नहीं है, इसलिए हमें इन वित्तीय विवरणों को संकलित करने के लिए आपके द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता का सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, हम इस विषय में कोई लेखा परीक्षा मत या समीक्षा निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं कि ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं।

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किए जाते हैं।

कृते अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं.: 017121C

सीए. मनीष गुप्ता
पार्टनर

स्थान:- दिल्ली
दिनांक:- 28.10.2025

सदस्यता संख्या:-517299
यूडीआईएन:-25517299BMOPXB3962

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां

अनुसूची 1

क) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं, {गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त व्यय और अनुदान सहायता को छोड़कर, जिनका लेखा नकद आधार पर किया जाता है} और ये आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार होते हैं।

ख) अचल संपत्तियों का रजिस्टर भौतिक सत्यापन के लिए रखा जा रहा है और परियोजना के अंतर्गत अर्जित सभी अचल परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की लेखा पुस्तकों में उस संबंधित वित्तीय वर्ष में पूंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें ऐसी परिसंपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। स्थिर परिसंपत्तियों को अधिग्रहण लागत सहित, यदि कोई स्थापना लागत हो तो उसे जोड़कर, और वर्ष के अंत तक वसूल की गई मूल्यह्रास राशि घटाकर प्रदर्शित किया गया है। अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।

ग) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में गृह मंत्रालय के पत्रांक एफ. सं. 45-16/2012-एनडीएम-II, दिनांक 24 मार्च 2017 के अनुसार, एनआईडीएम ने 2 कर्मचारियों (जिनमें से एक दिसंबर 2019 में सेवानिवृत हो गए) को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों की पेंशन एनपीएस खाते में जमा कर दी है, जिन्होंने पेंशन योजना में राशि जमा करने का विकल्प नहीं चुना है। 27 कर्मचारियों में से केवल 24 कर्मचारियों की राशि एनपीएस खाते में जमा की गई है। तथापि, जिन कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, अदालत में विचाराधीन और निधन के मामले, उनकी राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता का अंशदान) अभी भी एनआईडीएम के बैंक खाते में जमा हैं ।

घ) जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ड.) संस्थान का 1 चालू खाता और 2 बचत खाते तथा 1 पीएफएमएस से संबद्ध बचत खाता है।

च) जिन लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है वे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप हैं।

छ) **आकस्मिक देयताएं**

संस्थान के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में मान्यता नहीं दी गई - शून्य ।

ज) प्रबंधन की राय में सामान्य व्यावसायिक क्रम में चालू आस्तियां, ऋणों और अग्रिम वसूली का मूल्य बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा। सभी ज्ञात देनदारियों के लिए लेखा पुस्तकों में अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

(झ) गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के पत्रांक 45-5/2008-एनडीएम-IV/II दिनांक 23 मार्च, 2010 के निर्देशानुसार, एक अलग पब्लिक लेजर अकाउंट (पीएलए) रखा गया है और जमा राशि से अर्जित ब्याज सहित परियोजनाओं से सृजित निवल बचत भारत की संचित निधि में जमा कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पीएलए का वित्तीय विवरण अलग से तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) का एक भाग है।

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**
सीए मनीष गुप्ता	**(एस.एस. बिष्ट)**	**कर्नल मनोरम यादव, एसएम**	**मधुप व्यास, भा.प्र.से.**
(पार्टनर)	**लेखा अधिकारी**	**संयुक्त निदेशक**	**(कार्यकारी निदेशक)**

एम.नं. 517299
यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

31 मार्च, 2025 तक का बैलेंस शीट

राशि (रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
संचित निधि/पूंजी कोष और देयताएं			
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	96,90,22,420.76	1,04,44,82,485.76
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	3	1,97,62,701.15	2,07,69,711.15
कुल		**98,87,85,121.91**	**1,06,52,52,196.91**
आस्तियां			
स्थायी आस्तियां	4	90,95,84,068.14	96,96,72,082.14
निवेश	5	7,34,16,871.00	9,15,57,681.00
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	6	57,84,182.77	40,22,433.77
कुल		**98,87,85,121.91**	**1,06,52,52,196.91**

1

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां
हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-
सीए मनीष गुप्ता	(एस.एस. बिष्ट)	कर्नल मनोरम यादव, एसएम	मधुप व्यास, भा.प्र.से.
(पार्टनर)	लेखा अधिकारी	संयुक्त निदेशक	(कार्यकारी निदेशक)

सदस्यता संख्या: 517299

यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आय और व्यय का लेखा

राशि (रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025	31.03.2024
आय/अनुदान (गृह मंत्रालय से)			
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	7	24,99,94,432.00	19,64,81,368.00
कुल क		**24,99,94,432.00**	**19,64,81,368.00**
व्यय (गृह मंत्रालय अनुदान)			
स्थापना व्यय	8	7,27,62,299.00	7,21,60,127.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	9	10,91,62,917.00	9,24,16,552.95
प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं पर व्यय	10	4,57,65,523.00	5,25,74,058.94
अवमूल्यन	4	9,77,63,758.00	10,46,24,150.00
कुल ख		**32,54,54,497.00**	**32,17,74,888.89**
पूर्व अवधि और असाधारण मदों से पहले गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने के कारण शेष राशि		**(7,54,60,065.00)**	**(12,52,93,520.89)**
घाटा: पूर्व अवधि व्यय		-	-
गृह मंत्रालय कोष से घाटा होने पर शेष		**(7,54,60,065.00)**	**(12,52,93,520.89)**

1

महत्वपूर्ण लेखांकन और नीतियां एवं लेखा टिप्पणियां
हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**
सीए मनीष गुप्ता	**(एस.एस. बिष्ट)**	**कर्नल मनोरम यादव, एसएम**	**मधुप व्यास, भा.प्र.से.**
(पार्टनर)	**लेखा अधिकारी**	**संयुक्त निदेशक**	**(कार्यकारी निदेशक)**

सदस्यता संख्या: 517299
यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

अनुसूची 4: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्थिर आस्तियों और अवमूल्यन का विवरण

राशि (रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	दर	01.04.2024 को डब्ल्यूडीवी	परिवर्धन		कटौती	कुल	वर्ष के लिए अवमूल्यन	31.03.2025 को डब्ल्यूडीवी
				180 दिन से अधिक	180 दिन से कम				
	राजस्व शीर्ष से		रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
1	पुस्तकें	40%	13,82,978.00	2,092.00	1,29,361.00	–	15,14,431.00	5,79,900.00	9,34,531.00
2	कार्यालय उपकरण	15%	80,66,343.00	64,478.00	2,00,37,967.00	–	2,81,68,788.00	27,22,471.00	2,54,46,317.00
	फर्नीचर एवं उपस्कर								
3	फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	69,91,352.00	–	–	–	69,91,352.00	6,99,135.00	62,92,217.00
	संयंत्र और मशीनरी								
4	संयत्र एवं मशीनरी	15%	1,70,262.00	–	–	–	1,70,262.00	25,539.00	1,44,723.00
5	वाहन (मारूति सियाज)	15%	3,05,634.00	–	–	–	3,05,634.00	45,845.00	2,59,789.00
	कंप्यूटर								
6	कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	40%	23,64,847.00	24,950.00	–	–	23,89,797.00	9,55,919.00	14,33,878.00
7	सॉफ्टवेयर	40%	3.00	–	–	–	3.00	1.00	2.00
	पूंजी शीर्ष भूमि से								
1	भूमि (रोहिणी परिसर)	0%	5,54,17,002.00	--	--	--	5,54,17,002.00	--	5,54,17,002.00
2	भूमि (दक्षिणी परिसर)		1.00				1.00		1.00
	भवन (दक्षिणी परिसर)								
3	(क) भवन	10%	37,16,83,632.30	1,74,16,896.00	–	–	38,91,00,528.30	3,89,10,053.00	35,01,90,475.30
	(ख) संयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,49,30,283.00	–	–	–	1,49,30,283.00	22,39,542.00	1,26,90,741.00
	भवन (दक्षिणी परिसर)								
	(क) भवन	10%	46,45,82,792.84	–	–	–	46,45,82,792.84	4,64,58,279.00	41,81,24,513.84
	(ख) फर्नीचर एवं उपस्कर	10%	2,87,89,386.00				2,87,89,386.00	28,78,939.00	2,59,10,447.00
	(ग) संयंत्र एवं मशीनरी	15%	1,49,87,566.00				1,49,87,566.00	22,48,135.00	1,27,39,431.00
	कुल		**96,96,72,082.14**	**1,75,08,416.00**	**2,01,67,328.00**	–	**1,00,73,47,826.14**	**9,77,63,758.00**	**90,95,84,068.14**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024	
प्राप्तियां				
अथशेष				
केनरा बैंक खाता संख्या 120026243646	13,47,928.51		--	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	8,54,341.33		(5,49,437.00)	
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	30,560.02	**22,32,829.86**	3,85,25,756.02	**3,79,76,319.02**
प्राप्त अनुदान				
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	24,99,95,197.00		20,50,00,000.00	
पीएफएमएस के माध्यम से अव्ययित शेष राशि प्रेषित	(765.00)		(85,18,632.00)	
दक्षिणी परिसर के निर्माण के लिए प्राप्त अनुदान	--	**24,99,94,432.00**	--	**19,64,81,368.00**
अन्य प्राप्तियां				
बैंक से प्राप्त ब्याज	26,091.00		14,960.00	
प्राप्त ब्याज (पूंजी शीर्ष)	44,27,725.00		4,20,011.00	
एफडी ऑटो स्वीप	--		17,87,16,200.59	
एफडी (पूँजी शीर्ष) मैच्युर्ड	8,69,99,298.00		21,87,77,653.00	
प्राप्त सुरक्षा जमा	--		10,000.00	
विविध प्राप्तियां	--	**9,14,53,114.00**	1,55,621.00	**39,80,94,445.59**
एनपीएस के लिए कर्मचारी अंशदान	2,63,428.00	**2,63,428.00**	4,12,510.00	**4,12,510.00**
कुल		**34,39,43,803.86**		**63,29,64,642.61**
भुगतान				
पूंजीगत व्यय/अन्य देयताएं				
कार्यालय उपकरण की खरीद	2,01,02,445.00		49,650.00	
निर्माणाधीन भवन (दक्षिणी परिसर)	1,74,16,896.00		1,61,40,847.00	
पुस्तकों की खरीद	1,31,453.00		3,89,657.00	
लेनदारों को भुगतान	(7,06,852.00)		(7,44,878.00)	
सावधि जमा (एफडीआर) खोले गए/बुक किए गए	6,81,53,000.00		21,89,49,000.00	
सावधि जमा ऑटो स्वीप	--		11,59,10,000.00	
सुरक्षा जमा राशि की वापसी	60,000.00		--	
कम्प्यूटर की खरीद	24,950.00	**10,51,81,892.00**	71,103.00	**35,07,65,379.00**
राजस्व व्यय				
प्रत्यक्ष व्यय				
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं	4,52,08,651.00		4,65,12,398.00	
आकस्मिक व्यय हेतु अग्रिम	(27,662.00)	**4,51,80,989.00**	1,43,944.00	**4,66,56,342.00**
स्थापना व्यय				
वेतन और भत्ते	5,83,17,402.00		5,50,92,610.00	
बोनस	89,804.00		--	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024	
एलटीए/एलटीसी अग्रिमों का शुद्ध योग	12,41,536.00		3,19,596.00	
मेडिकल	36,33,284.00		8,43,567.00	
पेंशन/एनपीएस/अन्य निधियों में अंशदान और				
ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकद का भुगतान	91,70,657.00		1,35,40,154.00	
पेंशन फंड से निकासी	22,54,039.00			
सीजीएचएस	48,550.00		(59,250.00)	
एचआरए ईडी-एनआईडीएम	(57,990.00)		--	
जीपीएफ	(1,40,000.00)		--	
ईजीआईएस	(540.00)		--	
जीआईएस बचत एवं बीमा	(9,800.00)	**7,45,46,942.00**	--	**6,97,36,677.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मरम्मत एवं रखरखाव	1,86,54,181.00		1,70,05,927.00	
विद्युत व्यय	36,44,120.00		51,57,869.00	
डाक व्यय	2,64,177.00		62,777.00	
हॉस्टल संचालन/रखरखाव व्यय	72,91,939.00		53,01,214.00	
मुद्रण और स्टेशनरी	13,36,058.00		10,10,340.00	
किराया, दर और कर	16,32,659.00		16,32,659.00	
विविध व्यय	49,73,849.00		13,21,938.00	
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	1,98,314.00		2,17,563.00	
टेलीफोन व्यय	57,45,854.00		33,90,833.00	
जल शुल्क	3,05,183.00		1,31,355.00	
घरेलू यात्रा	26,07,281.00		21,65,325.00	
एनपीडीआरआर व्यय	--		74,26,120.00	
व्यवसायिक शुल्क	92,32,084.00		75,94,395.00	
पुस्तकालय/प्रकाशन	32,81,655.00		35,46,047.00	
बैंक शुल्क	3,755.00		7,448.75	
विदेश यात्रा	53,520.00		4,68,027.00	
दक्षिणी परिसर व्यय	1,86,26,159.00		1,53,96,703.00	
लाइसेंस शुल्क	(54,146.00)		--	
वाहन रखरखाव व्यय	2,28,508.00		2,81,490.00	
परामर्शदाता की नियुक्ति	3,08,94,621.00		2,62,55,258.00	
देय खर्चे	--	**10,89,19,771.00**	5,65,12,998.00	**15,48,86,286.75**
सरकार को भुगतान				
देय एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान	(3,68,800.00)		21,66,295.00	
सरकार को अतिरिक्त आय का भुगतान	65,73,959.00		66,37,277.00	
जीएसटी पर टीडीएस	(4,22,806.00)	**57,82,353.00**	(1,16,444.00)	**86,87,128.00**
अंतिम शेष				
यूको बैंक खाता संख्या 182001100067819	53,928.02		30,560.02	
केनरा बैंक खाता संख्या 120026243646	41,38,370.51		7,09,395.51	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	1,39,558.33		8,54,341.33	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024	
केनरा बैंक खाता संख्या 110150354860	--	**43,31,856.86**	6,38,533.00	**22,32,829.86**
कुल		**34,39,43,803.86**		**63,29,64,642.61**

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

कृते अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**
सीए मनीष गुप्ता	**(एस.एस. बिष्ट)**	**कर्नल मनोरम यादव, एसएम**	**मधुप व्यास, भा.प्र.से.**
(पार्टनर)	**लेखा अधिकारी**	**संयुक्त निदेशक**	**(कार्यकारी निदेशक)**

सदस्यता संख्या: 517299

यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 2: आरक्षितियां और अधिशेष

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आरक्षितियां एवं अधिशेष		
अथशेष	1,04,44,82,485.76	1,16,97,76,006.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान आय पर व्यय के आधिक्य का अंतरण	(7,54,60,065.00)	(12,52,93,520.89)
कुल	**96,90,22,420.76**	**1,04,44,82,485.76**

अनुसूची 3: वर्तमान देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि		
अथशेष	72,72,641.00	72,72,641.00
जोड़ें:- नियोक्ता अंशदान	-	-
-कर्मचारी अंशदान	-	-
भविष्य निधि पर ब्याज	-	-
	72,72,641.00	**72,72,641.00**
घटा: कर्मचारी को अदायगी	22,54,039.00	--
	50,18,602.00	**72,72,641.00**
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज (बीजी)		
सरकार को देय	7,70,209.00	6,38,434.00
सरकार को देय अन्य आय*	51,99,688.15	65,73,959.15
बयाना जमा राशि	2,71,298.00	2,71,298.00
देय व्यय	55,985.00	2,01,570.00
प्राप्त सुरक्षा राशि	21,809.00	81,809.00
अर्जित ब्याज (सीपीएफ कोष)	16,92,842.00	11,19,129.00
सीजीएचएस	48,400.00	96,950.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
एनपीएस/कोष में कर्मचारी का अंशदान	19,23,394.00	16,59,966.00
एनपीएस में नियोक्ता का देय अंशदान	25,77,018.00	22,08,218.00
देय शुल्क एवं कर (जीएसटी एवं टीडीएस पर टीडीएस)	19,17,120.00	6,45,737.00
देय लाइसेंस शुल्क	58,006.00	--
देय एचआरए-ईडी एनआईडीएम	57,990.00	
देय जीआईएस एवं जीपीएफ	1,50,340.00	
कुल योग	**1,97,62,701.15**	**2,07,69,711.15**

*इस राशि में सावधि जमा में निवेशित पूंजी अनुदान पर अर्जित ब्याज भी शामिल है।

अनुसूची 5: निवेश

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सावधि जमा (पूंजी शीर्ष खाता)	6,20,15,637.00	8,08,61,935.00
ब्याज उपार्जन (ऑटो स्वीप एफएफडी-एसबीआई)	--	--
सावधि जमा (निधि)	91,92,842.00	86,19,129.00
सावधि जमा (दक्षिणी परिसर-बीजी)	22,08,392.00	20,76,617.00
कुल	**7,34,16,871.00**	**9,15,57,681.00**

अनुसूची 6: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
क. बैंक बकाया:		
यूको बैंक खाता संख्या 18200200000924	--	--
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता संख्या 40256508810	1,39,558.33	8,54,341.33
केनरा बैंक होल्डिंग खाता सं.120026243646	41,38,370.51	13,47,928.51
केनरा बैंक खाता संख्या 110150354860	--	--
यूको बैंक खाता संख्या 18200110067819	53,928.02	30,560.02

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
कुल बैंक शेष (क)	**43,31,856.86**	**22,32,829.86**
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य आस्तियां		
सुरक्षित जमा राशि	9,50,999.00	9,50,999.00
स्रोत पर वसूली योग्य काटा गया टैक्स	3,40,047.65	3,40,047.65
आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम	49,895.00	82,302.00
परिवहन अग्रिम	29,781.00	29,781.00
पीएलए (विविध प्राप्ति खाते)	81,603.26	76,858.26
एलटीसी अग्रिम	--	3,09,616.00
कुल (ख)	**14,52,325.91**	**17,89,603.91**
कुल (क+ख)	**57,84,182.77**	**40,22,433.77**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय)
31 मार्च, 2025 की तिथि के अनुसार आय-व्यय खाता संबंधी अनुसूची

अनुसूची 7: गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
केन्द्र के अधीन गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	24,99,95,197.00	20,50,00,000.00
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुदान वापस भेजा गया	(765.00)	(85,18,632.00)
कुल	**24,99,94,432.00**	**19,64,81,368.00**

अनुसूची 8: संस्थापना व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वेतन एवं भत्ते	5,83,17,402.00	5,47,19,200.00
बोनस	89,804.00	--
पेंशन/एनपीएस/अन्य निधियों में अंशदान और ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकद का भुगतान	91,70,657.00	1,62,84,206.00
यात्रा रियायत भत्ता/एलटीए/एलटीसी	15,51,152.00	3,13,154.00
मेडिकल	36,33,284.00	8,43,567.00
कुल	**7,27,62,299.00**	**7,21,60,127.00**

अनुसूची 9: अन्य प्रशासनिक व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
मरम्मत और रखरखाव	1,86,54,181.00	1,70,11,617.40
डाक	2,64,177.00	62,777.00
मुद्रण और स्टेशनरी	13,36,058.00	10,10,340.00
विद्युत एवं जल प्रभार	39,49,303.00	52,89,224.00
विविध व्यय	49,73,849.00	14,37,154.00
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं	1,98,314.00	2,17,563.00
हास्टल संचालन एवं रखरखाव	72,91,939.00	53,16,214.00
टेलीफोन व्यय	57,45,854.00	64,05,594.00

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
घरेलू यात्रा	26,07,281.00	21,65,325.00
विदेश यात्रा	53,520.00	4,68,027.00
दक्षिणी परिसर व्यय	1,86,26,159.00	1,23,81,277.80
व्यवसायिक शुल्क	92,32,084.00	75,27,407.00
किराया, दर और कर	16,32,659.00	16,32,659.00
बैंक शुल्क	3,755.00	7,448.75
अनुसंधान एवं प्रलेखन	1,89,000.00	13,81,130.00
पुस्तकालय/प्रकाशन	32,81,655.00	35,46,047.00
परामर्शदाता की नियुक्ति	3,08,94,621.00	2,62,55,258.00
वाहन रखरखाव व्यय	2,28,508.00	3,01,490.00
कुल	**10,91,62,917.00**	**9,24,16,552.95**

अनुसूची 10: प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय (गृह मंत्रालय-अनुदान)

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला व्यय	4,57,65,523.00	4,51,47,938.94
एनपीडीआरआर व्यय	--	74,26,120.00
कुल	**4,57,65,523.00**	**5,25,74,058.94**

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**
सीए मनीष गुप्ता	**(एस.एस. बिष्ट)**	**कर्नल मनोरम यादव, एसएम**	**मधुप व्यास, भा.प्र.से.**
(पार्टनर)	**लेखा अधिकारी**	**संयुक्त निदेशक**	**(कार्यकारी निदेशक)**

सदस्यता संख्या: 517299

यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2025 तक पीएलए बैलेंस शीट

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
संचित निधि और देयताएं			
पूंजी और आरक्षिती तथा अधिशेष	1	33,04,551.00	7,31,560.00
निर्धारित राशि	2	1,05,25,675.99	67,34,661.00
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	1,81,96,575.61	13,27,913.00
कुल		**3,20,26,802.60**	**87,94,134.00**
आस्तियां			
स्थायी आस्तियां		--	--
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम	4	3,20,26,802.60	87,94,134.00
कुल		**3,20,26,802.60**	**87,94,134.00**

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-
सीए मनीष गुप्ता	(एस.एस. बिष्ट)	कर्नल मनोरम यादव, एसएम	मधुप व्यास, भा.प्र.से.
(पार्टनर)	लेखा अधिकारी	संयुक्त निदेशक	(कार्यकारी निदेशक)

सदस्यता संख्या: 517299

यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आय		
ब्याज आय	--	1,42,172.00
विविध प्राप्त राशि	--	10,24,755.00
आपदा प्रबंधन योजना की सेवाएँ	1,64,97,500.00	--
कुल (क)	**1,64,97,500.00**	**11,66,927.00**
व्यय		
बैंक शुल्क	--	1,525.30
परियोजना व्यय	1,39,24,509.00	19,942.00
कुल (ख)	**1,39,24,509.00**	**21,467.30**
शेष राशि अर्थात् अधिशेष (क-ख)	**25,72,991.00**	**11,45,459.70**
घटाः पीएओ, गृह मंत्रालय को अंतरित बचत	--	11,45,459.70
अधिशेष के रूप में बैलेंस शीट में स्थानांतरित किया गया शेष	**25,72,991.00**	--

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**	**हस्ताक्षर/-**
सीए मनीष गुप्ता	**(एस.एस. बिष्ट)**	**कर्नल मनोरम यादव, एसएम**	**मधुप व्यास, भा.प्र.से.**
(पार्टनर)	**लेखा अधिकारी**	**संयुक्त निदेशक**	**(कार्यकारी निदेशक)**

सदस्यता संख्याः 517299

यूडीआईएनः 25517299BMOPXB3962

दिनांकः 28.10.2025
स्थानः नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (पीएलए)

अनुसूची 1: संचित/पूंजीनिधि

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
अथशेष	7,31,560.00	7,31,560.00
वर्ष के दौरान अधिशेष	25,72,991.00	--
अंतिम राशि	33,04,551.00	7,31,560.00
कुल	**33,04,551.00**	**7,31,560.00**

अनुसूची 2: निर्धारित निधि

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
1 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	1,82,600.00	1,59,600.00
	1,82,600.00	**1,59,600.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	--
घटा: सरकारी कोष में देय बचत	1,82,600.00	1,59,600.00
	--	--
2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्राप्त राशि (कैप-रेस परियोजना)		
अथशेष	17,58,919.97	30,70,531.97
वर्ष के दौरान प्राप्ति	--	--
	17,58,919.97	**30,70,531.97**
घटा: पीएफएमएस के माध्यम से लौटाई गई अव्ययित शेष राशि	6,87,099.97	--
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	10,71,820.00	13,11,611.00
कुल	--	**17,58,919.97**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
3 यूनिसेफ/सीआरवाई/बीआरबी (सीसीडी आरआर परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	15,61,802.00	11,47,262.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	77,33,965.00	72,85,830.00
	92,95,767.00	**84,33,092.00**
घटा: यूनिसेफ/बीआरबी को लौटाई गई अव्ययित राशि	12,95,954.00	1,91,732.00
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	74,26,733.00	66,79,558.00
कुल	**5,73,080.00**	**15,61,802.00**
4 एमओसीएंडएफ (सीपीसीबी-सीएमपी परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	1,13,854.00	1,13,854.00
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	--
	1,13,854.00	**1,13,854.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय राशि	--	--
कुल	**1,13,854.00**	**1,13,854.00**
5 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जीआईजेड परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	9,45,443.00	--
वर्ष के दौरान प्राप्ति	51,57,521.99	27,68,728.00
	61,02,964.99	**27,68,728.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	64,31,423.00	18,23,285.00
कुल	**(3,28,458.01)**	**9,45,443.00**
6 एमओसीएंडएफ (एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	1,00,994.00	40,605.00
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	7,88,000.00
	1,00,994.00	**8,28,605.00**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	7,27,611.00
कुल	**1,00,994.00**	**1,00,994.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
7 एमओईएफएंडसीसी (एनईएफसी–डीएमपी परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	5,27,213.00	7,743.00
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	18,40,000.00
	5,27,213.00	**18,47,743.00**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की राशि	4,03,751.00	13,20,530.00
कुल	**1,23,462.00**	**5,27,213.00**
8 एमओएचएंडएफडब्ल्यू (एमएचएफडब्ल्यू परियोजना) से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	1,40,000.00
	--	**1,40,000.00**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	140,000.00
कुल	--	--
9 आयुष मंत्रालय (एनडीएमपी–आयुष) से प्राप्त राशि		
अथशेष	5,94,835.00	7,29,807.00
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	5,19,400.00
	5,94,835.00	**12,49,207.00**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	5,94,835.00	6,54,372.00
कुल	--	**5,94,835.00**
10. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से प्राप्त राशि		
अथशेष	11,31,600.00	11,31,600.00
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	
	11,31,600.00	**11,31,600.00**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	10,56,663.00	--
कुल	**74,937.00**	**11,31,600.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
11 टाटा सन्स (प्रशिक्षण कार्यक्रम) से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	2,45,000.00
	--	**2,45,000.00**
घटारू सरकारी कोष में देय बचत	--	2,45,000.00
कुल	--	--
12. आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	--	--
	--	--
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	3,07,500.00	
कुल	**3,07,500.00**	
13. कृषि मंत्रालय से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	1,00,00,000.00	--
	1,00,00,000.00	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	--	--
कुल	**1,00,00,000.00**	
14. एनपीसीसीएचएच परियोजना खाते से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	20,89,250.00	--
	20,89,250.00	
घटा: एनपीसीसीएचएच को लौटाई गई अव्ययित राशि	1,03,250.00	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय राशि	19,86,000.00	
कुल	--	
15. टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप ट्रेनिंग प्रोग्राम से प्राप्त राशि		
अथशेष	--	--

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	2,95,411.00	
	2,95,411.00	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग/व्यय की गई राशि	1,20,104.00	
कुल	**1,75,307.00**	
कुल योग	**1,05,25,675.99**	**67,34,660.97**

अनुसूची 3: चालू देयताएं और प्रावधान

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
सरकारी खाते में देय परियोजना बचत	11,58,582.35	11,45,459.82
देय शुल्क एवं कर	27,34,445.00	(20,473.00)
टीडीएस	89,805.00	1,22,840.00
जीएसटी पर टीडीएस	2,44,007.00	--
देय व्यय	19,64,979.00	--
ब्याज	3,228.00	3,228.00
संस्थागत शुल्क	14,24,526.00	--
अप्राप्त बकाया आय (सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजना)	1,04,95,400.00	--
एनआईडीएम (मुख्य खाता)	81,603.26	76,858.26
कुल	**1,81,96,575.61**	**13,27,913.08**

अनुसूची 4: चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
(क) बैंक शेष:		
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (पीएफएमएस)	--	18,95,450.00
एसबीआई बैंक खाता संख्या 5043	1,78,53,506.68	60,48,229.79
एसबीआई बैंक खाता संख्या 4332	2,46,367.92	7,37,294.00
ऋण एवं अग्रिम		
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजना अग्रिम	10,000.00	--
प्राप्य टीडीएस	10,87,260.00	1,13,160.00
अप्राप्त बकाया आय के विरुद्ध प्राप्य अग्रिम	1,28,29,668.00	--
कुल	**3,20,26,802.60**	**87,94,133.79**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

पब्लिक लेजर अकांउट (पीएलए)
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
(गृह मंत्रालय)
31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

राशि (रुपये में)

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
प्राप्तियां				
अथशेष				
1. महाराष्ट्र बैंक (कैप-रेस परियोजना)	18,95,450.00		32,07,061.00	
2. एसबीआई बैंक खाता संख्या 40257045043	60,48,229.79		36,65,128.09	
3. एसबीआई बैंक खाता संख्या 42141554332	7,37,294.00	**86,80,973.79**	--	**68,72,189.09**
वर्ष के दौरान प्राप्य योग्य/प्राप्तियां				
1. ऑनलाइन पाठ्यक्रम से प्राप्त राशि	1,82,600.00		1,59,600.00	
2. एफसीआई परियोजना से प्राप्त राशि	3,77,200.00		12,22,128.00	
3. बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना	--		72,85,830.00	
4. सीसीडीआरआर-बीआरबी परियोजना से प्राप्ति	52,76,000.00		---	
5. सीसी डीआरआर परियोजना (क्राई) से प्राप्त राशि	24,57,965.00		--	
6. जीआईजेड परियोजना से प्राप्त राशि	51,57,521.99		27,68,728.00	
7. एपी मेडिसीनल बोर्ड से प्राप्त राशि	--		3,12,500.00	
8. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजना से प्राप्त राशि	1,61,20,300.00		--	
9. एनसीपीसी-डीएमपी-परियोजना के लिए पेट्रोकेमिकल मंत्रालय से प्राप्त राशि	--		7,88,000.00	
10. एनपीसीसीएचएच खाते से प्राप्त राशि	20,89,250.00		--	
11. प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्राप्त राशि	--		2,45,000.00	
12. कृषि मंत्रालय से प्राप्त राशि	1,00,00,000.00		--	
13. आयुष मंत्रालय से प्राप्त राशि	--		5,19,400.00	
14. टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्राप्त	2,95,411.00		--	
15. एनईएफसी-डीएमपी परियोजना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त	--		18,40,000.00	
16. विविध प्राप्त राशि (प्रशिक्षण कार्यक्रम)	23,671.00			
17. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग परियोजना से अप्राप्त बकाया आय	1,04,95,400.00	**5,24,75,318.99**		**1,51,41,186.00**

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
अन्य प्राप्तियां				
1. अन्य विविध प्राप्त राशि	6,62,948.00		13,084.00	
2. प्राप्य टीडीएस	1,13,160.00		1,22,840.00	
3. प्राप्त ब्याज (अन्य)	4,08,485.00	**11,84,593.00**	1,47,028.00	**2,82,952.00**
कुल		**6,23,40,885.78**		**2,22,96,327.09**
भुगतान				
भुगतान/देय परियोजना व्यय				
1 बाल केंद्रित डीआरआर-यूनीसेफ परियोजना	--		68,71,290.00	
2. सीसीडीआरआर-बीआरबी परियोजना	62,92,010.00		--	
3. सीसीडीआरआर परियोजना (सीआरवाई)	24,30,677.00		--	
4. आयुष परियोजना	5,94,835.00		3,64,783.00	
5. एपी मेडिसीनल बोर्ड	--		3,12,500.00	
6. जीआईजेड परियोजना	64,31,423.00		16,27,933.00	
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना	--		1,10,000.00	
8. कैप-रेस परियोजना व्यय का किया गया भुगतान एवं सरकार को देय राशि	17,58,919.97		13,11,611.00	
9. एफसीआई परियोजना व्यय	10,56,663.00		--	
10. आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम (17-28 मार्च 25)	3,07,500.00		--	
11. टाटा सस्टेनेबिलिटी ग्रुप प्रशिक्षण कार्यक्रम	1,20,104.00		--	
12. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय-एनईएफसी-डीएमपी परियोजना	--		12,28,400.00	
13. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजना हेतु अग्रिम राशि	10,000.00		--	
14. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परियोजना व्यय	1,39,24,509.00		--	
15. एनपीसीसीएचएच परियोजना	20,89,250.00		--	
16. एनसीपीसी-डीएमपी परियोजना (पेट्रोरसायन मंत्रालय)	--		5,87,611.00	
17. एनईएफसी -डीएमपी परियोजना व्यय	4,03,751.00	**3,54,19,641.97**	--	**1,24,14,128.00**
अन्य व्यय/भुगतान				
1 सरकारी खाते में देय	11,45,460.00		9,17,524.00	
2. जीएसटी देनदारी	(27,54,918.00)		1,92,384.00	
3. विविध व्यय	1,36,530.03		19,942.00	
4 बैंक शुल्क	1,846.18		1,525.30	
5 टीडीएस	33,035.00		--	
6 देय व्यय	(19,64,979.00)		69,850.00	

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

विवरण	31.03.2025 तक		31.03.2024 तक	
7. देय संस्थागत शुल्क	(14,48,526.00)			
8. अग्रिम प्राप्य	1,28,29,668.00			
9. प्राप्य टीडीएस	10,87,260.00			
10. देय जीएसटी पर टीडीएस	(2,44,007.00)	**88,21,369.21**	--	12,01,225.30
अंतिम शेष				
1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (कैप-रेस परियोजना)	--		18,95,450.00	
2. एसबीआई बैंक खाता संख्या 40257045043	1,78,53,506.68		60,48,229.79	
3. एसबीआई बैंक खाता संख्या 42141554332	2,46,367.92	**1,80,99,874.60**	7,37,294.00	86,80,973.79
कुल		**6,23,40,885.78**		**2,22,96,327.09**

हमारे लेखाकार की सम तिथि की संकलन रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

अमांग एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि. सं. 017121C

कृते राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-	हस्ताक्षर/-
सीए मनीष गुप्ता	(एस.एस. बिष्ट)	कर्नल मनोरम यादव, एसएम	मधुप व्यास, भा.प्र.से.
(पार्टनर)	लेखा अधिकारी	संयुक्त निदेशक	(कार्यकारी निदेशक)

सदस्यता संख्या: 517299

यूडीआईएन: 25517299BMOPXB3962

दिनांक: 28.10.2025
स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा ।

अध्याय 8

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुबंध की सूची		
8.1	अनुबंध-I	संस्थान के सदस्य
8.2	अनुबंध-II	संस्थान के शासी निकाय के सदस्य
8.3	अनुबंध-III	आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम
8.4	अनुबंध-IV	आमने-सामने कार्यशाला

अनुलग्नक-I: संस्थान के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	केन्द्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3	सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
4	गृह सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
6	सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7	सचिव, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
8	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
9	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
10	सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
11	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
12	सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, महासागर भवन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
13	सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
14	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
15	सचिव/अपर सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
16	महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पूर्वी ब्लॉक-7, स्तर-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	सदस्य
17	उप प्रमुख, एकीकृत रक्षा स्टाफ, सिद्धांत संगठन एवं प्रशिक्षण (डीओटी), आईडीएस, मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ, 23 साउथ हटमेंट्स, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली-110001	सदस्य
18	सचिव (आपदा प्रबंधन), गुजरात सरकार, राजस्व विभाग, ब्लॉक-11, तीसरी मंजिल, नया सचिवालय, गांधीनगर-382010	सदस्य
19	सचिव (आपदा प्रबंधन), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, पटना-800015	सदस्य
20	कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006	सदस्य
21	निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248179	सदस्य
22	निदेशक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, शिवरामपल्ली, हैदराबाद-500052	सदस्य
23	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली	सदस्य
24	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, जोका, डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता-700104	सदस्य
25	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की, उत्तराखंड	सदस्य
26	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
27	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
28	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
29	महानिदेशक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, राजेंद्रनगर, हैदराबाद-500030	सदस्य
30	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वी. रामलिंगास्वामी भवन, अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029	सदस्य
31	अध्यक्ष, उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग, 159 श्रद्धा कुंज, वसंत विहार, चकराता रोड, देहरादून	सदस्य
32	राष्ट्रीय भूकंपीय सलाहकार, गृह मंत्रालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
33	सीएमडी, सामान्य बीमा निगम, सुरक्षा, जे टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020	सदस्य
34	सीएमडी, इलाहाबाद बैंक, मुख्यालय, 2, एन.एस. रोड, कोलकाता-700001	सदस्य
35	अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
36	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), कोर 4-ए, चौथी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003	सदस्य
37	निदेशक, अखिल भारतीय आपदा न्यूनीकरण संस्थान, 411, साकार फाइव, नटराज सिनेमा के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-9	सदस्य
38	महासचिव, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, 1 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली	सदस्य
39	निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद-500007	सदस्य
40	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
41	प्रोफेसर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली-110042	सदस्य
42	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली-110042	सदस्य सचिव

अनुलग्नक-II: संस्थान के शासी निकाय के सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2	केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष
3	अपर सचिव एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
4	सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
5	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली	सदस्य
6	सचिव, अंतरिक्ष विभाग, तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली	सदस्य
7	सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली	सदस्य
8	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली	सदस्य
9	प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम	सदस्य
10	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, 315, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	सदस्य
11	निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, डायमंड हार्बर रोड, पीओ जोका, कोलकाता-700104	सदस्य

क्र.सं.	सदस्य	पद
12	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, उत्तराखंड–267667	सदस्य
13	निदेशक, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद–500007	सदस्य
14	कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर–16सी, द्वारका, दिल्ली–110078	सदस्य
15	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, प्लॉट नंबर 15, पॉकेट 3, ब्लॉक बी, सेक्टर 29, रोहिणी, दिल्ली–110042	सदस्य सचिव

अनुलग्नक- III: एनआईडीएम दिल्ली और दक्षिणी परिसर द्वारा 01.04.2024 से 31.03.2025 तक आयोजित किए गए आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
			आन्ध्र प्रदेश				
1	आपदा जोखिम शमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः शैक्षणिक संस्थानों का सुदृढ़ निर्माण	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली	दिल्ली	02.04.2024	05.04.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
2	सुदृढ़ संस्थान निर्माण की दिशा में आपदा प्रतिक्रिया एवं तैयारी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	03.04.2024	05.04.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी एवं डॉ. सुषमा गुलेरिया	37
3	व्यावसायिक सुरक्षा एवं आपदा जोखिम प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम	एसआरएम आईएसटी, चेन्नई	तमिलनाडु	03.04.2024	05.04.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	60
4	बाल-केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	15.04.2024	19.04.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	42
5	सुंदरबन में आपदा शमन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमः अवसंरचना, आजीविका एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मुद्दों का समाधान	बर्धमान विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	22.04.2024	26.04.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	68
6	आपदा एवं आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	22.04.2024	26.04.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	45
7	आपात स्थितियों में मनोसामाजिक सहयोग पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमसीएचआर डीआई, तेलंगाना	तेलंगाना	22.04.2024	24.04.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	31
8	आपदा जोखिम प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (डीआरएम एवं सीसीए) में युवाओं एवं किशोरों की सहभागिता पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	सेंट्रल बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार/ बीएसडीएमए	बिहार	29.04.2024	02.05.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	58

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
9	बाढ़ आकलन एवं हाइड्रोलिक संरचनाएँ-जोखिम न्यूनीकरण हेतु नवीन दृष्टिकोण (एफईएचएस-2024) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमएनआईआईटी, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	29.04.2024	03.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	37
						कुल	**438**
			मई, 2024				
10	विभागीय आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एम.जी.एस.आई.पी.ए., चंडीगढ़	पंजाब	06.05.2024	08.05.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	49
11	आपदाओं एवं आपात स्थितियों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एस.ए.टी., मणिपुर	मणिपुर	06.05.2024	09.05.2024	डॉ. बालू आई	65
12	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	ओ.एस.डी.एम.ए., ओडिशा	दिल्ली	07.05.2024	09.05.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	25
13	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी एवं मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	असम	15.05.2024	17.05.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	101
14	राज्य समर्थित स्टार्ट-अप के लिए तेल रिसाव और डीआरआर पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री आपदा प्रबंधन और तटीय डीआरआर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.आई.डी.एम., दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	15.05.2024	17.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	47
15	आपदा जोखिम प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम	दिल्ली विश्वविद्यालय (कलिंदी कॉलेज)	दिल्ली	20.05.2024	24.05.2024	डॉ. आमिर अली खान	40
16	मध्याह्न भोजन रसोइया-सह-सहायकों के साथ राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला	आंध्र प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित	आंध्र प्रदेश	21.05.2024	24.05.2024	डॉ. कुमार राका	64
17	आपदा जोखिम प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में युवाओं एवं किशोरों की भागीदारी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एन.आई.डी.एम., दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	27.05.2024	30.05.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	48

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
18	लैंगिकता एवं आपदा प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	तमिलनाडु	27.05.2024	31.05.2024	डॉ अजिंदर वालिया	67
19	सुदृढ़ विकास हेतु प्रकृति-आधारित समाधान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप)	पुदुचेरी	27.05.2024	31.05.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
20	आई.एस.एस. प्रोबेशनरों के लिए ''आपदा प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एन.एस.एस. टी.ए., ग्रेटर नोएडा	दिल्ली	27.05.2024	31.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	29
21	जन स्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम) पी.डी.पी. टियर-III प्रशिक्षण (बैच-2)	एन.सी.डी.सी. (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) एवं सी.डी.सी. (सी.डी.सी.-इंडिया), पुणे	महाराष्ट्र	29.05.2024	31.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	38
						कुल	**633**
				जून, 2024			
22	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	03.06.2024	06.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	41
23	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के शिक्षाविदों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	03.06.2024	07.06.2024	डॉ. प्रीति सोनी एवं सुश्री नाजिया खान	60
24	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एचपीएसडी एमए, शिमला	हिमाचल प्रदेश	10.06.2024	13.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	42
25	शहरी बाढ़ प्रबंधन पर क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	11.06.2024	13.06.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	39

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
26	समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एमजीएसआई पीए, चंडीगढ़	पंजाब	11.06.2024	14.06.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	60
27	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली मूल एवं मध्यम स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जीआईपार्ड, गोवा	गोवा	19.06.2024	21.06.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	56
28	आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	24.06.2024	27.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	70
29	महाराष्ट्र में पीएचईडीएम-पीडीपी टियर-III प्रशिक्षण का तीसरा बैच	एनसीडीसी, सीडीसी इंडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	26.06.2024	28.06.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	34
						कुल	**402**
			जुलाई, 2024				
30	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान	झारखंड	01.07.2024	04.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
31	आपदा जोखिम की समझ और आपदा रोधी विकास अभ्यासों के मुख्यधारा में एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीआरएसयूए ओए, नैनीताल	उत्तराखंड	01.07.2024	05.07.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	50
32	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	03.07.2024	05.07.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	57
33	आपदा रोधी विकास पर प्रशिक्षण सह संकाय विकास कार्यक्रम पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में (लद्दाख)	लद्दाख विश्वविद्यालय	लद्दाख	05.07.2024	07.07.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	114
34	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	08.07.2024	11.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	42
35	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	इसरो, दिल्ली	दिल्ली	08.07.2024	12.07.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	56

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
36	सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शहरों को आपदा रोधी बनाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	08.07.2024	12.07.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
37	स्कूल सुरक्षा एवं स्कूल आपदा प्रबंधन योजना निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एमजीएसआई पीए, चंडीगढ़	पंजाब	09.07.2024	11.07.2024	डॉ. आमिर अली खान	56
38	सीबीआरएनई संकट प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	जीआईडीएम, गांधीनगर	गुजरात	18.07.2024	20.07.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	61
39	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण)	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	22.07.2024	25.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	42
40	महाराष्ट्र में पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण का चौथा चरण	एनसीडीसी, सीडीसी इंडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	24.07.2024	26.07.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	35
41	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एएसडीएमए, असम	असम	30.07.2024	01.08.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	25
						कुल	**658**
			अगस्त, 2024				
42	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	लद्दाख विश्वविद्यालय	लद्दाख	05.08.2024	08.08.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	50
43	जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु व्यापक आपदा प्रबंधन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	05.08.2024	09.08.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	40
44	नगरीय स्थानीय निकायों में आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकाय	उत्तर प्रदेश	06.08.2024	08.08.2024	डॉ. आमिर अली खान	51
45	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	19.08.2024	22.08.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	45
46	संकाय विकास कार्यक्रम ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ	दिल्ली	19.08.2024	23.08.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	60

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
	वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे और चुनौतियाँ''	विश्वविद्यालय, नई दिल्ली					
47	विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के एकीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	तमिलनाडु अर्बन स्टडीज संस्थान (टीएनआईयूएस)	तमिलनाडु	21.08.2024	23.08.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	49
48	आपदा प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर	एनईआईएस प्रशिक्षण	बीयूडी, नोएडा उत्तर प्रदेश	26.08.2024	30.08.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	52
49	आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआरआई डीएम, बेंगलुरु	कर्नाटक	27.08.2024	30.08.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	18
50	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	27.08.2024	30.08.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	49
51	जल संबंधी आपदा जोखिम न्यूनीकरण: अवधारणाएँ, तकनीकें और अनुकूलन रणनीतियाँ पर राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की	उत्तराखंड	27.08.2024	31.08.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	50
						कुल	**464**
			सितंबर, 2024				
52	आपदा प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम	आईएलडीएम, केरल	केरल	02.09.2024	06.09.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	59
53	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	02.09.2024	05.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	30
54	जिला आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	04.09.2024	06.09.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	59
55	लैंगिक समानता और आपदा प्रबंधन पर संकाय विकास कार्यक्रम	तमिलनाडु लॉ अंबेडकर विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	09.09.2024	13.09.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	60
56	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	09.09.2024	12.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	34

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
57	चरम मौसमीय घटनाओं के संदर्भ में शहरी अवसंरचना की समुत्थानशीलता पर राष्ट्रीय संकाय विकास कार्यक्रम	दिल्ली विश्वविद्यालय (पर्यावरण अध्ययन विभाग)	दिल्ली	09.09.2024	13.09.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	30
58	झारखंड में पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण का प्रथम चरण	एनसीडीसी, सीडीसी इंडिया, झारखंड	झारखंड	11.09.2024	13.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	27
59	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनडीआरएफ, दिल्ली	दिल्ली	18.09.2024	20.09.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	24
60	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	आईएलडीएम, केरल	केरल	23.09.2024	26.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
61	विकास कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया एवं बीएसडीएमए	बिहार	24.09.2024	26.09.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	60
62	स्थिरता और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन डिजाइन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईआईटी, गुवाहाटी	असम	23.09.2024	27.09.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	73
63	बड़े धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन के उपकरण के रूप में आईआरएस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीयूएस आईआरडी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	23.09.2024	27.09.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	46
						कुल	**562**
			अक्टूबर 2024				
64	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर आपदा तैयारी और शमन	सिविल इंजीनियरिंग विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	07.10.2024	09.10.2024	डॉ. आमिर अली खान	84

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
65	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	07.10.2024	10.10.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	55
66	संकाय विकास कार्यक्रम आपदा जोखिम प्रबंधन पर	पंजाबी विश्वविद्यालय	पंजाब	07.10.2024	11.10.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	60
67	ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (महिला बैच) का एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	पंजाब राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) एवं एम.जी.एस. आई.पी.ए., चंडीगढ़	पंजाब	08.10.2024	10.10.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	47
						कुल	**246**
			नवंबर 2024				
68	बदलते जलवायु में सुदृढ़ ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	04.11.2024	08.11.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया	37
69	आपदा प्रबंधन में मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीएमआई, बिहार	बिहार	11.11.2024	13.11.2024	डॉ अजिंदर वालिया	35
70	आपदाओं में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	11.11.2024	14.11.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	58
71	भूकंप आपदा जोखिम शमन एवं प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	11.11.2024	15.11.2024	डॉ. आमिर अली खान	20
72	आपदाओं एवं आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचसीएम-रिपा, जोधपुर	राजस्थान	18.11.2024	22.11.2024	डॉ. कुमार राका	51
73	शहरी बाढ़ एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	असम एसडीएमए एवं आईआईटी, गुवाहाटी	असम	19.11.2024	21.11.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	62
74	पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण का तीसरा बैच	एनसीडीसी, सीडीसी इंडिया, गुजरात	गुजरात	20.11.2024	22.11.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	25

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
75	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	25.11.2024	28.11.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	52
76	महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुदृढ़ता हेतु डीआरआर मुख्यधारा में एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एटीआई, मैसूरु	कर्नाटक	26.11.2024	28.11.2024	डॉ. आमिर अली खान	47
						कुल	**387**
दिसंबर 2024							
77	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	02.12.2024	05.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	73
78	आपदा के बाद आवश्यकताओं का आकलन (पीडीएनए) पर प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	04.12.2024	06.12.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	40
79	आपदाओं में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक देखभाल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	09.12.2024	12.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	47
80	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एटीआई, मैसूरु	कर्नाटक	16.12.2024	19.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	56
81	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	16.12.2024	18.12.2024	डॉ. कुमार राका	50
82	पुस्तकालयों और अभिलेखागार के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं के विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	17.12.2024	19.12.2024	डॉ. अजिंदर वालिया	35
83	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	19.12.2024	21.12.2024	डॉ. कुमार राका	60
						कुल	**361**
जनवरी 2025							
84	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	06.01.2025	09.01.2025	डॉ. कुमार राका एवं	48

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
	पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण					श्री रंजन कुमार	
85	घटना प्रतिक्रिया प्रणाली: बुनियादी एवं मध्यवर्ती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एचसीएम-रिपा, राजस्थान	राजस्थान	07.01.2025	10.01.2025	श्री शेखर चतुर्वेदी	60
86	जन स्वास्थ्य आपातकाल और आपदा प्रबंधन-पेशेवर विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी)	एनसीडीसी, सीडीसी, झारखंड	झारखंड	16.01.2025	18.01.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	28
87	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	टाटा समूह एवं ओएसडीएमए	ओडिशा	20.01.2025	22.01.2025	श्री एस.एन. सिद्ध	26
88	बदलते जलवायु में सुदृढ़ ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईआरडी, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	22.01.2025	24.01.2025	डॉ. सुषमा गुलेरिया एवं श्री मनजीत सिंह	22
89	आपात संचालन केंद्र प्रबंधन एवं घटना प्रतिक्रिया प्रणाली पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एसडीएमए, महाराष्ट्र (यशादा, पुणे)	महाराष्ट्र	20.01.2025	23.01.2025	श्री शेखर चतुर्वेदी	45
90	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	27.01.2025	29.01.2025	डॉ. कुमार राका	50
91	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	30.01.2025	01.02.2025	डॉ. कुमार राका	46
						कुल	**325**
			फरवरी 2025				
92	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	03.02.2025	07.02.2025	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	46
93	शहर की सुदृढ़ता हेतु अग्नि सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनएफएससी, नागपुर	दिल्ली	06.02.2025	08.02.2025	डॉ. गरिमा अग्रवाल	35
94	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	10.02.2025	12.02.2025	डॉ. कुमार राका	63
95	आपदाओं में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर	जीआईपीए आरडी/गोवा	गोवा	10.02.2025	13.02.2025	डॉ. कुमार राका एवं	74

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	विश्वविद्यालय				श्री रंजन कुमार	
96	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	13.02.2025	15.02.2025	डॉ. कुमार राका	45
97	युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में संलग्न करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	17.02.2025	21.02.2025	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	38
98	भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीडीएमए, कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	27.02.2025	01.03.2025	श्री शेखर चतुर्वेदी	73
99	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	27.02.2025	01.03.2025	डॉ. कुमार राका	37
						कुल	**411**
			मार्च 2025				
100	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	03.03.2025	07.03.2025	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	56
101	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	10.03.2025	12.03.2025	डॉ. कुमार राका	32
102	युवाओं और किशोरों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन में संलग्न करने पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	पांडिचेरी	27.01.2025	30.01.2025	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	60
103	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	17.03.2025	19.03.2025	डॉ. कुमार राका	42
104	बाल केंद्रित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	एमजीएसआईपीए	पंजाब	17.03.2025	19.03.2025	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	69
105	व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	17.03.2025	28.03.2025	श्री शेखर चतुर्वेदी	20
106	शहरी बाढ़ से निपटने पर प्रशिक्षण: भौगोलिक उपकरण और सामुदायिक	जादवपुर विश्वविद्यालय,	पश्चिम बंगाल	17.03.2025	21.03.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	60

क्र. सं.	पाठयक्रम का नाम	सहयोगी संस्था	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	संयोजक (गण)	प्रतिभागियों की संख्या
	आधारित दृष्टिकोण के बीच समन्वय	कोलकाता					
107	आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एपीएसडीएमए, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	24.03.2025	26.03.2025	डॉ. कुमार राका	36
						कुल	**375**
						कुल योग	**5262**

अनुलग्नक–IV: एनआईडीएम द्वारा अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025 के दौरान आयोजित किए गए आमने–सामने कार्यशाला

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
1	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सेमिनार	आईआईटी, बीएचयू	उत्तर प्रदेश	21.04.2024	22.04.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	158
2	पृथ्वी दिवस का अवलोकन: पृथ्वी बनाम प्लास्टिक	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	22.04.2024	22.04.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	41
3	जलवायु प्रभाव-जलवायु और स्थिरता पर एक दिवसीय सम्मेलन	दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	30.04.2024	30.04.2024	डॉ. प्रीति सोनी	174
						कुल	**373**
			मई 2024				
4	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जीआईएस के अनुप्रयोग पर जागरूकता कार्यक्रम	दयाल सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	दिल्ली	03.05.2024	03.05.2024	डॉ. सुषमा गुलेरिया एवं डॉ. प्रीति सोनी	129
5	युवाओं और किशोरों को डीआरएम एवं सीसीए में संलग्न करने पर कार्यशाला	सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार/ बीएसडीएमए	बिहार	03.05.2024	03.05.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	67
6	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला	एसएटी, मणिपुर	मणिपुर	10.05.2024	10.05.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	65
7	शहरी सुदृढ़ता और परियोजना निगरानी समिति बैठक: "सतत् शहरी विकास हेतु शहरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सक्षम करना"	इंडिया हैबिटैट सेंटर (आईएचसी), दिल्ली	दिल्ली	21.05.2024	21.05.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	34
8	आपदा जोखिम प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पर कार्यशाला	एनईएसएसी, उमियम, मेघालय	मेघालय	27.05.2024	28.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	91
9	जनस्वास्थ्य आपातकाल एवं आपदा प्रबंधन-पेशेवर विकास कार्यक्रम (पीएचईडीएम-पीडीपी) टियर-III, बैच-2 प्रशिक्षण	एनसीडीसी (एमओएचएफ डब्ल्यू) एवं सीडीसी	महाराष्ट्र	28.05.2024	28.05.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	6

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
		(सीडीसी इंडिया), पुणे					
						कुल	**392**
			जून 2024				
10	युवा नेताओं का सम्मेलन	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	04.06.2024	05.06.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	89
11	औद्योगिक रासायनिक सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरम पर सम्मेलन	फिक्की, नई दिल्ली	दिल्ली	06.06.2024	07.06.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	59
12	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	07.06.2024	07.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	41
13	1897 के महान शिलांग भूकंप की वर्षगांठ पर कार्यशाला	नेहू/एमएसडीएमए/एटीआई, मेघालय	मेघालय	12.06.2024	12.06.2024	डॉ. आमिर अली खान	241
14	शहरी बाढ़ प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	14.06.2024	14.06.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	39
15	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	एचपीएसडीएमए	हिमाचल प्रदेश	14.06.2024	14.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	42
16	आपदा शमन और प्रबंधन पर कार्यशाला	एनआईटीएस, नोएडा	उत्तर प्रदेश	21.06.2024	22.06.2024	डॉ. आमिर अली खान	15
17	आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण पर कार्यशाला	ईएसआईसी, फरीदाबाद	हरियाणा	22.06.2024	22.06.2024	प्रो. अनिल कुमार गुप्ता	121
18	पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण पर महाराष्ट्र में कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसीइंडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	25.06.2024	25.06.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	5
19	आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	28.06.2024	28.06.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	70

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
						कुल	**722**
			जुलाई 2024				
20	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन	झारखंड	05.07.2024	05.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
21	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	12.07.2024	12.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	42
22	पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण, महाराष्ट्र में कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसीइंडिया, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	23.07.2024	23.07.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	9
23	जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन और सुदृढ़ता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: एक समग्र दृष्टिकोण	जेएसएस अकादमी, कर्नाटक	कर्नाटक	25.07.2024	26.07.2024	डॉ. प्रीति सोनी	149
24	आपदाओं और आपात स्थितियों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	26.07.2024	26.07.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	49
						कुल	**309**
			अगस्त 2024				
25	आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	09.08.2024	09.08.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	190
26	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों पर कार्यशाला	लद्दाख विश्वविद्यालय	लद्दाख	09.08.2024	09.08.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	50
27	आगामी मेले में भीड़ नियंत्रण एवं भगदड़ पर कार्यशाला	डीडीएमए, राजकोट	गुजरात	20.08.2024	21.08.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	100
28	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	23.08.2024	23.08.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	45
						कुल	**385**

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
सितंबर 2024							
29	जलवायु कार्रवाई के लिए युवा पर राष्ट्रीय अध्ययन सम्मेलन	मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ताम्बराम, चेन्नई	तमिलनाडु	02.09.2024	04.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	150
30	सामुदायिक पीएचईडीएम टियर-I के संचालन हेतु सीईएमटी और सीईआरटी पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला	केन्द्रीय विश्वविद्यालय गया एवं बीएसडीएमए	बिहार	05.09.2024	05.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	52
31	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	06.09.2024	06.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	30
32	पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण, झारखंड में कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसी-इंडिया, झारखंड	झारखंड	10.09.2024	10.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	7
33	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	13.09.2024	13.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	34
34	''स्वास्थ्य, खतरे, जोखिम प्रबंधन और संचार'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला	एटीआई ओएनजीसी, गोवा	गोवा	18.09.2024	20.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश एवं सुश्री नाजिया खान	25
35	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	आईएलडीएम, केरल	केरल	27.09.2024	27.09.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	60
36	डीआरआर और सीसीए उपायों को विकास योजना में मुख्यधारा में शामिल करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसी-इंडिया, अलवर	राजस्थान	27.09.2024	27.09.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	150
						कुल	**508**

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
अक्टूबर 2024							
37	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	11.10.2024	11.10.2024	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	55
38	अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	23.10.2024	23.10.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	1000
						कुल	**1055**
नवंबर 2024							
39	पीएचईडीएम टियर-III प्रशिक्षण पर कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसी-इंडिया, गुजरात	गुजरात	19.11.2024	19.11.2024	प्रो. सूर्य प्रकाश	8
40	प्रैक्टिशनर्स का समुदाय-सतत शहरी विकास के लिए डीआरआर और सीसीए उपायों हेतु शहरों को सक्षम बनाने पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर	दिल्ली	28.11.2024	28.11.2024	डॉ. गरिमा अग्रवाल	63
41	आपदाओं और आपात स्थितियों में शिक्षा पर कार्यशाला	डीआईईटी, बारामुल्ला, कश्मीर/कश्मीर विश्वविद्यालय	जम्मू और कश्मीर	29.11.2024	29.11.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	52
						कुल	**123**
दिसंबर 2024							
42	भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष: सबक, चुनौतियां एवं संभावनाएं	आईएचसी, नई दिल्ली	दिल्ली	03.12.2024	03.12.2024	डॉ. प्रीति सोनी	171
43	आपदाओं और आपात स्थितियों में बाल संरक्षण और बाल अधिकार पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	06.12.2024	06.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	73
44	आपदाओं में बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	13.12.2024	13.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	47
45	राष्ट्रीय वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन (एनएटीसी)	एनआईडीएम, रोहिणी परिसर, नई दिल्ली	दिल्ली	13.12.2024	13.12.2024	श्री शेखर चतुर्वेदी	80

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
46	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	एटीआई, मैसूरू	कर्नाटक	20.12.2024	20.12.2024	डॉ. कुमार राका एवं डॉ. बालू आई	56
						कुल	**427**
जनवरी 2025							
47	पीएचईडीएम-टियर-I पायलट का संचालन	गोंदपुर, अलवर	राजस्थान	07.01.2025	08.01.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	35
48	सीसीडीआरआर पर कार्यशाला	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	10.01.2025	10.01.2025	डॉ. कुमार राका एवं श्री रंजन कुमार	46
49	पीएचईडीएम-पीडीपी टियर-III पर कार्यशाला	एनसीडीसी, सीडीसी, झारखंड	झारखंड	15.01.2025	15.01.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	7
50	संकाय विकास कार्यक्रम	एनआईडीएम, दक्षिण परिसर	आंध्र प्रदेश	17.01.2025	17.01.2025	श्री रोहित कुमार एवं श्री अमरजीत कुमार	28
						कुल	**116**
फरवरी 2025							
51	राष्ट्रीय क्रिटिकल केयर नर्सिंग सम्मेलन (एनसीएनसीओ)	पीजीआईएमई आर, चंडीगढ़	चंडीगढ़	14.02.2025	15.02.2025	श्री एस एन सिद्ध	150
52	सुदृढ़ समाज और स्थिरता के लिए प्राकृतिक खतरों और आपदा प्रबंधन में उन्नत भू-कम्प्यूटेशनल तकनीकों के उपयोग पर कार्यशाला	एमिटी विश्वविद्यालय, यूपी	उत्तर प्रदेश	27.02.2025	28.02.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	94
						कुल	**244**
मार्च 2025							
53	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम भूकंप जोखिम न्यूनीकरण	एनडीएमए, दिल्ली	दिल्ली	04.03.2025	04.03.2025	डॉ. आमिर अली खान	222
54	आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका पर क्षेत्रीय कार्यशाला,	आईएलडीएम, केरल	केरल	10.03.2025	11.03.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	59

क्र. सं.	कार्यक्रम/सेमिनार का शीर्षक	आयोजन स्थल	राज्य	कार्यक्रम प्रारंभ तिथि	कार्यक्रम समापन तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	प्रतिभागियों की संख्या
55	समुदाय आधारित जनस्वास्थ्य आपदा प्रबंधन (सीबी-पीएचईडीएम)	निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा, जयपुर	राजस्थान	18.03.2025	18.03.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	85
56	विजन जीरो सम्मेलन 2: सुदृढ़ शहरीकरण और सुरक्षित गतिशीलता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	एमएएनआईटी, भोपाल	मध्य प्रदेश	26.03.2025	28.03.2025	प्रो. सूर्य प्रकाश	150
57	हिमालयी क्षेत्र एवं उससे परे आपदा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर सम्मेलन	16वां वित्त आयोग और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख	लद्दाख	27.03.2025	28.03.2025	डॉ. प्रीति सोनी	81
						कुल	**597**
						कुल योग	**5251**

रोहिणी परिसर, दिल्ली

दक्षिण परिसर, आन्ध्र प्रदेश

nidm

समुत्थानशील भारत, आपदा मुक्त भारत

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

प्लॉट नं. 15, पॉकेट 3, ब्लॉक–बी, सेक्टर–29, रोहिणी, दिल्ली–110042

ईमेलः ed.nidm@nic.in | वेबसाईटः https://nidm.gov.in